प्रभात

इस अंक में...

1. बंगाल में एमसीसी के हमले 6
2. शिक्षा गारन्टी या बेगारन्टी शिक्षा? 17
3. बस्तर का मुक्ति संग्राम 19
4. फिलिप्पींस की लड़ाई की खबरें 24
5. गोण्डी रिपोर्टें 26
6. सुखमन की पुलिस द्वारा हत्या 32
7. दण्डकारण्य के संघर्ष-पथ परे 64

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (पीपुल्सवार) दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष-13 अंक-1 नवंबर 1999 - जनवरी 2000 मूल्य-10 रुपए

भारत की क्रान्ति के नेता कॉमरेड श्याम, महेश और मुरली को हमारी लाल-लाल श्रद्धांजली!

सामंतवाद, साम्राज्यवाद और नौकरशाही दलाल पूंजी को दफनाने जनयुद्ध को तेज करके हमारे नेताओं की हत्याओं का बदला लेंगे!

मुक्त इलाकों के लक्ष्य से छापामार इलाकों को मजबूत बनाएंगे!!!

1 दिसम्बर, 1999. समाप्ति की ओर जा रही दूसरी सहस्राब्दी और 20वीं सदी के अन्तिम महीने का पहला दिन. यह दिन भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में, विशेषकर आन्ध्रप्रदेश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में विशेष रूप से अंकित हो गया. क्योंकि इस दिन इतिहास यह देखकर पल भर के लिए हक्का-बक्का रह गया है कि पुरोगामी स्वभाव की उसकी गति को कर्कशता से रोकने के लिए प्रतिक्रियावादी और चरित्रहीन कितनी क्रूरतम आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय दे सकते हैं, कितनी कायरता बरत सकते हैं और कितने झूठों के पीर साबित हो सकते हैं. अपनी गति को सुगम बनाने के लिए कटिबद्ध होकर असामान्य कुरबानियों, आत्म-बलिदानों और लक्ष्य के प्रति सच्चे मन से मौत को चुनौती देते हुए जंग में धराशायी होने वाले अपने प्यारे सपूतों को गर्व से देखकर, इतिहास ने यह दिन इस भरोसे से आगे कदम बढ़ाया कि इन वीरों की राह में हजारों हजार वारिस चल पड़ेंगे.

इसी 1 दिसम्बर, 1999 को दोपहर करीब 1.30 बजे, आन्ध्र के नक्सल विरोधी ग्रे-हाउण्ड्स बल (जो स्पेशल इंटलिजेन्स ब्यूरो भी कहा जाता है) के खून के प्यासे गुण्डों ने एक गद्दार की शह पर, बंगलूर शहर में बनाशंकरी सरक्की गेट बस स्टॉप के निकट एक मकान पर धावा बोलकर, भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के तीन प्रमुख नेता कॉमरेड श्याम (नल्ला आदिरेड्डी), कॉमरेड महेश (येर्रमरेड्डी संतोषरेड्डी) और कॉमरेड मुरली (शीलम नरेश) को गिरफ्तार किया. आन्ध्र की पुलिस ने उसी दिन हवाई मार्ग से उन्हें हैदराबाद ले जाकर, रात भर उनसे पार्टी की गोपनीय जानकारी उगलवाने के बेकार इरादे से बेहद बर्बरतापूर्ण यातनाएं दीं. अगले दिन की सुबह इन पुलिस कुत्तों ने फिर उन्हें हवाई मार्ग से करीमनगर जिले के कोय्यूरु जंगली इलाके में ले जाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी.

आन्ध्र के पुलिस प्रमुख एच.जे.दोरा जिसने इस 'मुठभेड़' की देखरेख करने करीमनगर के लिए उड़ान भरा और इस पूरी कार्रवाई का सीधा नेतृत्व किया, ने बेशर्मी से घोषणा की कि ये कॉमरेड, एक दस्ता सदस्य अरुण के साथ, एक मुठभेड़ में मारे गए जो कोय्यूरु के जंगल में छापामारों के एक कैम्प पर पुलिस के हमले के दौरान हुई थी. उसका भाड़े का दिमाग इससे विश्वसनीय कहानी भी नहीं गढ़ सका. अधिकांश प्रतिक्रियावादी अखबारों ने खुद ही इस कथित मुठभेड़ में चार नक्सलवादियों के मारे जाने और एक भी पुलिस वाले को चोट नहीं आने पर आश्चर्य प्रकट किया. और तो और, सभी तीन नेता पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए जबकि बाकी छापामार सही सलामत भाग निकले, इस पर अखबारों ने भी यकीन नहीं किया. कथित तौर पर जिस जगह पर पांच घण्टों तक यह मुठभेड़ हुई वह मुख्य सड़क स बहुत करीब है, लेकिन आसपास के गांवों में किसी भी व्यक्ति ने गोलियों की आवाज नहीं सुनी.इसके बावजूद दोरा और बाकी सरकारी प्रवक्ता इसी कहानी को लगातार दोहराते रहे और इस हत्याकाण्ड की जांच-पड़ताल करने के लिए उच्च स्तर की न्यायिक जांच कमेटी बिठाने की कई संगठनों और जाने-माने शख्सों द्वारा की गई मांग ठुकरा दी गई. बदतर तो यह है कि पाखण्डी दोरा ने इस पूरी कार्रवाई का सीधा नेतृत्व करने के बाद, संवेदनशीलता जाहिर करने की कोशिश करते हुए, यहां तक कि कॉमरेड श्याम की यह कहकर प्रशंसा की कि वे क्रान्तिकारी आन्दोलन के ज्यादा समर्पित और प्रतिबद्ध नेता थे. जहां आन्ध्र के मुख्यमन्त्री और विश्व बैंक की कठपुतली चन्द्रबाबू नाइडू ने परदे के पीछे से इसका समन्वय किया, वहीं केन्द्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भारतीय क्रान्ति के इन नेताओं की हत्या करने के लिए रची गई साजिश में सक्रिय भागीदारी की.

इन समर्पित वीरों की शहादत, जिनकी जीवनियां भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के इतिहास और पिछले दो दशकों के आन्दोलन को प्रतिबिम्बित

करती हैं, देश में चल रहे जनयुद्ध के लिए एक जबर्दस्त झटका है. *स्पेशल जोनल कमेटी* आन्ध्र में क्रान्तिकारी आन्दोलन के पथ-प्रदर्शक इन बहादुर कॉमरोडों को लाल श्रद्धांजली पेश करती है जिन्होंने अपनी बेजोड़ कुरबानियों से भारतीय क्रान्ति की राह को उज्जवल बनाते हुए, लाल झण्डे के साये में मुस्कराते हुए अपनी जानें दीं. आइए, हम इन शहीदों की याद में पूरी नम्रता से अपने सिर झुकाएंगे. हम अपने आपको फिर से उस लक्ष्य के प्रति समर्पित करेंगे जिसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया. हम शपथ लेंगे कि इन कॉमरेडों के लहू से सिंचित लाल झण्डे को हमेशा ऊपर उठाकर रखेंगे और जब तक आखरी जीत हासिल नहीं होगी तब तक उस रास्ते पर अटल संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे जिसे इन कॉमरेडों ने अपनी शानदार कुरबानियों से जाज्वलित किया.

हत्यारा चन्द्रबाबू - एक तानाशाह जिसने बाकी तमाम तानाशाहों को पीछे छोड़ दिया

शासक वर्ग अपनी प्रतिनिधि पार्टियों - विशेषकर तेलुगुदेशम, कांग्रेस और भाजपा - के जरिए भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) जिसने पिछले दो दशकों के दौरान आन्ध्र, उत्तर तेलंगाना और दण्डकारण्य में ताकतवर क्रान्तिकारी आन्दोलन का निर्माण किया, का उन्मूलन करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. केन्द्र में सत्ता हथियाने के बाद भाजपा क्रान्तिकारी आन्दोलन और उसके नेतृत्व का उन्मूलन करने के इरादे से तमाम किस्म की घिनौनी योजनाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा आक्रामक ढंग से आगे आ रही है. लेकिन क्रान्तिकारी आन्दोलन को उपलब्ध जबर्दस्त जनाधार के चलते शासक वर्गों और उसके पुलिस-नौकरशाही अमले की तमाम कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गईं. चूंकि पार्टी और क्रान्तिकारी आन्दोलन के उन्मूलन के बजाए, दरअसल वे अपने पर लादे गए दमन के हरेक अभियान को मात देते हुए ताकतवर बनते ही जा रहे हैं, इसलिए शासक वर्गों और उनके नमक हलाल पुलिस अधिकारियों ने अपने दांवपेंच में बदलाव लाया और पिछले दो साल से धोखेबाजी *कॅवर्ट आपरेशन* (छिपी लड़ाई) से आन्दोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह की छिपी लड़ाई के तहत ही उन्होंने करीमनगर जिले के रामगिरिकिला में कॉ. रमेश की हत्या की और नलगोण्डा में चार कॉमरेडों की हत्या की. इन हत्याओं के पहले करीमनगर जिले में कॉ. भूपति और दो अन्य कॉमरेडों को इसी तरह मारा गया था. इस जघन्य प्रति-क्रान्तिकारी लड़ाई के तहत, केन्द्र और आन्ध्र की सरकारों ने, खासतौर पर मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू, गृहमन्त्री देवेन्दर गौड़, डीजीपी एच.जे. दोरा, प्रदेश के मुख्य सचिव वी. आनंद राव, केन्द्रीय गृहमन्त्री आडवाणी और केन्द्रीय गृह सचिव कमल पाण्डे ने और खून के प्यासे एस.आइ.बी. और ग्रेहाउण्ड्स ने इस हत्याकाण्ड को बेशर्मी से और बेहद क्रूरता से अंजाम दिया. उन्होंने गोविन्द रेड्डी को खरीदा, मकान पर धावा बोलकर हमारे कॉमरेडों को पकड़ लिया, उनकी हत्या करके लाशें कोय्यूरु के जंगली इलाके में फेंक दीं और हमेशा की तरह एक मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी.

यहां तक कि उन लातिनी अमरीकी देशों के कुख्यात तानाशाहों ने भी जहां पर फिलहाल क्रान्तिकारी आन्दोलन चल रहे हैं, गिरफ्तार नेताओं को जेल में डाल दिया, बजाए उन्हें जान से मारकर मुठभेड़ की कहानी गढ़ने के, जैसा कि भारत में अक्सर होता है. लेकिन आन्ध्र के शासक वर्ग (दोनों तेलुगुदेशम और कांग्रेस सरकारें) पिछले दो दशकों से भी ज्यादा समय से गिरफ्तार क्रान्तिकारियों को गोली मारकर मुठभेड़ घोषित करने का हंतक अभियान चला रहे हैं.आन्ध्र की पुलिस पकड़े गए कॉमरेडों को अमानवीय यातनाएं देने के बाद 24 घण्टों के अन्दर ही गोली मार देने की परम्परा चला रही है. इन भयंकर कार्रवाइयों का श्रेय या, यूं कहें कि बदनामी चन्द्रबाबू और उसके गैर-कानूनी एस.आइ.बी. अधिकारियों को जाती है.

चन्द्रबाबू एक पक्का फासीवादी तानाशाह है. उसे किसी भी जनवादी मूल्य पर विश्वास नहीं है. वह एक सौदागर है जो अपने मन्त्रीमंडल को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य यन्त्र को अपनी मुट्ठी में रखकर, साम्राज्यवादियों के सामने घुटने टेककर और उसकी पूरी सेवा करते हुए करोड़ों रुपए इकठ्ठा रहा है. वह विश्व पूंजीवादी वर्ग का सबसे नमक हलाल दलाल है जिसने इस मामले में दूसरे एशियाई, अफ्रीकी और लातिनी अमरीकी देशों के शासक वर्ग नेताओं को काफी पीछे छोड़ दिया. इसलिए ही साम्राज्यवादी प्रचार यन्त्र और उसके स्थानीय पुछल्लों ने इसे प्रधानमन्त्री के बाद देश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं भावी प्रधानमन्त्री के रूप में चित्रित करते हुए महिमामंडित करना शुरू किया. पिछले दो साल से यह एक तरफ केन्द्र में भाजपा को समर्थन देते हुए, दूसरी ओर सैकड़ों क्रान्तिकारियों और सामान्य किसानों की हत्या करते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन पर बर्बर हमले कर रहा है.

चन्द्रबाबू यह सपना देख रहा है कि ऐसे हमले छेड़कर वह अपने साम्राज्यवादी प्रभुओं को खुश कर सकता है और अपने मनमाने शासन को स्थाई बना सकता है. लेकिन ताकतवर क्रान्तिकारी आन्दोलन उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगा. विश्व के इतिहास ने चन्द्रबाबू जैसे कई हत्यारों और तानाशाहों को देखा जिन्हें जबर्दस्त जन आन्दोलनों ने धूल चटा दिया था. हिटलर, मुस्सोलिनी जैसे पुराने तानाशाहों को छोड़ भी दें, तो यहां तक कि हाल के मोबुतु, मार्कोस, सुहार्तो आदि को सशक्त जन आन्दोलनों ने कड़ा सबक सिखा दिया, और उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया.

ऐसे तमाम तानाशाहों का इतिहास सम्पूर्ण पराजय का इतिहास है, भले ही उन्होंने जन आन्दोलनों पर सभी प्रकार के बर्बर हमले किए हों. लेकिन जन आन्दोलनों का इतिहास तमाम ज्वार-भाटाओं को सहते हुए लगातार विकसित होने का है और आखरी जीत हासिल करने का है. वह दिन दूर नहीं कि चन्द्रबाबू को भी उसी नियति का सामना करना पड़ेगा जिसका इतिहास में बाकी तमाम खून के प्यासे तानाशाहों ने सामना किया.

कॉमरेड श्याम, महेश और मुरली जनता के दिलों में सदा जिन्दा रहेंगे !

कॉमरेड श्याम, महेश और मुरली भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में ऐसे अनमोल नेता हैं जिन्होंने लाल झण्डे को और भी लालिमा देते हुए उसकी रक्षा करते हुए अपने बहुमूल्य प्रणों की आहुति दी. ये तीनों कामरेड भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में, विशेषकर महान नक्सलबाड़ी उत्कर्ष के बाद के पिछले तीन दशकों के इतिहास का हिस्सा बनने वाले चन्द नेताओं में शीर्षस्थ स्थान पर रहेंगे. उन्होंने न सिर्फ भारत के ठोस हालात में दीर्घकालीन जनयुद्ध के नियमों को लागू किया, बल्कि खुद दो दशकों से ज्यादा समय से हथियारबन्द संघर्ष के निर्माण में भाग लिया. हमेशा उत्पीड़ित जन-समुदायों के बीच रहकर आन्दोलन को उच्च स्तर पर विकसित किया. इन शहीदों का जीवन हर क्रान्तिकारी के लिए आदर्श है.

कॉमरेड श्याम का नाम युग-युग अमर रहेगा !

नल्ला आदिरेड्डी, जो क्रान्तिकारी कतारों के बीच कॉमरेड श्याम के नाम से जाने जाते थे, का जन्म करीमनगर जिले के हुजूराबाद कस्बे के निकट ग्राम कोत्तागट्टु में एक मंझोले किसान परिवार में हुआ था. वह करीमनगर-आदिलाबाद आन्दोलन के प्यारे सपूत थे. वह कदम ब कदम परिपक्व होते गए, इन आन्दोलनों को और भी आगे बढ़ाते हुए भारतीय क्रान्ति के शीर्षस्थ नेताओं में से एक बन गए. आखरी सांस तक सच्चे क्रान्तिकारी के रूप में रहते हुए उन्होंने हमारे दिलों में एक शाश्वत योद्धा के रूप में स्थान प्राप्त किया. उनकी जिन्दगी सभी क्रान्तिकारी गुणों का सम्मेलन है और एक नमूना है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए.

1970 के दशक की शुरूआत में करीमनगर जिले के छात्रों में नक्सलबाड़ी की राजनीति पल्लवित होने लगी. नक्सलबाड़ी की रोशनी में जब नई पीढ़ी नए विचारों से लैस हो रही थी, तब कॉ. श्याम जम्मिकुण्टा के कॉलेज के छात्र थे.

कॉ. श्याम ने नाच-गाने के प्रदर्शनों से करीमनगर जिले के उत्पीड़ित जन-समुदायों को जागृत किया. जनसेना में शामिल होने का आह्वान करते हुए उन्होंने जो गीत गाया उसने लोगों के दिलों को छू लिया. तब वह सिर्फ 20 साल के थे. सामंती उत्पीड़न के खौफ में डरते-डरते जी रहे बेगारी लोगों के दिलों को छूकर जगाने वाला गीत करीमनगर होते हुए आदिलाबाद पहुच गया. उसके बाद वह गीत करीमनगर-आदिलाबाद के आन्दोलनों को उन्नत चरण में ले जाने वाला छापामार इलाके के गान के रूप में दण्डकारण्य पहुंचा और दस्तों का निर्माण किया. उस गान ने लाल सेना को जन्म दिया और आधार इलाकों के पहले बीज बोकर भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में तब्दील हो गया. इतिहास के इस पूरे क्रम में कॉमरेड श्याम अपनी छाप छोड़ते हुए उभरे थे. जब नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम के आन्दोलनों ने पीछे कदम डाला, तब उन आन्दोलनों की राजनीति को ऊंचा उठाने वाली नई पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे कॉमरेड शयाम. आन्दोलन के पीछे कदम के बाद के शुरूआती दिनों में जनदिशा पर चलने वाले लोगों में से कॉमरेड श्याम एक थे.

1975 तक देश में राजनीतिक और आर्थिक संकट बढ़ गया था, इसके परिणामस्वरूप जन आन्दोलनों में भी बढ़ोत्तरी हुई. उसी साल उन्होंने पेशेवर क्रान्तिकारी के तौर पर काम करने का फैसला लिया, और अपनी एक-चौथाई सदी की क्रान्तिकारी जिन्दगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.जून 25 को इंदिरा ने आपात्काल की घोषणा की और देश भर में क्रान्तिकारी आन्दोलन पर और संसदीय विपक्ष पर फासीवादी हमला छेड़ दिया. इस हमले के विरोध में कॉमरेड श्याम और कुछ अन्य कॉमरेडों ने स्नातक की परीक्षाओं का बहिष्कार करके कॉलेज छोड़कर मैदान-ए-जंग में कदम रखा. तबसे शुरू हुई कॉमरेड श्याम की भूमिगत जिन्दगी.

कॉमरेड आदिरेड्डी ने अपनी नई जिन्दगी कॉ. रघु के नाम से गोल्लापल्लि गांव का पारा, गोविंदपल्लि में एक स्कूल शिक्षक बनकर शुरू की. गोविंदपल्लि, एनुगुमट्ला गांवों के अलावा, पास के मद्दुनूर के लोगों को संगठित करके उन्हें मद्दुनूर का कुख्यात और क्रूर जमींदार राजेश्वर राव के खिलाफ संघर्ष में उतारा. उस जमींदार का सफाया करने के लिए पार्टी द्वारा गठित विशेष दस्ते का कॉ. रघु एक सदस्य थे. लेकिन जमींदार भाग गया, तो उस दस्ते ने दो अन्य हमले किए थे. एक सूदखोर से सम्पत्ति छीन ली और दूसरे गांव में एक बन्दूक छीन ली. शुरूआती छापामार हमलों से कॉ. श्याम ने अपने छापामार जीवन का आरम्भ किया. उसके बाद महदेवपुर जंगलों से आदिलाबाद के तपालापुर जंगलों तक, पेद्दापल्लि के मैदानों से वड़कापुर होते हुए कोरुट्ला तक उन दिनों में पार्टी द्वारा किए गए कई हमलों में कॉ. श्याम ने बहादुरी से भाग लिया. इन हमलों के दौरान वह साथी कॉमरेडों में विश्वास जगाया करते थे.

आपात्काल हटाए जाते ही पार्टी ने फिर से जनता में व्यापक काम शुरू कर दिया. कॉ. रघु उन कॉमरेडों में से एक थे जो आपात्काल के दौरान भूमिगत होकर दुश्मन की गिरफ्त में जाने से सफलतापूर्वक बच गए थे. कई कॉमरेडों के गिरफ्तार होने से कॉ. रघु ने बाकी कॉमरेडों को इकठ्ठा किया. उन्होंने पहलकदमी के साथ जन-समुदायों में गहराई से प्रवहश करते हुए करीमनगर-आदिलाबाद जिलों में उस समय के ठोस हालात के मुताबिक सही कार्यनीति विकसित की. उन्होंने वहां के आन्दोलन का नेतृत्व किया. वह एक जिला स्तर की कमेटी के सचिव चुने गए थे जो पहली बार करीमनगर-आदिलाबाद-निजामाबाद आन्दोलन का समन्वय करने के लिए गठित की गई थी. बाद में जब 1979 में इन तीनों जिलों की अलग-अलग जिला कमेटियां चुन ली गईं, तब कॉ. रघु आदिलाबाद जिला कमेटी के सचिव चुन लिए गए.

1980 में आयोजित 12वें अधिवेशन में उन्हें राज्य कमेटी के लिए चुन लिया गया और 1982 में वह सचिवालय के सदस्य चुन लिए गए. आदिलाबाद के आन्दोलन और सिंगरेनी कोयला खदानों के मजदूर आन्दोलन को उन्होंने प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान किया.

1984 में उन्हें आन्ध्र राज्य कमेटी के सचिव चुन लिया गया. 1984 के आखिर में पार्टी द्वारा छह बुराइयों के खिलाफ चलाए गए भूल सुधार आन्दोलन में उन्होंने समूची पार्टी को कुशल नेतृत्व दिया. इसी दौरान पार्टी को पहले अन्दरूनी संकट का सामना करना पड़ा. आन्ध्र इकाई के सचिव के नाते कॉ. आदिरेड्डी ने सही मार्क्सवादी-लेनिनवादी रुख अपनाते हुए, पार्टी

की श्रेणियों में सम्पूर्ण एकता हासिल करने में शानदार भूमिका निभाई. इसी बीच दुश्मन ने समूचे आन्ध्रप्रदेश में क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ अपना पहला आक्रामक युद्ध छेड़ दिया. टीम के नेता के नाते कॉ. रघु ने दुश्मन के आक्रामक युद्ध का मुकाबला करने के लिए पार्टी के दांवपेंच तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान किया.

इस दौरान दुश्मन ने कई कॉमरेडों को गिरफ्तार किया और यह सिलसिला कॉ. श्याम की गिरफ्तारी तक जारी रही. 1975-86 के बीच 11 साल के भूमिगत जीवन के बाद पहली बार कॉ. श्याम दुश्मन द्वारा पकड़ लिया गया. दुश्मन ने उन्हें अमानवीय एवं क्रूरतम यातनाएं दीं ताकि उनसे बाकी नेताओं पते जबरन उगलवाए जा सके. कॉ. रघु ने एक सच्चे क्रान्तिकारी एवं अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए, सभी यातनाओं को दृढ़ता से सह लिया और पार्टी की एक भी गुप्त जानकारी दुश्मन को नहीं दी. इन यातनाओं की बर्बरता की तीव्रता का अंदाजा इस सचाई से लगाया जा सकता है कि पिछले 13 सालों से, अपनी आखरी सांस तक वह असहनीय शारीरिक दर्द से पीड़ित थे. लेकिन अपनी सच्ची क्रान्तिकारी स्फूर्ति से उन्होंने अपने दर्द की वजह से पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आने दी.

जेल में रहते समय कॉ. श्याम ने स्वास्थ्य-लाभ करते हुए, क्योंकि यातनाओं के चलते उनकी सेहत बुरी तरह प्रभावित हुई थी, मार्क्सवादी-लेनिनवादी साहित्य के अध्ययन पर केन्द्रित किया. 1988 के मध्य में वह दो अन्य साथियों के साथ जेल के गारदों के हथियार छीनकर जेल से भाग निकले.

वह फिर एक बार राज्य कमेटी में सहयोजित कर लिए गए. अगस्त 1990 में वह आन्ध्र राज्य कमेटी के सचिव और नव गठित केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी (सी.ओ.सी.) के सदस्य चुन लिए गए. बाद में उन्होंने आन्ध्र, दण्डकारण्य और उत्तर तेलंगाना के इलाकों का विस्तृत दौरा किया ताकि आन्दोलन के बारे में अपनी समझ में आई दरार को दूर किया जा सके जो दो साल के जेल जीवन के चलते आई थी. उन्होंने 1989 में दण्डकारण्य में आयोजित फौजी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया ताकि अपनी फौजी समझदारी को बेहतर बनाया जा सके. इस बीच 1989-90 तक आन्दोलन ने फिर एक बार बुलंदियों को छू लिया. 1990 में आन्ध्र में दमन में अस्थाई तौर पर मिली ढिलाई के दौरान ठोस दांवपेंच तैयार करने में कॉ. श्याम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इसी समय पार्टी में फिर एक संकट उत्पन्न हुआ था. तब तक पार्टी के निर्विवाद नेता रहे कोंडापल्लि सीतारामैया के नेतृत्व वाला पार्टी-विराधी टोला इस संकट के लिए जिम्मेदार था. षडयन्त्रकारियों को पराजित करने और पार्टी की एकता को सुदृढ़ बनाने में कॉ. श्याम ने जबर्दस्त योगदान किया. इसी अवधि के दौरान उन्होंने कई रिपोर्टें और लेख लिखना एवं आन्दोलन में पनप रही समस्याओं का वैचारिक दृष्टिकोण से अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद अपने विचारों को शब्दों में ढालना शुरू किया. पार्टी द्वारा आयोजित राजनीतिक कक्षाओं में उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाया भी. व्यवहार और सिद्धांत का तालमेल करते हुए छात्रों को आसानी से समझाते हुए, कॉ. श्याम धीरे-धीरे एक बढ़िया शिक्षक के रूप में उभरे.

इस दौरान उन्होंने सीओसी द्वारा प्रारम्भ की गई सैनिक पत्रिका ***जंग*** के सम्पादक मंडल के सदस्य के तौर पर भी काम किया.

1992-94 के दौरान बुनियादी दस्तावेजों की तैयारी और इसके तहत चलाए गए अध्ययन और चर्चाओं ने कॉ. श्याम की राजनीतिक और वैचारिक समझदारी और भी बढ़ा दी. 18-20 साल तक मुख्य रूप से व्यवहार में ही अपना वक्त लगाने वाले और संघर्ष के इलाकों में हर निर्णायक मोड़ पर सीधा नेतृत्व प्रदान करने वाले कॉ. श्याम ने तब व्यवहार-अध्ययन-अध्ययन पर केन्द्रित करने का कर्तव्य स्वीकार किया ताकि वैचारिक नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता भी बढ़ाई जा सके. 1990 से अपनी शहादत के पल तक कॉ. श्याम ने अपना अधिकांश समय राज्य कमेटियों की बैठकों में शामिल होने या आन्ध्र और उत्तर तेलंगाना के इलाकों का अध्ययन करने में ही खर्च किया.

1998 में जब हैदराबाद के कुछ उदारवादी बुद्धिजीवियों ने पार्टी के प्रतिनिधिमंडल (जिसमें कॉ. श्याम और कॉ. महेश शामिल थे) से मुलाकात की और उनसे विस्तृत चर्चाएं की, तो इन कॉमरेडों ने उनके बूर्जुवाई जनवादी विचारों में मौजूद गलतियों को उजागर किया. साथ ही साथ, उन्होंने उनके समक्ष स्वीकार किया कि पार्टी की ओर से गलतियों को सुधारने की जरूरत है जो विभिन्न स्तरों के काडरों की समझदारी में दरार के चलते हो रही हैं. महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन मुद्दों पर पार्टी सदस्यों का ध्यान खींचने के लिए, सबसे पहले उन्होंने इन मुद्दों पर केन्द्रीय कमेटी में बहस करके, बाद में केन्द्रीय कमेटी की तरफ से एक सरकुलर तैयार किया.

पैनी निगरानी, सीधी-सपाट बोली, सामान्य और सादी जीवन शैली, साहसपूर्ण आचरण, साथी कॉमरेडों के साथ सस्नेह बरताव, निस्वार्थता, किसी भी कुरबानी के लिए तैयारी - ये थे कॉ. रघु के गुण. उन्होंने सही वर्ग दृष्टिकोण से काम करते हुए जनता और जन संगठनों को नेतृत्व प्रदान करने में एवं वर्ग संघर्ष में तपकर खुद को सुदृढ़ बनाने में बाकी कॉमरेडों के सामने खुद को मिसाल के तौर पर पेश किया. गलतियों को स्वीकारने में वे हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार रहते थे. दूसरे कॉमरेडों की खामियों की आलोचना करते समय, गलतियों को सुधारने में उनकी हर सम्भव सहायता करते हुए विशेष रूप से उनका खयाल रखते थे.

पिछले दस महीनों के दौरान उन्होंने उत्तर तेलंगाना के विभिन्न जिलों की जिला कमेटियों,पार्टी की श्रेणियों और पार्टी के हमदर्दों के साथ विस्तृत तौर पर चर्चाएं कीं. और केन्द्रीय कमेटी के सामने पेश करने के लिए कई रिपोर्टें तैयार कीं. उनमें कुछ अधूरी रह गई हैं.

आर्थिकवादी भटकाव को सुधारने और काडरों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयास के तहत कॉ. श्याम ने उत्तर तेलंगाना के व्यवहार को आधार बनाकर एक लेख लिखा जिसमें बताया गया कि पार्टी के काम में आर्थिकवाद किस तरह प्रतिबिम्बित होता है.

कॉमरेड श्याम एक अनुशासनबद्ध सैनिक थे जिन्होंने अपनी आखरी सांस तक पार्टी की दिशा पर दृढ़तापूर्वक अमल किया. उन्होंने कम्युनिस्ट आन्दोलन में वामपंथी और दक्षिणपंथी अवसरवाद के खिलाफ लगातार संघर्ष किया. अपने पूरे क्रान्तिकारी जीवन में कॉ. श्याम ने निर्भीकता और शूरता का प्रदर्शन किया. भारतीय क्रान्ति ने कॉमरेड श्याम की शहादत से एक प्रतिभाशाली रणनीतिज्ञ तथा एक रचनात्मक और आलोचनात्मक मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारक गंवा दिया. कहना नहीं होगा कि क्रान्ति चाहने वाली जनता को कॉमरेड श्याम हमेशा-हमेशा के लिए प्रेरणा देते रहेंगे और भारतीय क्रान्ति के लिए प्रकाश-स्तम्भ बने रहेंगे.

कॉमरेड महेश की बहादुराना शहादत जिन्दाबाद !

वरंगल जिले का कडवेण्डी गांव वह गांव है जहां महान तेलंगाना हथियारबन्द संघर्ष का रणनाद पहली बार किया गया था. यह वह गांव था जिसने उस महान और शानदार संघर्ष के पहले शहीद कॉमरेड दोड्डी कोमुरय्या को जन्म दिया था. यह वह गांव है जिसने कई बहादुर योद्धाओं को जन्म दिया. यह वह गांव है जिसने इन पूरे छह दशकों के दौरान सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ बगावत का परचम ऊंचा उठाकर रखा है. कॉमरेड येर्रमरेड्डी संतोष रेड्डी (महेश) उस ऐतिहासिक गांव का प्यारा सपूत है. अपनी शहादत के समय तक उन्होंने 40 की उम्र को पार नहीं किया. बचपन से ही वह कम्युनिस्ट राजनीति के बीचोंबीच पले-बढ़े थे. उन्हें संशोधनवादी और दक्षिणपंथी अवसरवादी नेताओं को और उनके व्यवहार को करीब से परखने का मौका मिला था. वरंगल के एल.बी. कॉलेज, जिसने कई अन्य क्रान्तिकारियों को जन्म दिया और जो रैडिकल छात्र आन्दोलन का केन्द्र था, में पढ़ते हुए उन्होंने रैडिकल छात्र आन्दोलन का नेतृत्व किया. वे दिन वह थे जब शहीद कॉमरेड पुलि अंजन्ना के नेतृत्व में क्रान्तिकारी छात्र आन्दोलन ने अपनी बुलंदियों को छू लिया और दर्जनों कार्यकर्ता और नेता पेशेवर क्रान्तिकारियों में तब्दील होने लगे. कम समय में ही कॉ. सन्तोष एक छात्र नेता और पेशेवर क्रान्तिकारी के रूप में उभरे थे. बाद में उन्होंने वरंगल छोड़ दिया और हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया.

1981 में पहली बार गठित हैदराबाद नगर कमेटी में कॉ. संतोष को सदस्य चुन लिया गया जो तब तक शहर के छात्र आन्दोलन के जिम्मेदारी लेकर पेशेवर क्रान्तिकारी के तौर पर काम कर रहे थे. तबसे उन्होंने न सिर्फ छात्र आन्दोलन के निर्माण करने में, बल्कि मजदूर, महिला और जनवादी आन्दोलनों के निर्माण करने में भी अन्य साथियों के साथ बेहद परिश्रम किया. 1984 में, तत्कालीन राज्य कमेटी ने कॉ. संतोष को खम्मम जिले में आन्दोलन का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी देकर वहां जिला संगठक के तौर पर भेजा था. लेकिन जल्द ही एक गद्दार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने कॉ. संतोष को गिरफ्तार किया. 1985 से 1990 तक, लगभग पांच साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा. उन्होंने इस समय का खुद को सुदृढ़ बनाने के लिए बेहतर इस्तेमाल किया. उन्होंने न केवल अध्ययन पर ध्यान दिया बल्कि सैद्धांतिक और विचारधारात्मक ज्ञान को बढ़ाया और जेल की जिन्दगी काट रहे अपने साथी कॉमरेडों को सही दिशा में ढालने पर विशेष ध्यान दिया. इस अवधि में उन्होंने अलग-अलग जेलों की पार्टी इकाइयों का नेतृत्व किया. जेल की लम्बी जिन्दगी ने उनके क्रान्तिकारी जोश पर पानी नहीं फेरा. बल्कि जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने एक परिपक्व राजनीतिक नेता के तौर पर क्रान्तिकारी आन्दोलन की जिम्मेदारी उठाई.

उन्होंने उत्तर तेलंगाना के जंगल इलाके की जिम्मेदारी ली. यह वह समय था जबकि उन्होंने उन क्षमताओं को प्राप्त किया जो भविष्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन के निर्माण करने के लिए जरूरी थीं, और फिर एक बार खम्मम के आन्दोलन के साथ जीवंत सम्पर्क साधकर तथा आन्दोलन के विकासक्रम को प्रत्यक्ष रूप से समझते हुए संगठनात्मक ढांचे पर पकड़ और स्पष्टता हासिल की. 1991 में उन्हें उत्तर तेलंगाना फॉरेस्ट डिवीजन के सचिव चुन लिया गया जो पहली बार गठित की गई थी. बाद में वह रीजिनल कमेटी में भी चुन लिए गए और 1993 तक उस पद पर काम करते रहे.

उन्होंने दक्षिणपंथी अवसरवादियों द्वारा भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के खिलाफ छेड़े गए हथियारबन्द हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाले दस्तों का नेतृत्व किया. उत्तर तेलंगाना रीजिनल कमेटी में उन्हें लिए जाने के बाद, उत्तर तेलंगाना के बाकी चार जिलों के आन्दोलनों के बारे में समझ हासिल करने के लिए उन्होंने 1991 से 1992 तक कड़ा परिश्रम किया. इसी अवधि में पार्टी ने दूसरे आंतरिक संकट का सामना किया, और कॉ. संतोष ने पार्टी में सही दिशा के समर्थन में किए गए प्रयास में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

1993 में कॉ. महेश को दक्षिण तेलंगाना की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं. उन्होंने मेदक जिले में प्रत्यक्ष रूप से आन्दोलन का निर्माण करने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली. वह उस रीजिनल कमेटी के सचिव चुन लिए गए और पूरे आन्दोलन को समझने के लिए विशेष प्रयास किया. यह वह समय था जबकि उन्होंने बुनियादी स्तर पर जाकर, आन्दोलन को और कॉमरेडों के हालात को समझा. इस तरह उन्होंने स्पष्ट समझ हासिल की कि आन्दोलन को किस तरह मजबूत बनाया जा सकता है और खामियों को किस तरह दूर किया जा सकता है.

कॉ. महेश को आन्ध्रप्रदेश के राज्य प्लेनम में राज्य कमेटी में चुन लिया गया जो 1993 के आखिर में सम्पन्न हुआ था. जेल से रिहा होने के बाद 4-5 सालों में उन्होंने न सिर्फ उत्तर और दक्षिण तेलंगाना के आन्दोलनों का नेतृत्व किया, बल्कि हैदराबाद-सिकंदराबाद जुगल शहरों की जिम्मेदारी भी बांट ली. उन्होंने ऐसी अनगिनत समस्याओं का जिनका सामना जन संगठनों को करना पड़ रहा है, विश्लेषण करके राज्य कमेटी के सामने पेश किया ताकि उनका निराकरण किया जा सके. इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन में आन्ध्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. वह विशेष अधिवेशन के तमाम प्रतिनिधियों द्वारा स्पष्ट राजनीतिक समझ हासिल नेता के तौर पर तब सराहे गए जब उन्होंने दो मुद्दों पर पार्टी की समझदारी को बदलने में सभी को मनाया था. इस अधिवेशन में वह नई केन्द्रीय कमेटी के लिए चुन लिए गए. पिछले चार सालों के दौरान कॉ. महेश लगातार एक ऐसे परिपक्व नेता के रूप में उभरते गए जिन्होंने आन्ध्र के आन्दोलन के अनुभवों की बुनियाद पर समूची पार्टी की औसत समझ को बढ़ाने में बेहद प्रयास किया.

विचारधारा के कार्य में कॉ. महेश की असाधारण भूमिका का विशेष जिक्र करना होगा. उदारपंथी बुद्धिजीवियों, जिन्होंने दुश्मन द्वारा अपनाए गए

रुख को समझे बिना उनकी अपनी सीमाओं के मुताबिक आन्दोलन पर सीमाएं निर्धारित करने की कोशिश की, के जवाब में उनका जबर्दस्त योगदान रहा. एक युवा विचारक के तौर पर कॉ. महेश ने राज्य सचिव के नाते महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसकी बदौलत उदारपंथियों के हमलों से क्रान्तिकारी आन्दोलन का बचाव करने में पार्टी ने अपनी पहलकदमी नहीं गंवाई.

1995-98 का दरमियानी वक्त ऐसा वक्त था जब नकली मार्क्सवादियों, नारीवादियों, रूढ़िवादियों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिक्रियावादियों ने प्रगतिशील होने का दिखावा करते हुए मार्क्सवाद के खिलाफ तरह-तरह के तर्कों से एक बड़ा आक्रमण छेड़ दिया जैसे कि मार्क्सवाद ने जाति सवाल, महिला सवाल, तबकाती (sectional) आन्दोलनों वगैरह पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, और कि इन सवालों का हल करने में मार्क्सवाद अपर्याप्त था. आन्ध्र में जाति सवाल, महिला सवाल और बाकी सवालों पर अपनाए जाने वाले दांवपेंच निर्धारित करने में कॉ. महेश ने पार्टी की दिशा को सही तरीके से प्रतिबिम्बित किया.

और तो और, कॉ. महेश ने 'विजन 2000' की नीतियों का पर्दाफाश करने में आन्ध्र राज्य कमेटी का नेतृत्व किया. दरअसल इसे विश्व बैंक ने तैयार किया और चन्द्रबाबू द्वारा अपनी 'जन्मभूमि', 'महिला जन्मभूमि', 'जनता के आंगन में प्रशासन' आदि अन्य योजनाओं की तरह बड़े पैमाने पर उछाली जा रही थी.

पिछले 7-8 सालों के दौरान जबकि दुश्मन के एस.आइ.बी. के गिरोह के अधिकारियों ने पार्टी के राज्य और केन्द्र के नेतृत्व का सफाया करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रखा था, राज्य कमेटी ने अपनी पहलकदमी नहीं गंवाई जिसका श्रेय कॉ. महेश को जाता है.

वह एक सेना के जनरल थे जो दुश्मन के दांवपेंच के खिलाफ समुचित दांवपेंच तैयार करके जंग छेड़ने और क्रान्तिकारी ताकतों को जरूरत के मुताबिक तैनात करने हमेशा मुस्तैद रहा करते थे. क्रान्तिकारी आन्दोलन की ठोस समस्याओं के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को रचनात्मक तरीके से लागू करने में उन्होंने अपने विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन किया. 1999 के फरवरी में आयोजित आन्ध्र के राज्य प्लेनम में यह तब साफ जाहिर हुआ जब उन्होंने प्रतिनिधियों के सामने भूल-सुधार आन्दोलन का एक ठोस कार्यक्रम तैयार करके पेश किया ताकि उदारतावाद, सद्योजनिता (spontaneity), आर्थिकवाद, नौकरशाहाना दुष्टिकोण, मनोगतवाद वगैरह गलतियों को पार्टी से निकाल बाहर किया जा सके.

एक भीतरी गद्दार को पाकर शासक वर्गों ने अस्थाई तौर पर जीत हासिल की है. आज कॉ. महेश ऐसी एक गद्दारी का शिकार बन गए. एक योद्धा की मौत से आंसू नहीं निकलेंगे, वह हमारे फर्ज की याद दिलाती है. कॉ. महेश एक अनुकरणीय नेता थे जिन्होंने हमेशा अपना सिर ऊंचा रखकर दृढ़ता का परिचय दिया, और तब भी मैदान-ए-जंग नहीं छोड़ा जबकि दुश्मन ने उन्हें बोटी-बोटी काट दिया. जनता के प्यारे नेता कॉ. महेश, जिन्होंने क्रान्ति की नाव को तूफानी समंदरों में छिपी चट्टानों से बचाकर कुशलता से पार कराते हुए सिद्धांत और व्यवहार का तालमेल बिठाया, का नाम हमेशा-हमेशा के लिए याद किया जाएगा.

कॉमरेड मुरली को लाल-लाल सलाम!

कॉमरेड मुरली उत्तर तेलंगाना के उत्पीड़ित जन-समुदायों का नाज हैं. दो दशकों तक, 1981 से 1999 तक उन्होंने प्रचण्ड तूफानों के बीच संघर्ष की नाव को पीड़ादायक खाड़ियों द्वारा सुरक्षित ले जाते हुए, आन्दोलन के दरमियान कई ज्वार-भाटाओं का मुकाबला करने वाले एक वरिष्ठ नाविक की तरह दृढ़तापूर्वक डटे रहकर पार्टी का नेतृत्व किया. एक शब्द में उनकी जिन्दगी खून से लथपथ तेलंगाना का इतिहास है. उनके बारे में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि एक सीधी-सादी सचाई है कि उत्तर तेलंगाना में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां उन्होंने कदम नहीं रखा हो, ग्रामीण जन-समुदायों का कोई ऐसा तबका नहीं हैं जिसे उन्होंने गोलबन्द नहीं किया हो, और क्रान्तिकारी शिविर का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने उनका नाम नहीं सुना हो.

कॉमरेड शीलम नरेश का जन्म करीमनगर जिले के जगित्याल कस्बे के एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था. जगित्याल और सिरसिल्ला के सामंतवाद विरोधी संघर्षों की सरसराहट ने कॉ. नरेश को जगा दिया जो उस समय सिरसिल्ला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे थे. उन्होंने रैडिकल छात्र संगठन को संगठित करने की जिम्मेदारी उठाई और न सिर्फ सिरसिल्ला में बल्कि मेटपल्लि, जगित्याल, कामारेड्डी और निजामाबाद कस्बों में रैडिकल छात्र आन्दोलन का नेतृत्व किया. कम समय में ही वह सिरसिल्ला और कामारेड्डी इलाकों में संगठक के तौर पर जम गए.

कॉमरेड नरेश सिर्फ 20 साल के युवा थे जब उन्होंने पेशेवर क्रान्तिकारी के रूप में आन्दोलन की जिम्मेदारियां लीं. वह तब शादीशुदा और एक बच्ची के बाप भी थे. चूंकि उनकी पत्नी परम्परागत तौर-तरीकों में पली-बढ़ी थीं और क्रान्तिकारी जीवन के लिए तैयार नहीं थीं, इसलिए उन्होंने उनके साथ वैवाहिक जीवन जारी नहीं रखा. 1982-84 से उन्होंने कामारेड्डी इलाके में किसान आन्दोलन का नेतृत्व किया. 1984 में आयोजित पहले जिला अधिवेशन में उन्हें जिला कमेटी के लिए चुन लिया गया. उन्होंने कामारेड्डी के अलावा अन्य केन्द्रों की जिम्मेदारियां भी उठाईं. आन्दोलन में कदम रखने के बाद से वह कभी दुश्मन की गिरफ्त में नहीं आए. उन्होंने कभी भी किसी खुली गतिविधि में भाग नहीं लिया. कॉलेज छोड़कर उन्होंने सीधा मैदान-ए-जंग में कदम रखा, दुश्मन के खिलाफ लड़ाई के दौरान एक सुदृढ़ और कठोर छापामार का जीवन जीया, और आन्दोलन के हर मोड़ में असाधारण नेतृत्व प्रदान किया. इसीलिए कॉ. मुरली के नाम सुनने से ही डर से कांपने वाले दुश्मन को समर्पित दलालों पर निर्भर होना पड़ता था.

1985 से दुश्मन ने दमन का एक नया अभियान छेड़ा था. समूचे उत्तर

तेलंगाना में विशेष हथियारबन्द पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों को बड़े पैमाने में तैनात किया गया, और उन्होंने खोजबीन कार्रवाइयां और घात हमले छेड़ दिए. इस दौरान कॉ. नरेश ने जिनके जिम्मे में पश्चिम में निजामाबाद से लेकर पूर्व में उत्तर तेलंगाना फॉरेस्ट डिवीजन तक फैले हुए विशाल इलाके में जारी आन्दोलन था, न सिर्फ इन हमलों का व्यक्तिगत तौर पर मुकाबला किया, बल्कि अपने साथी नेताओं और दस्तों को दुश्मन का प्रतिरोध करने में संगठित किया. इन बीस सालों में वे दुश्मन द्वारा लगाए गए अनगिनत घात हमलों और मुठभेड़ों से कॉमरेडों को सुरक्षित बाहर लाते हुए एक वरिष्ठ जनरल के रूप में उभरे. इसीलिए जब वह केन्द्रीय कमेटी का सदस्य भी बने थे, तब भी पीछे हटने वाले दस्तों में से अपने दस्ते के वह खुद ही कमाण्डर थे. इसीलिए पीपुल्सवार के छापामारों का उन पर अटल भरोसा था.

पहले अघोषित युद्ध के दौरान कॉ. मुरली ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर नेतृत्व का मोर्चा संभाला ताकि जनता अपनी पहलकदमी न गंवा दे. उन्होंने समूचे निजामाबाद जिले में जन संगठनों के निर्माण का काम उठाया. मजदूरी में बढ़ोत्तरी के लिए तेंदुपत्ता मजदूरों के संघर्ष, खेतिहर नौकरों के संघर्ष, दिहाड़ी मजदूरों के संघर्ष, अपने उत्पादों के लिए वाजिब दाम के लिए किसानों के संघर्ष, जंगली जमीनों पर कब्जा करने के लिए संघर्ष, जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष, जाति के सवाल के पर संघर्ष, खासतौर पर दलितों पर हो रहे हमलों के खिलाफ, पुलिसिया अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष जैसे अनगिनत संघर्षों में कॉ. मुरली ने जन-समुदायों को गोलबन्द करके, जन-मानस को पढ़ा, जनता की नब्ज पकड़ी और जन-समुदायों के नेता बन गए. निजामाबाद आन्दोलन का इतिहास यह दर्शाता है कि आन्दोलन की कोख से नेता कैसे उभर कर सामने आते हैं.

कॉमरेड मुरली को बात करने में सीधापन, एक बड़ा नेता होने का दिखावा कभी न करते हुए हर एक के साथ घुल-मिल जाने, जीवन-शैली में सादगी, अस्वस्थता के चलते कमजोर पड़ने से भी किसी भी तरह की विशेष सुविधाओं की मांग न करने की निस्वार्थता, ऐसी क्रान्तिकारी जिन्दगी जिसमें रत्ती भर ढुलमुलपन भी कभी प्रदर्शित नहीं किया गया हो वगैरह-वगैरह क्रन्तिकारी आदर्शों के लिए हमेशा याद किया जाएगा.

1987 में कॉ. मुरली को जिला कमेटी का सचिव और उत्तर तेलंगाना रीजिनल कमेटी का सदस्य चुन लिया गया. कॉ. अयिलन्ना, कॉ. राजलिंगु और कॉ. मुरली की यह तिकड़ी उत्तर तेलंगाना के नए नेतृत्व के रूप में उभरी. लेकिन चूंकि पहले के दो कॉमरेड क्रमशः 1987 और 1988 में शहीद हो गए, इसलिए रीजिनल कमेटी कुछ समय के लिए काम नहीं कर सकी और जिला कमेटी ने सीधा राज्य कमेटी के तहत ही काम किया. इस दौरान करीमनगर के नेतृत्व में नुकसान होने से कॉ. मुरली को करीमनगर भेजा गया और उन्होंने जिला सचिव के रूप में करीमनगर का नेतृत्व सम्भाला. 1989 तक दुश्मन के पहले हमले का मुकाबला करते हुए और जनता को बड़े पैमाने पर गोलबन्द करते हुए उत्तर तेलंगाना के सभी जिलों में नेतृत्व की नई टीमें उभरीं. दुश्मन के पहले हमले को पराजित किया गया. 1989 में उत्तर तेलंगाना की रीजिनल कमेटी को पुनरगठित किया गया जिसका सचिव कॉ. मुरली बने थे.

1989-99 के दौरान कॉ. मुरली ने आन्दोलन में आए कई उतार-चढ़ावों के बावजूद आन्दोलन की नेतृत्वकारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं. तबसे लेकर अपनी शहादत तक कॉ. मुरली पार्टी के नेतृत्वकारी केन्द्र के एक सदस्य के तौर पर और दुश्मन के दांवपेंच का मुंहतोड़ जवाब देने वाले जवाबी दांवपेंच तैयार करने में एक माहिर रणनीतिज्ञ के तौर पर उभरे. 1987-89 के दौरान वे प्रशिक्षण लेने गए थे ताकि फौजी जिन्दगी के लिए जरूरी तकनीकों को हासिल किया जा सके. कॉ. मुरली की पहलकदमी का खास जिक्र करना मुनासिब होगा जिसे उन्होंने दुश्मन के रोजाने के हमलों का मुकाबला करने, जवाबी हमलों की योजनाएं रचने और विद्रोह-विरोधी कार्रवाइयों के नाम पर राज्य के बलों द्वारा अपनाए गए दांवपेंच को पलटकर जवाब देने में दिखाया. पेट में अल्सर के चलते काफी बीमार होने के बावजूद कॉ. मुरली ने खुद को छापामार जिन्दगी की मुश्किलों में में ढाला और कड़े अनुशासन का पालन किया.

1990 में आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी की प्लेनम बैठक ने कॉ. मुरली को उस कमेटी के सदस्य के तौर पर चुन लिया. अपने उत्तर तेलंगाना संघर्ष के अनमोल अनुभव के बदौलत, उन्होंने दक्षिण तेलंगाना और आन्ध्र के बाकी संघर्ष के इलाकों में वर्ग-संघर्ष को तेज करने के लिए आवश्यक नीति-निर्धारण करने और उन संघर्षों को छापामार इलाके की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 1989-95 के दौरान कॉमरेड मुरली रीजिनल कमेटी के सचिव बने रहे.

1995 में आयोजित अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन में कॉ. मुरली को केन्द्रीय कमेटी के वैकल्पिक सदस्य के तौर पर चुन लिया गया. 1995 में उत्तर तेलंगाना एक विशेष इलाके के रूप में उभरा था. उसके सचिव के नाते 1997 में वे केन्द्रीय कमेटी के मुकम्मल सदस्य बन गए. उन्होंने केन्द्रीय कमेटी में आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दांवपेंच और नीति-निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

इस अवधि के दौरान, 1997 में दुश्मन द्वारा छेड़े गए नए आक्रमण के मद्देनजर, कॉ. मुरली ने दुश्मन के खिलाफ किए गए घात हमलों और रेइडों की योजनाओं की खामियों का जायजा लेने और दस्तों को शिक्षित करने में काफी मेहनत की. हमारे दस्तों और जिला कमेटियों की कमजोरियों का पता लगाकर, उन्होंने उन्हें विशेष सावधानियां बरतने का मार्गदर्शन दिया ताकि दुश्मन के हमलों से सुरक्षित बच निकल सकें.

ऐसे मौकों पर जबकि हमारी अपनी कमजोरियों के चलते कई नुकसान उठाने पड़े हों, कॉ. मुरली उन इलाकों के कॉमरेडों को अपनी कमजोरियों से उबरने के लिए व्यक्तिगत तौर पर और धैर्य के साथ समझाते, आदेश देते और मार्गदर्शन करते थे. उन्होंने खुद इलाके में रहते हुए काडरों को ठोस मार्गदर्शन उपलब्ध कराया.

कॉमरेड मुरली ने अपनी 20 साल की क्रान्तिकारी जिन्दगी उत्तर तेलंगाना के उत्पीड़ित जन-समुदायों के बीच, आन्दोलन के हर मोड़ पर उनसे एकताबद्ध होते हुए और मार्गदर्शन करते हुए बिताई. कॉ. मुरली केन्द्रीय कमेटी के सदस्यों में से सबसे कम उम्र (39 साल) के थे. उनकी शहादत से भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन ने जनता के एक युवा और जमीन से जुड़े नेता खो दिया. आइए, हम हमारे इस प्यारे नेता को लाल सलाम पेश करेंगे, जिन्होंने 20 साल तक तेलंगाना का दौरा करके उस मिट्टी में अमिट पदचिन्ह छोड़ दिए और आन्दोलन के इतिहास में अपने लिए स्थाई जगह हासिल की!

समूचे देश में जनयुद्ध के शोले भड़काकर सामंती-दलाल पूंजीवादी-साम्राज्यवादी टोले के फासीवादी हमले को मात दो !

लुटेरे साम्राज्यवादी गिद्धों द्वारा समर्थित भारतीय शासक वर्ग सुनहरे सपने देख रहे हैं कि हमारे प्यारे नेताओं को कत्ल करके वे पीपुल्सवार को और भारत में फिलहाल चल रहे जन संघर्षों को कुचल सकेंगे. तीखे वर्ग-संघर्ष और राष्ट्रीयता संघर्षों वाले इलाकों में सफेद आतंक मचाकर, वे निर्भीकता से देश को साम्राज्यवादी और दलाल नौकरशाही पूंजी के बेलगाम शोषण के लिए एक मुफ्त शिकारगाह बनाने की योजनाएं रच रहे हैं. वे क्रान्तिकारी और जनवादी आन्दोलनों का और भी व्यापक और ज्यादा क्रूरतापूर्ण दमन की तैयारियां कर रहे हैं.

विश्व पूंजीवादी व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था का लगातार बढ़ता संकट; देश में उत्पीड़ित जनता और राष्ट्रीयताओं पर बढ़ते शासक वर्गों के हमले ताकि विश्व बैंक-आइएमएफ-विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों पर अमल किया जा सके; रिआयतों में कटौतियां, भारी-भरकम करों को लागू करना, मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों की छंटनी वगैरह-वगैरह से बहुसंख्यक किसानों की कंगाली, बेरोजगारी, महंगाई और भयानक गरीबी बेहद बढ़ रही हैं. परिणामस्वरूप जनता ने यह समझना शुरू किया कि क्रान्ति ही एक मात्र विकल्प है ताकि खुद को सामंती और साम्राज्यवादी उत्पीड़न से मुक्त किया जा सके. यहां तक कि अपनी रोजमर्रा की समस्याओं पर भी उन्हें जूझारू संघर्षों में उतरने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और अक्सर राज्य के हथियारबन्द बलों से भिड़ना पड़ रहा है.

देश में बढ़ते संकट और शक्तिशाली जन आन्दोलन की सम्भावनाओं की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, शासक वर्गों ने भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के नेतृत्व का उन्मूलन करने की भरसक कोशिश शुरू की है ताकि जन आन्दोलनों को नेतृत्वविहीन बनाया जा सके. इस तरह की जघन्य हत्याओं के जरिए वे जनयुद्ध के लगातार बढ़ते प्रवाह को रोक सकने के मीठे सपने देख रहे हैं.

आन्ध्र में, विश्व बैंक के लाड़ले पालतू कुत्ते चन्द्रबाबू नाइडू ने क्रान्तिकारियों को क्रूरता से कत्ल करने में लातिनी अमरीका के निर्दयी तानाशाहों को भी पीछे छोड़ दिया. केन्द्र में भाजपा नेतृत्व वाली गठबन्धन सरकार के सक्रिय सहयोग से, नाइडू ने भारी कोष आवंटित करके और आन्ध्र के एस.आइ.बी. व ग्रे-हाउण्ड्स के गुण्डों को मनमानी हत्याएं करने का लाइसेंस देकर आन्ध्र में पुलिस-राज को और भी तगड़ा बना दिया. इन हमलावरों ने आन्ध्र में क्रान्तिकारियों और हमदर्दों पर अकथनीय अत्याचार किए हैं. हमारे नेताओं की हत्या करने के बाद, उन्होंने पीपुल्सवार के नेतृत्व में अंदरूनी अनबन होने, सर्वोच्च स्तर के नेताओं द्वारा आत्मसमर्पण की संभावनाएं होने, पार्टी को और वर्तमान जनयुद्ध को कुचल दिए जाने आदि अफवाहें फैलाते हुए झूठा प्रचार अभियान छेड़ दिया.

देशवासियों ने एक महीने से भी ज्यादा अवधि तक जन-प्रतिरोध खड़ा करके इस झूठे प्रचार अभियान का मुंहतोड़ जवाब दिया. जवाबी कार्रवाइयां और जन-प्रतिरोध की घटनाएं भारत के कई हिस्सों में फैल गईं; समूचे उत्तर तेलंगाना और आन्ध्र के बाकी इलाकों में तमाम सरकारी कामकाज ठप्प हो गए. दुख और शोक में डूबने वाले क्रान्तिकारी जन-समुदायों ने उसे दुश्मन के खिलाफ धधकती वर्ग-घृणा में बदल लिया और भारत की धरती से सामंतवाद, साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाही पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए जनयुद्ध को तेज बनाकर हमारे लोक-नायकों के सुंदर सपनों को साकार बनाने का अपना संकल्प पक्का कर लिया.

आइए, हम इन शासक वर्गों को मिटा देने की शपथ लें जो एक अस्थाई जीत पर जश्न मना रहे हैं. हम एक हाथ से हमारे शहीद कॉमरेडों के लिए आंसुओं को पोंछते हुए, दिल में घुमड़ रहे शोक को दबा लेंगे. हमारे स्तब्ध मनों को सख्त बनाएंगे. शहीदों के खून से सिंचित लाल झण्डे को हम करोड़ों विशाल जन-समुदायों तक पहुंचाएंगे. हम शपथ लेंगे कि अटल संकल्प के साथ लड़ते हुए मैदान-ए-जंग में धराशायी होने वाले हजारों शहीदों के खून से सने लाल परचम को ऊंचा उठाकर रखेंगे. हम शपथ लेंगे कि हम हमारे नेता कॉ. श्याम, कॉ. महेश और कॉ. मुरली की शहादत को महान आदर्श के रूप में स्वीकार कर अंतिम विजय प्राप्त होने तक लड़ाई को जारी रखेंगे. वही और सिर्फ वही हमारे शहीदों के प्रति सच्चा सम्मान होगा. ✪

पार्टी के केन्द्रीय नेताओं की जघन्य हत्या के खिलाफ 15 जनवरी को उत्तर बस्तर बन्द

भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) की उत्तर बस्तर डिवीजनल कमेटी ने हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के नेता कॉमरेड श्याम, महेश और मुरली सहित एक आम किसान कॉ. अरुण की हत्या के खिलाफ 15 जनवरी को 'उत्तर बस्तर बन्द' का आह्वान किया. छापामार दस्तों और जन संगठनों ने गांव-गांव में सभाओं का आयोजन करके लोगों को शहीदों की जीवनियों के बारे में, आन्दोलन के विकास के लिए उनके द्वारा निभाई गई भूमिका, भारत की उत्पीड़ित जनता के लिए अपना सब कुछ छोड़कर दी गई उनकी जान की कुरबानी के बारे में बताया गया. जनता ने शहीद नेताओं की जघन्य हत्या के लिए जिम्मेदार दुश्मनों का बदला लेने की शपथ लेते हुए उन्हें श्रद्धांजलि पेश की. पूरे डिवीजन में पोस्टरों और पर्चों के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार चलाया गया. बन्द के कार्यक्रमों में कोइलीबेड़ा, डौला, कोण्डागांव और केसकाल दस्ता इलाकों में हजारों लोगों ने भाग लिया.

इस बन्द का व्यापक असर रहा. बन्द के दो दिन पहले नारायणपुर-कोण्डागांव मुख्य सड़क पर राज्य परिवहन निगम की एक बस को डीएकेएमएस और केएएमएस के दर्जनों सदस्यों और छापामारों ने मिलकर जला डाला. बन्द के दिन उत्तर बस्तर में स्थित नारायणपुर, कोण्डागांव, केसकाल, अंतागढ जैसे प्रमुख कसबों में बन्द का पूरा असर दिखाई दिया. दुकानें बन्द रहीं.

दस्ते के कुछ छापामारों के साथ लोगों ने बन्दूकों और भरमारों से अन्तागढ़ थाने पर हमला किया. 15 जनवरी की रात थाने पर गोलीबारी करके जनता ने पुलिस को आतंकित कर दिया. शहीदों को सलाम कहते हुए, पुलिस का बदला लेने के नारे देते हुए लोग वापस आ गए. केसकाल दस्ता इलाके के ग्राम सरंडी में और कोइलीबेड़ा इलाके के ग्राम बड़गांव में जनता ने सब्बल, फांवड़े, कुल्हाड़ियां आदि से लैस लेकर वन विभाग और पटवारी के भवनों को तोड़ डाला. कोइलीबेड़ा कस्बे में स्थित विकासखण्ड के कार्यालय को सैकड़ों लोगों ने जलाकर, वहां जोरदार नारेबाजी की. सरकार द्वारा की गई हमारे नेताओं की कायरतापूर्ण हत्याओं की निंदा की.

जोर शोर की नारेबाजी से कॉमरेड महेश की अंतिम विदाई !

कोय्युरु झूठी मुठभेड़ में मारे गए कॉमरेड श्याम, मुरली और महेश को लोगों ने क्रान्तिकारी परम्पराओं के साथ विदाई दी. 3 और 5 दिसम्बर को कॉ. श्याम और कॉ. मुरली के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने भाग लिया. हैदराबाद के उच्च न्यायालय द्वारा दोबारा पोस्टमॉर्टम के आदेश के चलते कॉ. महेश का अंतिम संस्कार 10 दिसम्बर को उनके गांव कडवेण्डी में सम्पन्न हुआ. इसके पहले कडवेंडी में आयोजित होने वाले कॉ. महेश के अंतिम संस्कार में भाग लेने का आह्वान करते हुए राज्य भर में पोस्टर व पर्चे बांटे गए. भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के सचिव कॉमरेड गणपति ने अखबारों को भेजे एक वक्तव्य में हजारों की संख्या में शहीदों की अंत्येष्टि में भाग लेने का जनता से आह्वान किया. सुबह साढ़े दस बजे कॉ. संतोष की लाश को एक ट्रैक्टर में रखकर अंतिमयात्रा निकाली गई. उनकी लाश पर लाल झण्डा ओढ़ दिया गया. करीब 20 साल पहले गांव छोड़कर अब लाश बनकर वापस आने वाले इस शहीद नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों लोग आए थे जिनमें हर उम्र के लोग शामिल थे. कॉ. संतोष की शहादत की खबर फैलते ही पूरे गांव में दीवारों पर नारे लिखे गए थे. गांव में कई स्थानों पर बैनर लगाए गए थे जिनमें 'पीपुल्सवार के राज्य सचिव कॉ. संतोषरेड्डी अमर रहें' का नारा लिखा गया था. इस अंतिम यात्रा में लोगों को भाग लेने के लिए रोकने के लिए पुलिस ने हर संभव कोशिश की. कडवेण्डी की ओर आने वाली सभी बसों को रोक दिया गया. हजारों लोगों को जबरन वापस भेज दिया गया. ट्रक आदि वाहनों को पहले ही जब्त करके थानों में जमा करा दिया गया. इसके बावजूद, इस दमन का विरोध करते हुए हजारों लोग पैदल ही कडवेंडी पहुंच गए और इस अंत्येष्टि में भाग लेकर शहीद नेता को अंतिम सम्मान दिया.

अंतिम यात्रा में भाग लेने वाले लोगों ने अपने हाथों में लाल झण्डे थाम लिए थे, जबकि अलग-अलग क्रान्तिकारी जन संगठनों के नेताओं ने सरकार द्वारा की जा रही नृशंस हत्याओं और जन आन्दोलनों पर छेड़े गए पाशविक दमन के विरोध में काले झण्डे थाम लिए. 'कॉमरेड संतोषरेड्डी अमर रहें', 'अमर शहीदों को लाल सलाम', 'क्रन्तियों का युग है हमारा - लड़ने से जीत हमारी', 'पीपुल्सवार जिन्दाबाद', 'चन्द्रबाबू के लोक-हंतक शासन का नाश हो' आदि नारे लगाए गए. जन नाट्य मंडली के कॉ. गद्दर ने कॉ. महेश पर लिखे गीत गाए तो तमाम लोगों ने उनसे गले मिलाए. करीब साढ़े तीन बजे तक यह जुलूस गांव के पास की एक नदी पहुंचने के बाद समाप्त हो गया जहां वह सभा में परिवर्तित हो गया.

कॉ. संतोष की लाश के गिर्द लोगों को बिठाकर चारों तरफ लाल झण्डे गाड़कर वक्ताओं ने स्मारक भाषण दिया. क्रान्तिकारी जन संगठनों के नेताओं ने कॉ. महेश के अलावा कॉ. श्याम और कॉ. मुरली के साथ अपनी यादें लोगों को बताईं. इस शहीद-सभा को क्रान्तिकारी लेखक संघ के नेता कॉ. वरवर राव, अखिल भारतीय क्रान्तिकारी सांस्कृतिक संघ के कॉ. गद्दर, आंध्रप्रदेश मानवाधिकार संगठन की अध्यक्ष कॉ. रत्नमाला और कॉ. शेषय्या, जनकवि कलोजी नारायण राव, जनशक्ति के नेता कॉ. चल्लापल्लि श्रीनिवास, महिला चैतन्य समाख्य की नेता कॉ. अनुराधा के अलावा प्रजाप्रतिघटना, प्रतिघटना, तेलंगाना जनसभा आदि जन संगठनों के अन्य नेताओं ने संबोधित किया.

इस अंत्येष्टि के दौरान ही सभा में एक वक्ता ने भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के केन्द्रीय सचिव कॉ. गणपति के प्रेस बयान को पढ़कर सुनाया जिसमें यह विस्तार से बताया गया था कि किस तरह पुलिस ने गोविन्देरेड्डी नामक एक गद्दार के जरिए हमारे तीनों नेताओं की निर्मम हत्या की. इसी मौके पर इन तीन शहीदों की याद में छपी एक पुस्तक 'जनयुद्ध के योद्धा' का विमोचन भी कॉ. गद्दर ने किया.

शहीदों की अंत्येष्टियों में व्यापक तौर पर भाग लेकर जनता ने साबित कर दिया कि सरकार ने जिन नेताओं की कायरता से, एक गद्दार के सहारे सरकार ने हत्या की उन्हें अपने दिलों में बसा लिया है. जनता ने उन तथाकथित बुद्धिजीवियों और उदारपंथियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिनका कहना है कि पीपुल्सवार का जनाधार घट चुका है. *दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी* बहादुर जनता को, विभिन्न क्रान्तिकारी जन संगठनों एवं मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों को आभार प्रकट करती है जिन्होंने शहीद नेताओं की हत्या का जोरदार खण्डन करते हुए राजकीय आतंक का पर्दाफाश किया और अंतिम संस्कार में बढ़-चढ़कर भाग लिया. ✪

कडवेंडी के सपूत कॉमरेड संतोष को लोगों की अश्रुपूरित विदाई का एक दृश्य

पीपुल्सवार के खिलाफ एमसीसी की लड़ाई का अब बिहार से बंगाल तक विस्तार

हाल ही में एमसीसी ने पश्चिम बंगाल के मिडनापुर जिले के बेलपहारी प्रखण्ड के बन्सबहार इलाके में भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के राज्य कमेटी सचिव कॉमरेड मलय घोष पर एक घृणास्पद हमला किया. एमसीसी कार्यकर्ताओं के गिरोह ने उनके हाथों कोपीछे से बांधकर डण्डे और बांस की छड़ियों से बेरहमी से पीटा. तमाम हमलावर बिहार-बंगाल इलाके के विभिन्न प्रांतों से आए थे. ये सभी बेलपहारी से बाहर के लोग ही थे. हमले में कॉमरेड मलय घोष का सिर फट गया. उनकी पिटाई करते हुए ही निंदापूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां भी दी गईं. बिप्लबी कृषक मजदूर समिति (बीकेएमएस) द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने आए किसान तब असमंजस में पड़ गए जब उनसे हमलावर गिरोह के नेता ने यह कहकर हमले को उचित ठहराया कि पीपुल्सवार और एमसीस केन्द्रीय कमेटियों द्वारा एक पार्टी के इलाके में दूसरी पार्टी प्रवेश नहीं करने के किए गए समझौता का उन्होने उल्लंघन किया. उन्हें बोलने का मौका तक नहीं देते हुए उन पर हमला किया गया. बोलने का मौका देने के उनके आग्रह पर शराब के नशे में पूरी तरह धुत्त एमसीसी गिरोह के सदस्यों ने कोई ध्यान नहीं दिया.

इस घटना से काफी अरसे पहले ही वे पीपुल्सवार के खिलाफ उस इलाके में गलत प्रचार करते रहे और पीपुल्सवार पार्टी के नेतृत्व में गोलबन्द हो रहे ग्रामवासियों को बन्दूक दिखाकर धमकियां देते रहे. इस इलाके के पीपुल्सवार पार्टी का पूरी तरह सफाया करने के इरादे से ही वे जनता में आतंक पैदा करते आ रहे हैं. इसके अलावा, मई 1999 में उनके राज्य नेतृत्व ने अपनी बंगाली पत्रिका 'मुक्तिकामी' में कॉमरेड मलय घोष पर किए हमले को बेशर्मी से जायज ठहराते हुए एक मनगढ़ंत कहानी लिख डाली जिसमें पीपुल्सवार पार्टी पर झूठे आरोप लगाए. गत फरवरी महीने में हमारीबंगाल राज्य कमेटी ने एमसीसी को एक खुला पत्र भेजा जिसमें उससे आग्रह किया गया कि राज्य और केन्द्र के स्तरों पर द्विपक्षीय वार्ता चलाकर अपने बीच मौजूद मतभेदों को सुलझा लिया जाए और उसकी पत्रिका में लिखी जा रहे झूठों को तत्काल रोक दे. उस खुले पत्र का एमसीसी ने इस तरह जवाब देना शुरू किया.

एमसीसी इतनी शत्रुतापूर्ण रवैये के साथ पीपुल्सवार पर अपने हमले क्यों जारी रख रही है? भारत को जमींदारों और साम्राज्यवादियों के शिकंजे से और उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए ऊंची कुर्बानियां देने वाली एक पार्टी पर क्यों एमसीसी झूठा प्रचार और हमले कर रही है? बिहार की ही तरह बंगाल में भी अपने हमलों का दायरा बढ़ाते हुए कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता को क्यों तोड़ रही है? बेलपहारी की घटनाक्रम के पीछे वास्तविक कारण क्या रहे?

निष्पक्षता से वस्तुगत हालात की जांच-पड़ताल किए बिना पीपुल्सवार पर एमसीसी के गलत आरोपों का पर्दाफाश कर उसकी असलियत और सच्चाई को उजागर करना संभव नहीं है.

तथ्य क्या है?

यह बात सच है कि शुरू से ही बेलपहारी इलाके में पीपुल्सवार के क्रियाकलापों को रोकने के लिए एमसीसी गंभीर कोशिशें कर रही है. 1998 में ही एमसीसी के कार्यकर्ताओं ने पीपुल्सवार के एक कार्यकर्ता पर हमला करके उन्हें प्रताड़ित किया. इस घटना के बाद एमसीसी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में पीपुल्सवार के प्रतिनिधिमण्डल ने इस मामले पर भी एमसीसी की केन्द्रीय कमेटी का ध्यान खींचा. तुरन्त एमसीसी ने मान लिया कि यह भूल उनकी अनजाने में ही हुई और उनकी ओर से हुई गलती थी. उसने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देने की हामी भरी. उसके बाद भी बेलपहारी इलाके के गांवों में राजनीतिक प्रचार के लिए गए छात्र-नौजवानों के दलों को एमसीसी के काडरों ने प्रताड़ित किया. पहले की पीपुल्सवार की केन्द्रीय कमेटी ने एमसीसी को यह सूचना दी कि चूंकि बेलपहारी इलाका बिहार और बंगाल को जोड़ने वाला इलाका है, इसलिए हमें उस इलाके में काम करने की जरूरत है और काम करने का फैसला लिया, साथ ही साथ इसका गलत अर्थ न निकाला जाए. अगस्त 1997 में एमसीसी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता पहले की पीपुल्सवार के नेतृत्व ने एमसीसी को स्पष्ट कर दिया कि कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच किसी तरह का इलाका-बंटवारा जरूरी नहीं है; किसी भी इलाके में किसी भी क्रांतिकारी पार्टी काम कर सकती है; मौजूदा चरण में कुछ इलाकों में एक से ज्यादा क्रांतिकारी पार्टियों का काम जारी रहना अनिवार्य हो जाता है; उस तरह के इलाकों में काम करने वाली क्रांतिकारी ताकतों और पार्टियों को चाहिए कि वे मिल-जुलकर काम करते हुए जनता को वर्ग संघर्षों में गोलबन्द करें. यह भी स्पष्ट करके बताया कि इस तरह मिल-जुलकर काम करने से ही दोनों पार्टियों के कैडरों की समझ बढ़ेगी और क्रांतिकारियों के बीच मजबूत एकता की बुनियाद तैयार होगी.

इस तरह की वार्ताओं के तहत ही बेलपहारी में 1998 के दिसम्बर माह में कॉमरेड मलय घोष और एमसीसी के स्थानीय संगठनकर्ता कॉमरेड सुकान्त के बीच बातचीत हुई जिसमें दोनों पार्टियों की प्रस्तावित साझी गतिविधियों के बारे में चर्चा हुई. कॉमरेड सुकान्त को यह भी बताया गया कि दोनों पार्टियों के बीच हुई वार्ताओं में उस इलाके में साझे क्रिया-कलापों और जन-संघर्षों को विकसित करने का फैसला लिया गया. लेकिन उन्होने इन फैसलों पर कभी अमल नहीं किया, साथ ही पीपुल्सवार विरोधी प्रचार तेज कर दिया. सुकान्त को पीपुल्सवार की विरोधिता की घुट्टी पिलाकर जरूर एमसीसी के नेतृत्व ने ही उसे पीपुल्सवार विरोधी प्रचार के लिए उकसाया होगा. पिछले फरवरी माह में ही पीपुल्सवार ने तेन्दुपत्ता मजदूरी दरों को बढ़ाने के लिए प्रचार कार्यक्रम अपनाया. 200 पत्तों वाली पुड़िया का 25 रू. की मांग पर जनता को गोलबन्द करने का फैसला लिया. बन्सपहारी, भूलाबेडा और सिमुलपाल ग्राम पंचायतों में दीवार-लेखन के जरिए तयशुदा मजदूरी के लिए प्रचार करते हुए बैठकें भी की गईं. इन बैठकों में जनता ने बड़े उत्साह से भाग लिया. ग्राम कमेटियों का गठन करने का कार्यक्रम लिया गया ताकि जनता की पहलकदमी के आधार पर तेन्दुपत्ता संघर्ष चलाया जा सके. लगभग 40 गांवों में ऐसी कमेटियों के गठन के बाद बीकेएमएस के नेतृत्व में अलग-अलग इलाकों में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया गया. 27 मार्च को बन्सपहारी और सिमुलपाल नामक दोनों गांवों में एक साथ सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान भी किया गया. चूंकि बन्सपहारी में सम्मेलन होते वक्त ही कॉमरेड मलय घोष पर एमसीसी ने हमला किया जिससे उस सम्मेलन में बाधा पड़ी. इस अधूरे सम्मेलन में ही सिमुलपाल और भूलाबेड़ा

की जनता ने इलाका स्तर की कमेटियों का गठन करके तेन्दुपत्ता संघर्ष को शीघ्र ही तेज करने का फैसला लिया. 3 अप्रैल को भूलबेड़ा में आयोजित सम्मेलन के बाद लगभग 150 किसानों द्वारा किए गए सशस्त्र प्रदर्शन ने उस पूरे इलाके में एक संघर्षमय माहौल पैदा कर दिया.

27 मार्च को कॉमरेड मलय घोष पर हमले के बाद एमसीसी ने एक विशेष दस्ते का गठन किया जिसमें सभी बाहर के ही थे. इस दस्ते ने गांव-गांव घूमते हुए पीपुल्सवार से संबंध नहीं रखने को कहते हुए यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई सम्बन्ध रखता है तो उसे मार दिया जाएगा. चूंकि एमसीसी का यह रिकॉर्ड रहा कि उसने एक गरीब आदिवासी महिला को आदेशों का पालन नहीं करने के कारण गुस्से से बन्दूकों के कुंदों से पीटकर जान से मारा, जनता इस बात से डर गई कि कहीं इस बार भी एमसीसी वही न दोहरा दे.

1990 के दशक की शुरुआत में भूलाबेड़ा इलाके के पुकूरिया गांव में हुई उस घटना ने उस पिछड़े आदिवासी इलाके की जनता का क्रोध बढ़ा दिया था. परिणामस्वरूप सभी आदिवासियों ने एकजुट होकर एमसीसी को उस इलाके से बाहर खदेड़ दिया था. उस घटना के बाद सिमुलपाल इलाके के सुष्नी जोगी गांव में जाने वाले एमसीसी कार्यकर्ताओं को स्थानीय जनता ने पकड़कर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी करवा दिया. एमसीसी से पूरी तरह शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रखने वाले उस इलाके के ग्रामीणों के पास जाएंगे तो एमसीसी का इतिहास पूरा-पूरा बता देंगे. तब से एमसीसी ने उस इलाके में अपने क्रिया-कलापों को बन्द कर दिया. तीन साल पहले ही पीपुल्सवार पार्टी ने उस इलाके में कदम रखा, तो एमसीसी ने भी अपनी ताकतों को फिर से एकजुट करके पीपुल्सवार पार्टी के प्रवेश को रोकते हुए उस इलाके में अपनी पकड़ हासिल करने के एकमात्र इरादे से 'काम' शुरू कर दिया.

कॉमरेड मलय घोष पर हमले के बाद से एमसीसी के कार्यकर्ता 14-15 सदस्यों के दस्तों का गठन करके गांव-गांव घूमते हुए जनता को आतंकित कर रहे हैं. इससे तेन्दुपत्ता संघर्ष आगे नहीं बढ़ सका. आमतौर पर तेन्दुपत्ता संघर्ष करने वाली जनता का पुलिस या ठेकेदारों के भाड़े के गुण्डे दमन करते हैं. लेकिन बीकेएमएस के नेतृत्व में 25 रूपए प्रति बन्डल की मांग की जाने पर एक 'माओवादी' संगठन ही वह काम कर रहा है. आन्दोलन का उसने विघटन करके बन्डल की 20 रू. दर तय की. पहले ही यह फैसला कुछ इलाकों में लागू किया गया. बहरहाल, यह तो कहा जा सकता है कि तेन्दुपत्ता समस्या पर एमसीसी ने जनता को गोलबन्द करने का कोई भी कार्यक्रम नहीं अपनाया. कुछ इलाकों में 20 रू. की दर से भी तेन्दुपत्ता के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ. जनता के हित में एमसीसी ने कुछ तो नहीं किया, पर तेन्दुपत्ता संग्राहक मजदूरों से उसने लेवी वसूलना शुरू कर दिया. पुकूरिया गांव में एमसीसी द्वारा आयोजित मीटिंग में सिर्फ एक ही आदमी ने भाग लिया. वह और कोई नहीं, एक तेन्दुपत्ता ठेकेदार था जिसका नाम था तारपाडा हलदार. उस इलाके की जनता ने इसी के खिलाफ संघर्ष चलाया था. वह एक वर्ग दुश्मन था जिसकी जनता ने खिलाफत की. एमसीसी के समर्थन से इस बार उसने तेन्दुपत्ता मजदूरों से लेवी वसूलने की जिम्मेदारी भी ली. संग्रहित तेन्दुपत्ता को बेचने गए मजदूरों से एमसीसी द्वारा तय रकम मजदूरी से घटाकर भुगतान कर दिया. इस तरह इस बार एमसीसी ने लगभग 4-5 लाख का चन्दा जनता से लूटा. इस पूरे चंदे में आधा हिस्सा हलदार ने ही इकट्ठा करके दिया. आखिरकार तेन्दुपत्ता संघर्ष टूट गया. बन्डल का 20 रू. भी नहीं दिया गया, तो तेन्दुपत्ता ठेकेदारों को बेहद मुनाफे मिले. चूंकि इस इलाके से पीपुल्सवार का सफाया करने का लक्ष्य हलदार और एमसीसी दोनों का रहा, उनके बीच अनैतिक सम्बन्ध कायम हो गया. कोई भी उस इलाके में कुछ समय बिताकर किसी से भी तथ्यों का पता लगा सकता है. बेहतर होगा कोई बुद्धिजीवी इस इलाके का दौरा करके तथ्यों का पता लगाएं.

क्यों एमसीसी डर से कांप रही है?

एमसीसी में डर पैदा हो गया. चाहे कितने गलत प्रचार करके भी राजनीतिक तौर पर पीपुल्सवार का मुकाबला करना संभव नहीं हो सका जिससे एमसीसी को डर लगा और उसने पीपुल्सवार की बंगाल राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड मलय घोष पर हमले के रूप में व्यक्त भी किया. इसीलिए उसने बढ़ते क्रांतिकारी पार्टियों के प्रभाव का जब का तब अंदाजा लगाने वाले शासक वर्गों और उसके दलालों सा बरताव किया. उस पूरे इलाके में जनता को और उनके नेताओं को डराना, प्रताड़ित करना, गाली-गलौज करना आदि कार्रवाइयां जारी रखते हुए एमसीसी ने आतंक का माहौल बनाया.

बंगाल इलाके में पीपुल्सवार ने जबसे काम शुरू किया, उसके तुरन्त बाद से एमसीसी ने पीपुल्सवार के खिलाफ सीधे तौर पर प्रचार शुरू कर दिया. विगत में वह पीपुल्सवार के खिलाफ खुलकर प्रचार नहीं करती थी. 'पीपुल्सवार चुनाव में भाग लेने वाली है', 'उसका नेतृत्व कानूनी बनने जा रहा है' आदि कई किस्म के बेबुनियाद आरोपों से एमसीसी ने पीपुल्सवार को बदनाम करने की कोशिश की. द्विपक्षीय वार्ताओं में उसने पीपुल्सवार पर अपनी इन शंकाओं का जिक्र कभी नहीं किया. अपनी पत्रिकाओं में पीपुल्सवार के साथ उसके सैद्धांतिक मतभेदों पर एक भी लेख नहीं लिखा. अपने काडरों में पीपुल्सवार के प्रति विरोधिता बढ़ाने के लिए ही उन्होंने यह सारी तिकड़मबाजी की. इस तरह विरोधिता से भरे काडरों को ही पीपुल्सवार पर भौतिक हमलों के लिए उकसाया जा रहा है. याद रहे कि 1960 के दशक के आखिर में भाकपा (मा-ले) के गठन के बाद माकपा ने भी अपने काडरों में यह झूठा प्रचार करके हमले करवाए कि चारु मजुमदार सीआईए (अमरीकी गुप्तचर संस्था) का दलाल है. बदकिस्मती से अब एमसीसी नेतृत्व भी वही तरीका अपना रहा है.

शुरू में, जब एमसीसी बंगाल के एक छोटे गुट के तौर पर रहा था, उसकी पत्रिका 'दक्षिण देश' में नक्सलबाड़ी के खिलाफ, नक्सलबाड़ी के नेतृत्व के खिलाफ, बाद में गठित भाकपा (मा-ले) के खिलाफ शत्रुतापूर्ण लेख लिखे गए थे. उन्होंने सोनारपुर किसान संघर्ष को नक्सलबाड़ी संघर्ष के वैकल्पिक संघर्ष के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की. भाकपा (मा-ले) के नेतृत्व को अवसरवादी कहते हुए बदनाम करने की कोशिश की. ऐसी घिनौनी कोशिशों की वजह से वे खुद-ब-खुद उपहास का शिकार बनकर पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारियों से अलग-थलग पड़ गए. उस मामले में किसी भी तरह की आत्मालोचना किए बिना ही अचानक वे आज नक्सलबाड़ी की और कॉमरेड चारु मजुमदार की प्रशंसा करने लगे. दूसरी ओर, भाकपा (मा-ले) द्वारा निर्मित सर्वोन्नत परम्पराओं, हासिल लक्ष्यों को और राजनीतिक व संगठनात्मक तौर पर भाकपा (मा-ले) के उत्तराधिकारी के नाते आगे बढ़ने वाली भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. पीपुल्सवार ने पश्चिम बंगाल और बिहार में काम करने का फैसला किया, तो वे डर रहे हैं. पीपुल्सवार और पार्टी यूनिटी के विलय की खबर ने उनका डर ज्यादा बढ़ा दिया. विलय के बाद से 60-70 सदस्यों के सशस्त्र गिरोहों ने सभी इलाकों में घूमते हुए पीपुल्सवार पर व्यापक स्तर के हमलों की शुरुआत की. पीपुल्सवार के नेताओं, कार्यकर्ताओं और हमदर्दों

को आतंकित करते हुए उनके घरों को उड़ाते हुए, ढहाते हुए पीपुल्सवार का उन्मूलन करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं. एमसीसी एक बार यह बात याद करे तो बेहतर होगा कि भारतीय राज्य भी ऐसी दमनात्मक नीतियों पर अमल करके भी पीपुल्सवार का सफाया नहीं कर सका. इन भौतिक हमलों के साथोंसाथ ही पीपुल्सवार पर झूठा प्रचार भी व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है.

दूसरी ओर, केन्द्रीय स्तर पर प्रस्तावित वार्ताओं को हर बार टालते हुए एमसीसी इस बात को ठुकरा रही है कि पहले बिहार की समस्या का हल किया जाए. आखिर में बिहार की तरह के हमले बंगाल में भी पीपुल्सवार के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर करने का फैसला लिया.

एमसीसी के पतन का क्रम

एमसीसी के इस रुख से ही कि कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच इलाका-बंटवारा होना चाहिए, यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह पतन की अवस्था में पहुंच चुकी है. उसने पहले यह प्रस्ताव रखा कि पीपुल्सवार दक्षिण भारत में ही काम करते हुए उत्तर भारत को एमसीसी के हक में छोड़ दे. उसने पीपुल्सवार से यह मांग की कि बिहार और बंगाल में काम न करे, मानो वे इलाके उसकी जागीर हों. उसके गलत सिद्धांतों को ठुकराकर पीपुल्सवार ने बिहार और बंगाल में काम करना शुरू किया, तो पीपुल्सवार के प्रति एमसीसी के रवैए में बदलाव आने लगा. एकता वार्ताओं की विफलता के बाद वे पीपुल्सवार पर हमले चोरी-छिपे और बाद में खुलकर ही गलत प्रचार करने लग गए. बाद में बिहार में हमले तेज करके अन्ततः पश्चिम बंगाल तक एमसीसी ने हमलों का विस्तार किया.

एमसीसी हताशा और बेचैनी का शिकार होकर ही बंगाल में पीपुल्सवार के राज्य कमेटी सदस्य पर भौतिक हमला करने पर तुल गई. 1980 के दशक से ही उसके बेलपहारी इलाके में काम करने के बावजूद, यह बात सच है कि जनता में भाकपा (मा-ले) ने जो असर डाला उसे एमसीसी ने कुछ भी कम नहीं किया. बंगाल-बिहार-उड़ीसा रीजिनल कमेटी के नेतृत्व में 1969-70 में इस इलाके में आग की तरह फैलने वाला क्रांतिकारी किसानी आंदोलन और सर्वोच्च कुरबानियों ने आज तक जनता के दिल में अमिट छाप छोड़ रखी है. अपने खून से उस इलाके में क्रांतिकारी राजनीति के बीज बो चुकी भाकपा (मा-ले) का ही उस इलाके की अधिकांश जनता आदर करती है. इसलिए, जैसे ही वहां भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) ने अपना काम शुरू किया, पीपुल्सवार के नेतृत्व में जनता का दोबारा संगठित हो जाना शुरू हो गया.

एमसीसी का नेतृत्व डर से कांपते हुए जो हमले कर रहा है उसके वास्तविक कारण यही हैं. आज तक एमसीसी का काम यही रहा कि तेन्दुपत्ता सीजन में बेलपहारी को अपना केन्द्र बनाकर आसपास के इलाकों में अपने दस्ते भेजते हुए ठेकेदारों से लाखों रूपए का चंदा वसूलना. एमसीसी को अब डर यह हो गया कि तेन्दुपत्ता चन्दे बन्द हो जाएंगे. अब उस इलाके में पीपुल्सवार काम करते हुए आन्दोलनों का निर्माण करेगी, तो ठेकेदार एमसीसी को पैसा क्यों देंगे? हलदार जैसे ठेकेदार उस इलाके में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ही एमसीसी का सहयोग कर रहे हैं. लेवी वसूल करने के लिए और अपनी अघोषित 'जमींदारी' पर हक बनाए रखने के लिए ही एमसीसी को पीपुल्सवार पर हमले करना आवश्यक हो गया. पश्चिम बंगाल में माकपा भी इसी तरह के हितों के मद्देनजर देहाती इलाकों और शहरों में भी क्रांतिकारी हमले कर रही है. जनता को आतंकित कर रही है.

एमसीसी भी इसी ढंग से हमले करते हुए क्रांतिकारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. 27 मार्च को एमसीसी के हमलावरों द्वारा किया गया हमला भी ठीक शराब के नशे में धुत्त माकपा के गुण्डों के हमलों से मेल खाता है. ऐसा परिणाम पीड़ादायक होने के बावजूद, सहज ही सभी के मन में एक सवाल पैदा कर देता है. वह यह कि क्या एमसीसी भी माकपा के ही रास्ते पर चल रही है? ✪

(....अन्तिम पृष्ठ का शेष)

अन्य पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए.

उत्तर तेलंगाना के धधकते खेत-खलिहानों से दक्षिण तेलंगाना तक और नल्लमला के पहाड़ों तक; रायलसीमा से तटीय आन्ध्र होते हुए पूर्वी इलाके तक जनता के क्रोध के शोले पूरे एक महीने तक उनके प्यारे नेताओं की हत्याओं की जांच पुरजोर मांग करते हुए भड़कते ही रहे.

16 दिसम्बर को, हमारे दण्डकारण्य में सशस्त्र छापामारों ने बालाघाट जिले के सोनपुरी गांव में मध्यप्रदेश के परिवहन मन्त्री लिखीराम कावरे के घर पर धावा बोला और उसका सफाया कर दिया.

इसी दिन उत्तर भारत के बिहार राज्य में पीपुल्सवार के छापामर दस्तों ने जहानाबाद के निकट तरेगना में रेल लाइन को बारूद के विस्फोट से उड़ा दिया जिससे पटना-गया लाइन में गाड़ियों की आवाजाही बन्द हो गई. 18 दिसम्बर को पलामू जिले में एक रेल लाइन को उड़ा दिया गया. उसी दिन कजरा-नवाडीह रेलवे स्टेशन को भी उड़ा दिया गया जिससे रेल सेवाओं में करीब दस घण्टे तक बाधा पड़ी. जवाबी कार्रवाइयों का यह सिलसिला अभी भी जारी है.

जनता के क्रोध के इस ज्वार और हथियारबन्द छापामारों की जवाबी कार्रवाइयों से लुटेरे शासक वर्गों के प्रतिनिधि इतना भयभीत हो गए कि सभी राजनेताओं, अफसरों और अन्य प्रतिनिधियों ने उत्तर तेलंगाना सहित आन्ध्र के सभी तेज वर्ग-संघर्ष वाले इलाकों के गांवों और कस्बों से भागकर हैदराबाद में सुरक्षित पनाह ली. सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम के एक भी राजनेता ने, यहां तक कि सरपंचों ने भी जिले में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, और यहां तक कि राजधानी हैदराबाद में पुलिस सुरक्षा की अपील की. बदला लिए जाने के डर से आन्ध्र में करीब 700 अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा दी गई. कुल मिलाकर, तीन कॉमरेडों की शहादत के बाद एक महीने में करीब 150 बड़ी जवाबी कार्रवाइयां की गईं.

जन-प्रदर्शनों, रैलियों और विरोध के अन्य तरीकों तथा क्रान्तिकारी ताकतों की ओर से अपने प्यारे नेताओं की शहादत का बदला लेने के दृढ़ इरादे ने शासक वर्गों में दहशत फैला दी. देश में जारी जनयुद्ध को कुचलने और जन आन्दोलनों को दबाने के उनकी सुनहरे सपने वास्तव में दुःस्वप्न साबित हो गए. मरने वाले जिन्दा लौट गए. जनता के व्यापक विरोध ने सबित कर दिया कि कॉमरेड श्याम, महेश और मुरली ने, जिन्हें शासक वर्गों ने अत्यन्त बर्बरतापूर्ण तरीके से कत्ल किया, शोषक वर्गों का सफाया करने के लिए जन-समुदायों को अप्रतिरोध्य ताकत से आगे बढ़ाते हुए उनके बीच फिर से जन्म लिया. इन कॉमरेडों द्वारा प्रदर्शित आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए, क्रान्तिकारी जन-समुदाय भारत की धरती से सामंतवाद, साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाही पूंजीवाद को जड़ों से उखाड़ फेंकने के अपने ऐतिहासिक लक्ष्य को ज्यादा दृढ़ता से आगे बढ़ाने वाले हैं. ❖

शिक्षा गारन्टी या बेगारन्टी शिक्षा?

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री योजनाओं की घोषणा करने में माहिर हैं. आज देश में योजनाओं की घोषणाओं के विज्ञापनों का अंबार लगाने वाले मुख्यमंत्रियों में आन्ध्रप्रदेश के नारा चन्द्रबाबू नायडू के बाद दिग्विजय सिंह का नाम भी लिया जाएगा. वे घोषित योजनाओं के नतीजों पर बिलकुल ध्यान नहीं देते. जनता को बड़े वरदान देने की तर्ज पर जोर-शोर से आए दिन नई-नई योजनाओं की घोषणा करते हैं. अब से 40 महीने पहले अपने पद के पहले दौर में दिग्विजय सिंह ने 'महिला नीति' के नाम पर एक कार्यक्रम अपनाया. इसके तहत यह गंभीर घोषणा की गई है कि जिस इलाके की 50 प्रतिशत महिलाएं लिखित आवेदन-पत्र में अपने इलाके की शराब दुकानों को बन्द करने की मांग करती हैं, वहां उस पर तत्काल ही अमल किया जाएगा. लेकिन अब तक महिलाओं के सैकड़ों आवेदन-पत्र कचरे के टोकरे में डाल दिए गए, पर शराब दुकानों को बन्द नहीं किया गया. अधिकारियों ने तो यह कहते हुए अपनी मन की बात बताई कि जरूरी हो तो दुकानों को बदल दिया जाएगा, लेकिन राज्य के आय के असली स्रोतों को नहीं छोड़ दिया जाएगा. पहले ही छह साल के अपने शासन में घोषित कई योजनाओं पर अमल नहीं करते हुए ठण्डे बस्ते में डालकर रखा गया. 1 जनवरी 1997 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान् दिग्विजय सिंह ने 'शिक्षा गारन्टी योजना' के नाम से एक नई योजना जाहिर की. इस योजना का विवरण देते हुए जनता को आवश्यक शिक्षा दिलाना ही योजना का लक्ष्य बताया. (पाठक इस बात पर ध्यान दें कि निहायत गरीबी झेलने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश का नाम ऊपर है. और विश्व बैंक के ऋणों के लिए झोली फैलाकर चक्कर लगा रहा है).

प्राथमिक शिक्षा के नाम पर शुरू की गई इन नई शिक्षा गारन्टी योजना को ग्राम पंचायतों के सरंपचों के जिम्मे छोड़ दिया गया (इसमें ग्रामसभाओं की क्या भूमिका होगी, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया). इसके मुताबिक जहां से एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था (स्कूल) न हो, उस गांव के लोग सरकार से मांग करते हैं, तो 90 दिनों के अन्दर वहां स्कूल खोली जाएगी. 6 से 11 वर्ष की उम्र के 25 से 40 बच्चों का वहां होना जरूरी है. यह है सरकार द्वारा दी जा रही गारन्टी. भारत के सबसे विशालतम राज्य मध्यप्रदेश (पूर्व से पश्चिम तक 1127 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 996 किलोमीटर) का आबादी का घनत्व 149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. आबादी की दृष्टि से छठे स्थान पर खड़े मध्यप्रदेश के 61 जिलों में मौजूद कुल 75,000 गांवों में से 16,479 शालाएं इस शिक्षा गारंटी योजना के तहत चलाई जा रही हैं, यह बात सरकारी आंकड़ों में दर्ज है (आखिर सरकारी अमला और मीडिया का काम ही यह है न). यह भी कहा गया कि एक स्कूल पर सालाना 8500 रू. आवंटित हैं और सरपंचों के अलावा 'स्वयंसेवी संगठन' भी इस वृहत् कार्यक्रम में शामिल हैं.

और इन स्कूलों में काम करने के लिए गुरुजी के वांछित योग्यताएं ये बताई गईं- वह गुरुजी उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो जहां पर स्कूल खोली जाती है. इसका मतलब बाहरी लोगों की नियुक्ति नहीं होगी; कम से कम वह मैट्रिक पास हो. गुरुजी के लिए यदि महिला उम्मीदवार हों तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसी योग्यताएं प्राप्त उम्मीदवारों को तत्काल ही मात्र 18 दिनों का प्रशिक्षण देकर, 500 रू. महिने के हिसाब से वेतन दिया जाएगा. (दूर-दराज के जंगली इलाकों में ग्राम पंचायत के दायरे में कितने लोगों की ये योग्यताएं होगी सरकार ही जाने. मध्यप्रदेश में साक्षरता दर 45 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है. महिलाओं में यह और भी कम है .)

सरकार द्वारा एक स्कूल पर वार्षिक बजट में आवंटित खर्चों का ब्यौरा यह है-

वार्षिक आवंटन 8500 रू.

1. गुरुजी का मानदेय 500 रू. प्रतिमाह के हिसाब से 6000 रू.
2. प्रशिक्षण (18 दिवसीय) 610 रू.
3. स्कूल का नैमित्तिक व्यय 850 रू.
4. पुस्तकें (25 रू. प्रति छात्र - 40 छात्रों के लिए अनुमानित) 1000 रू.
5. प्रशासनिक नैमित्तिक व्यय (बैठकों के लिए) 40 रू.

नैमित्तिक व्यय में आवंटित 850 रू. को इस तरह खर्च करेंगे-

ब्लेक बोर्ड	400 रू.
स्लेट	200 रू.
चॉक	100 रू.
पेन्सिल	50 रू.
रजिस्टर	50 रू.

पैसों का आवंटन आदि पर सरकार की घोषणाएं तो होती हैं. पर सवाल यह है कि वास्तव में कितनी ईमानदारी से पैसे देंगे. स्वीकृत पैसों का कितनी ईमानदारी से खर्च करेंगे और योजना को कैसे लागू करेंगे इसका अंदाजा मौजूदा नफाखोरी शोषक व्यवस्था के मद्देनजर आसानी से लगाया जासकता है. साल में ये स्कूलें 210 दिन चलना प्रस्तावित हैं. त्यौहार और अन्य आवश्यक छुट्टियों की घोषणा करनी है तो ग्राम का सरपंच ही फैसला करेगा. साथ ही, इस योजना के तहत सरपंच को क्या-क्या अधिकार दिए जाएंगे, इसकी भी सूची दी गई.

- ◇ शिक्षण सामग्री
- ◇ गुरुजी की उपस्थिति
- ◇ गुरुजी का प्रशिक्षण
- ◇ गुरुजी का मानदेय
- ◇ छात्रों का नामांकन एवं उपस्थिति
- ◇ छात्रों का शैक्षणिक स्तर इत्यादि .

ग्राम स्तर से अपने अधिकार को मजबूत बनाने के लिए पहले ही ग्राम पंचायतों के अधिकारों को व्यापक बनाने की घोषणा करने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने (इस मामले में दिग्गी राजा ने पूरे देश में वाहवाही लूटी) उनके मद में बेहिसाब जन धन आवंटित करके व्यवहार में भ्रष्टाचार के द्वार खोल डाले. इन पैसों के समुचित व्यय पर पड़ताल करने का रत्ती भर अधिकार जनता को नहीं दिया गया. पहले ही सरकार द्वारा शुरू की गई 'रोजगार गारन्टी योजना' के तहत 7880 स्कूलें चलने की बात कही जा रही है. देश के अत्यधिक आबादी वाले मध्यप्रदेश राज्य के कुल 6 लाख स्कूली बच्चों में 4,11,000 बच्चे, यानी 70 प्रतिशत बच्चे आदिवासी और दलित बच्चे

ही हैं. सरकार ने खुद को आदिवासी और दलितों का हितैषी होने का दावा किया जो कि मात्र छलावा है. लेकिन बस्तर की आज की तस्वीर स्पष्ट कर देती है कि ये सारी बयानबाजी महज कागजों तक सीमित है.

"हमारे गुरूजियों को हमारे गांव भेज दो"

मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा गारन्टी योजना की घोषणा हुए दो साल होने जा रहे हैं. 1997 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर घोषित यह योजना चुनाव की नौटंकी के बाद दिग्गी महाराज के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही फीकी पड़ गई. दरअसल, दण्डकारण्य के दक्षिण बस्तर डिवीजन स्थित भैरमगढ़, बीजापुर और गंगलूर रेंजों को ही ले लें, तो यहां स्थित 150 गांवों में इने-गिने पुराने स्कूलें ही हैं.

पूरे बस्तर जिले में कुल 3000 गांवों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक स्कूलें 3498 हैं, इनमें 60 प्रतिशत शालाएं और उनमें 60 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शालाएं हैं. महाविद्यालयों की संख्या मात्र 10 है. मौजूद प्राथमिक पाठशालाओं में भी अधिकांश जनसंख्या के ज्यादा घनत्व वाले शहरों में ही केन्द्रित हैं. दूरस्थ जंगली गांवों के बच्चों के लिए तो एकलव्य ही आदर्श गुरूजी होंगे! उपरोक्त तीनों रेंजों में पुरानी स्कूलों में गुरुजी नहीं आ रहे हैं और न ही पढ़ा रहे हैं, ऐसी शिकायतें ग्रामवासी खुद ही कई बार उच्च अधिकारियों से कर रहे हैं. भारी बरसात के बीच किसानों ने हल चलाने का काम छोड़कर अपने बच्चों को लेकर उफनती नदी-नालों को पार करके रेंज मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों में रैलियां निकालीं. इन रैलियों में 'गुरुजी हमें पढ़ाओ', 'गुरुजी स्कूल में उपस्थित रहें', 'बुनियादी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराओ' आदि नारे लगाए गए. और रैलियों में बच्चे अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए थे. बीजापुर, भैरमगढ़, बासागूड़ा, जेगुरुगोण्डा, सेन्ड्रा, आवपल्लि, चिन्तलनार और पामेड में बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ मिलकर रैलियां निकालीं. 4 अगस्त, 1999 को 40 गांवों से 3000 स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने भैरमगढ़ में आयोजित रैली में भाग लिया. आवपल्लि में आयोजित रैली में 8000 लोगों और बीजापुर में 3000 लोगों से विशाल रैलियां निकाली गईं. 17 जुलाई को 6 से 11 साल की उम्र के 3000 बच्चों ने चिन्तलनार में रैली निकाली. जेगुरगोण्डा में 300 बच्चों सहित सैकड़ों गांव वालों ने अपने गांवों के सरपंचों को आगे रखकर रैली निकाली. पामेड में रैली निकालने के लिए 200 बच्चों को लेकर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए, पर पामेड के पास नदी उफान पर थी, इसलिए उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ा. सेन्ड्रा में 25 अगस्त को पालक कमेटी के नेतृत्व में बच्चों और पालकों ने रैली निकाली. कुछ रैलियों के दौरान पुलिस ने रैलियों को रोकने का प्रयास किया, लाठियों और बंदूकों से शक्ति प्रदर्शन किया. पुलिस ने यह धमकी देकर लोगों को तितर-बितर कर डाला कि 'गुरूजी का मामला हम देखेंगे-आइंदा ऐसा कोई जुलूस नहीं निकाले' .पहले की स्कूलों का ही यह हाल रहा, तो मुख्यमंत्री की शिक्षा गारन्टी योजना की बकवास पर यहां तक कि सरपंचों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया. जंगली गांवों के सरपंचों को भी सरकार के तौर-तरीके समझ में आ रहे हैं. कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री की योजना के मुताबिक स्कूल खोले जाने के बावजूद गुरुजी महीने भर के बाद गायब हो जाता है. यह है मुख्यमंत्री महोदय की निष्फल योजनाओं का हंगामा!

स्कूली शिक्षकों की मुसीबतें

मुख्यमंत्री द्वारा घोषित शिक्षा गारन्टी योजना के तहत कहीं भी अगर स्कूल खोली जाती है, तो वहां के शिक्षकों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सरकार बुरी तरह विफल हो रही है. जंगली इलाके में एक ग्राम पंचायत के तहत कुछ जगहों पर 15-20 गांव-पारा होते हैं. आश्चर्य की बात नहीं कि इनका दायरा 15-20 किलोमीटर का होता है. ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को उस गांव में रहते हुए स्कूल चलाना है, तो उसे पहले रहने का बन्दोबस्त किया जाना चाहिए. दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार, दुकान, डाकघर, अस्पताल आदि न्यूनतम सुविधाएं उस गांव में होना जरूरी है. इन सभी से वंचित होकर सदियों से, और 'स्वतंत्र' भारत में 52 वर्षों से आदिवासी जनता रोज की आफतों से जिस तरह जूझने को मजबूर है, सरकार शिक्षक को भी उसी स्थिति में जीने को मजबूर बनाना चाहती है. सरकार के मात्र 500 रू. प्रतिमाह मानदेय से इन सारी मुसीबतों को झेलना और अपना परिवार चलाना गुरुजी के लिए एक टेढ़ी खीर है . मिली नौकरी को छोड़ने से कोई दूसरी नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. ऐसे में किसी तरह इसी नौकरी में लगे रहने से भी महीनों तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है. इस मौके पर ऊसूर विकासखण्ड के शिक्षाकर्मी संघ के कोषाध्यक्ष देवेन्द्र झाडी ने अखबार वालों को अपनी मुसीबतों का जो बयान दिया, उसका जिक्र करना मुनासिब होगा. ''साल भर पहले सरकार ने सहमति दी कि नियम के मुताबिक लगातार तीन साल सेवा करने वाले शिक्षकों को पर्मानेन्ट किया जाएगा और उन्हें वेतन के साथों-साथ सेवा सुविधा भत्ता, छुट्टियां आदि सभी लागू की जाएंगी. (वह चुनाव का मौका था) लेकिन पांच साल बीतने के बाद भी उनका कोई ठिकाना नहीं है. शिक्षाकर्मियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है .'' उन्होंने आगे कहा, ''शिक्षक नौकरी को बेरोजगार का उन्मूलन करने का साधन बताया जाता है. पर बस्तर में, विशेषकर दक्षिण बस्तर में नौकरी के अलावा, ठेकेदारी करे या सेलून खोले बगैर उपवास रहना पड़ सकता है.'' उनका कहना है कि शिक्षाकर्मी की जिन्दगी दिहाड़ी मजदूरों और सरकारी चपरासियों से भी बदतर है. वे कहते हैं, ''दोपहर का भोजन होने के बाद बर्तन और बच्चों की जूठी थालियों को भी हमें मांजना पड़ता है.''

दूसरी ओर, शिक्षकों को सरकार द्वारा सौंपे जा रहे मुफ्त के कामों की फेहरिस्त बढ़ती ही रहती है. जन्म और मृत्यु की गणना, मतदाता सूची तैयार करना, विकलांगों और बूढ़ों की गणना, विधवाओं की गणना आदि सभी सर्वेक्षणों का जिम्मा सरकार आसानी से शिक्षकों पर मढ़ती है. यहां पहले ही शिक्षा का ही खस्ता हाल है, तो शिक्षकों को ऐसे काम सौंपकर सरकारी अधिकारी निश्चित रूप से छात्रों की पढ़ाई पर चोट कर रहे हैं.

पुलिस अधिकारी भी कुछ जगहों पर शिक्षकों और ग्रामवासियों के बीच अच्छे सम्बन्धों का नाजायज फायदा उठाते हुए संघर्षशील संगठनों की जानकारी और क्रान्तिकारियों के आने-जाने की सूचनाएँ जुटाने का काम भी सौंप रहे हैं. जहां ऐसा सम्भव न हो और गुरूजी प्रतिरोध करते हों, सरकार स्वयं गुरुजियों की नियुक्ति करके कई किस्म के सर्वेक्षणों की आड़ में दूरस्थ जंगलों का सर्वेक्षण करवा रही है. इस तरह समाज में गुरुजी को प्राप्त सम्मान को विकृत बनाते हुए खुफिया का काम करने वाले शिक्षक भी दण्डकारण्य में कहीं-कहीं दिखाई पड़ते हैं.

ऐसे दूभर हालात को झेलते हुए शिक्षक की नौकरी करने कौन आगे आएगा? इसके अलावा शिक्षकों पर बढ़ते शिक्षण के बोझ से राज्य की अन्य जगहों पर भी शिक्षकों में बेहद असन्तोष व्याप्त है. धमतरी जिले के डाहि, अंगारा, बोधली जैसे बड़े गांवों में 240-250 छात्र-छात्राओं को एक साथ बिठाकर स्कूल के पत्र-व्यवहार जैसे कामों को संभालते हुए एक ही गुरुजी पढ़ा नहीं सक रहा है. वहां के शिक्षक अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहते हैं कि असल में सरकारी नियमों के मुताबिक ही एक शिक्षक के बदले 45 छात्रों से अधिक नहीं होने चाहिए. कुछ अधिकारी अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि ग्रामवासी स्वयं ही पैसा जुगाड़ करके अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है. वास्तविक स्थिति यह है कि सरकारी प्रचार अमला तो यह ढिंढोरा पीटता है कि इन दो सालों में 1,47 9 शिक्षा गारन्टी की स्कूलें खोली गईं. लेकिन दिग्गी का दावा था कि 40 हजार स्कूलें खोली जाएंगी.

दिग्गी राजा की नई घोषणा

दो साल बीतने के बावजूद शिक्षा गारन्टी योजना सफल नहीं हुई, तो मुख्यमंत्री ने 13वीं लोकसभा के चुनावों का मौका देखकर 'गुरु पूर्णिमा' के शुभ मुहूरत पर एक नई योजना का जाल फेंका. 100 प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में अनिवार्य दाखिला देने, खासतौर पर लड़कियों को पढ़ाने के संकल्प से ग्राम पंचायत अमले का कमर कसने का आह्वान किया गया. 1 से 15 अगस्त तक (जहां शासकों के लिए 53वें स्वतंत्रता दिवस की जश्न मनाने का अवसर है, वहीं बदकिस्मती से स्कूली बच्चों के लिए झण्डा त्यौहार के रूप में नाम हो चुका है.) 15 दिनों का अभियान चलाने का मुहूरत भी तय किया गया. लेकिन, दरअसल मध्यप्रदेश में स्कूलें 1 जुलाई को खुलती हैं, तो एक माह देरी ऐसी योजना की घोषणा करना दुस्साहस ही नहीं, शर्म की बात है.

यही नहीं, मध्यप्रदेश की विधानसभा ने जुलाई 1999 में मानसून सत्र के दौरान एक और अनोखी योजना तैयार की. इसके मुताबिक वर्ष 2001 तक हर तीन किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक स्कूल खोलना प्रस्तावित है. (स्कूल की बात पर तो कोई भरोसा नहीं, पर तब तक दण्डकारण्य में हर 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस शिविर का खुल जाना निश्चित है) इसके अतर्गत इसी वित्तीय वर्ष में राज्यभर में 3500 माध्यमिक स्कूलें खोलने और इस मद में 13 करोड़ रू. भी आवंटित करने की बात कही गई. इनमें सामान्य माध्यमिक स्कूलें विशेष इलाकों में खोलने की बात कही गई. घोषणा में बताया गया कि शुरू में इन स्कूलों में एक प्रधान अध्यापक के अलावा दो शिक्षक भी होंगे. व्यवहार में चाहे जो हो, पर सुनियोजित ढंग से योजनाएं घोषित करने में सरकारी अमला भी मुख्यमंत्री से भी पीछे नहीं है. लेकिन इस योजना पर लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के मौके पर आदर्श आचार संहिता के चलते रोक लगने से गुस्सा भी प्रदर्शित किया. राजनेताओं के नाटकों सेअनजान मासूम शिक्षक तो अपनी किस्मत आजमाते हुए नई नौकरियों की आस लगाए बैठे रहते हैं. वे अपेक्षा कर रहे हैं कि 1894 शिक्षकों को पदान्नति मिलेगी, 1447 सहायक शिक्षक और 4997 शिक्षाकर्मी शिक्षक बन जाएँगे. लेकिन इस बाबत अब तक किसी भी तरह के आधिकारिक आदेश नहीं मिलने की भी चर्चा है.

मध्याह्न भोजन अधिकारी ही खा जाते हैं

छात्रों को दिया जाने वाला दोपहर का भोजन वाली योजना पर बस्तर में सुचारु ढंग से अमल नहीं हो रहा है. दूर-दराज के जँगली इलाकों में समय पर सामग्री भेजने में सरकार बुरी तरह विफल है. सरकारी आश्रमस्कूलों को प्राप्त खाद्य सामग्री सड़ी-गली, कीड़ेयुक्त और घटिया किस्म की होती है. ऐसे चावल और दाल खाकर बच्चों को दस्त, पेट दर्द, उलटी आदि बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को सरकार द्वारा मिल रही बेहद घटिया खाद्य सामग्री और कुपोषण के कारण छात्र कई दिक्कतें झेल रहे हैं. बच्चों को मिल रहे आहार में भी मिलावट करके, बच्चों के नाम पर आने वाले पैसे अपनी झोली में भरके, बच्चों को न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित रखकर भ्रष्ट अधिकारी उनके पेट पर लात मार रहे हैं- हजारों रूपए डकार रहे हैं. हाल ही में प्रकाश में आने वाले अन्तागढ़ विकासखण्ड के ऊसेली आश्रमशाला के भ्रष्टाचार काण्ड पर नज़र डालेंगे, तो बस्तर के आदिवासी बच्चों पर सरकार का 'लाड़-प्यार' समझा जा सकता है.

यहां की आश्रमशाला 24 फरवरी, 1997 को खोली गई . 30 अप्रैल 1998 तक इसमें 50 छात्रों की भर्ती दर्शाकर आश्रम अधिकारियों ने उनके नाम पर बैंक से 52,800 रू. निकाले. लेकिन, वास्तव में उसमें सिर्फ 21 बच्चों ने ही दाखिला लिया. बाकी छात्रों के नाम अधिकारियों के कमाल का ही नतीजा है. उनके नाम से निकले 30,624 रूपए उन्हीं अधिकारियों ने आपस में बांट ली. जब नन्हें बच्चे ये शिकायत करते कि अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सामग्री से उनका पेट नहीं भर रहा है, तो अधिकारी यह कहकर डांटते कि 'पैसे कम होने से उपवास भी रहना पड़ता है.' इसके अलावा आश्रम में मौजूद 21 बच्चों को मात्र 12 गद्दे और चादरें दी गईं. बाकी के बारे में पूछने पर मुंह फेर लिए. आश्रम में खाना पकाने के लिए भी नन्हें बच्चों को ही जंगल से लकड़ी बीनकर लाना पड़ता है. इतने काले कारनामों और भ्रष्ट आचरण को लोगों ने जब सुना, तो अवाक रह गए.

दरअसल स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना में हमारे शासक वर्गों की महानता कुछ भी नहीं है. अमरीका में गोदामों में सड़ रहे खाद्य अनाजों को अमरीकी कानून पीएल-484 (1954) के मुताबिक अमरीका हजारों स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से पिछड़े देशों में वितरित करती है. केर (को-ऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एविरीवेर), वर्ल्डविज़न, चर्च वर्ल्ड सर्विसेस जैसे संगठनों के माध्यम से इन देशों पर अपना शिकंजा कसते हुए सरकारी अस्पतालों और स्कूली बच्चों को इसी तरह का दान-धर्म करता है. केर और वर्ल्डविज़न का वार्षिक बजट 1993 तक ही 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गया जिससे इसका अंदाजा लगाया जासकता है ये स्वयंसेवी संगठन पिछड़े देशों की सरकारों को किस तरह नचा सकते हैं. यहां गौरतलबबात यह है कि हमारे शासक वर्ग इतनी बदहालत में हैं कि ऐसे सुधारों के लिए भी साम्राज्यवादियों पर ही निर्भर रहने को मजबूर हैं. इस तरह आयातित सामानों में भ्रष्ट अधिकारियों के घोटालों का कोई हिसाब ही नहीं है.

उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा नीति की बदहाली और सरकारी योजनाओं के खोखलापन को छोड़कर यह देखेंगे कि असल में भारत में प्राथमिक शिक्षा के तौर-तरीके कैसे हैं. यूनिसेफ द्वारा 'विश्व के बच्चों की हालत-1999' के नाम से जारी वास्तविक पत्र में भारत में प्राथमिक शिक्षा की हालत पर यह टिप्पणी की गई.

''6 से 11 वर्ष की उम्र के भारत के 50 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं. भारत के कुल निरक्षरों में दो-तिहाई महिलाएं ही हैं. दुनिया के हर तीन अनपढ़ लोगों में एक भारतीय है. आगामी कुछ महीनों में भारत सबसे ज्यादा अनपढ़ों का देश बनने जा रहा है, यह विज़न 2000 की है. (हमारे नेताओं के हंगामे के पीछे शायद ये रिकॉर्ड भी काम कर रहे होंगे) स्कूलों में पढ़ने वाले 50 प्रतिशत बच्चे 5वीं कक्षा से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं . 5वीं पास बच्चों में 50 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर का किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है'', ये तथ्य वास्तविक पत्र में दिए गए. दरअसल यूनिसेफ के हिसाब में नहीं आने वालों की संख्या भी कम नहीं होगी. वास्तविक पत्र में प्राथमिक शिक्षा पर सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च का जिक्र भी किया गया. 5वीं वार्षिक योजना से 9वीं पंचवर्षीय योजना तक शिक्षा पर किए जा रहे पूरे खर्च में प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा 58 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक घट चुका है. देश की दो-तिहाई आबादी ग्रामीण अंचल में रहने के बावजूद,कठोर सच्चाई यह है कि शिक्षा के पूरे खर्च में अधिकांश हिस्सा शहरी इलाकों में ही किया जा रहा है. 1970 में ग्रामीण शिक्षा पर 490 करोड़ खर्च किया गया, जबकि शहरी शिक्षा पर 620 करोड़ खर्च किया गया.

देश में 50 प्रतिशत साक्षर होने का दावा करने के बावजूद, वास्तव में 70 प्रतिशत लोगों को पढ़ना-लिखना नहीं आता! सरकार बयानबाजी और योजनाओं का उद्घाटन करने से ही संतुष्ट है, पर स्कूली शिक्षा पर किसी वास्तविक प्रयास नहीं करती है. शिक्षा के विकास के लिए व्यावहारिक प्रयास करने के बजाय आंकड़ों की जादूगरी से लोगों को गुमराह करना सरकारों की आदत-सी बनी है. 1981 तक देश की जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत बताया जाता था, पर साक्षरता के मापदण्ड बेहद कम कर देने से जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते वे भी साक्षरों के खाते में शामिल हो गए! 1991 में अचानक यूं दिखाई दिया कि देश में साक्षरता दर तेजी से बढ़कर 52 प्रतिशत तक पहुंच गई है. देश में 5-14 वर्ष उम्र के कम से कम 10 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं. बड़ों की बात छोड़ भी दें, तो इतने करोड़ 'भारत के भावी नागरिकों' को पढ़ाने में सरकार कितनी लापरवाही बरत रही है,यह बात आसानी से समझी जा सकती है. इन सभी बच्चों को साक्षर बनाना है, तो कम से कम 25 लाख कमरे (सरकार द्वारा तय एक कक्षा में 40 छात्रों के हिसाब से) और उतनी ही संख्या में गुरुजी अतिरिक्त लगेंगे. उसके बाद हर वर्ष सालाना 10 करोड़ रुपए खर्च करने परसभी बच्चों को कम से कम अक्षरों के ज्ञान से लैस करने के लिए आवश्यक सुविधाएं बन सकती हैं. फिलहाल केन्द्र और सभी प्रदेशों की सरकारें शिक्षा की मद में सालाना 4.5 लाख करोड़ रू. खर्च कर रही हैं. यानी प्रतिदिन 1230 करोड़ या हर घण्टे में 52 करोड़ खर्च. फिर भी यह अपर्याप्त है. देश के सभी बच्चों को साक्षर बनाना है, तो सालना 10,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा है जो इन 53 वर्षों से सरकारें नहीं कर सकीं. इन दो सालों में तीन बार हुए मध्यावधि चुनावों पर 30,000 करोड़ रू. और कारगिल की लड़ाई में 6 हजार करोड़ से ज्यादा का दुरुपयोग करने वाली सरकार स्कूली शिक्षा पर खर्च करने के नाम पर अंगूठा दिखा देती है.

आज भारत के 9 राज्य-आंध्रप्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा के मामले में बेहद पिछड़े गिने जाते हैं. 5-14 वर्ष उम्र के स्कूल न जाने वाले बच्चों में 80 प्रतिशत इन्हीं राज्यों में हैं. उपरोक्त राज्यों में से आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम है. फिर, बिहार की तो बात ही छोड़िए.

जहां तक स्कूलों के हालात का सवाल है, 4वीं अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण 1978 के मुताबिक 9 प्रतिशत स्कूलों के भवन नहीं है. 41.15 प्रतिशत स्कूलों में ब्लेकबोर्ड का अभाव है. 53.7 प्रतिशत स्कूलों के बच्चे खेल के मैदानों से वंचित हैं. ग्रामीण इलाकों की 89 प्रतिशत स्कूलों में (या 100 प्रतिशत भी हो सकता है) पेशाबघर और लेट्रिन की सुविधा नहीं है. इसके अलावा, कक्षाओं में छात्रों की भीड़, शिक्षकों के समुचित प्रशिक्षण का अभाव, स्कूलों में उनकी अनुपस्थिति, बच्चों से शिक्षकों का कठोर और घिनौना बर्ताव, बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाठ्यांशों का बोझ आदि कई कारणों से बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं.

हमारे मानव संसाधन मन्त्रालय को अप्रैल 199 में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार करने में शर्म नहीं महसूस हुई कि 5वीं कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही 38.23 प्रतिशत लड़के और 41.34 प्रतिशत लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं. 8वीं कक्षा में पहुंचने से पहले ही 54.14 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं जिनमें लड़कों का प्रतिशत 50.72 और लड़कियों का प्रतिशत 58.61 है. इसका मतलब, स्कूल में दाखिला लेने वाले तमाम बच्चों में दो-तिहाई बच्चे पढ़ाई बन्द कर रहे हैं. इनमें लड़के 67.65 प्रतिशत और लड़कियां 72.67 प्रतिशत हैं.

लेकिन, यह रिपोर्ट इस बात का जिक्र करने में स्वाभाविक रूप से विफल हो गई कि भारत में ग्रामीण अंचल में व्याप्त भीषण गरीबी की स्थिति ही बच्चों के स्कूल छोड़ने और स्कूल नहीं जाने का असली कारण है.

इसी मौके पर मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा जारी श्वेतपत्र में दर्शाई गई उसकी आर्थिक हालत को भी जान लेना मुनासिब होगा. दिग्गी राजा का खजाना खाली होने के बावजूद, राज्य को कर्जों में डुबोकर और जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ाकर अपनाई जा रही योजनाओं के अमल को समझा जा सकता है. देश के बेहद गरीब राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के साथ मध्यप्रदेश भी है. फिलहाल भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 5583 रू. है, जबकि बिहार में यह 2904 रू. है और मध्यप्रदेश में 4077 रू. है. भारत से 20 गुना ज्यादा आय वाले अमरीका से तुलना करना तो मुश्किल ही है, लेकिन नेपाल और बांगलादेश की आय से भी इन राज्यों की आय कम है.

ऐसे दूभर हालात वाले मध्यप्रदेश में सरकार की आर्थिक नीतियों से किसानों का जीना और भी मुश्किल हो गया. मजदूरों पर ये नीतियां कुठाराघात कर रही हैं और छात्र-कर्मचारियों को बेहद प्रभावित कर रही हैं .

लगातार तीन सालों से घाटे में चलने के नाम पर मध्यप्रदेश सरकार ने 8 कारखानों को बन्द करने का फैसला लिया. इनमें कार्यरत 5 हजार मजदूरों को दूसरी जगह नौकरी देने के खोखले वायदे भी किए. हालांकि लोगों के विरोध से बचने के लिए वह ऐसा कहती है, लेकिन आखिर में गरीब मजदूरों और किसानों को अंगूठा दिखा देती है. इन कारखानों को बन्द करने के सरकार के फैसले से हजारों मजदूर सड़कों पर आ जाएंगे. चमड़ा विकास संस्था, मत्स्य विकास संस्था, झोपड़पट्टी उन्मूलन संस्था आदि को प्रोत्साहन देने के बजाय, सरकारें नई औद्योगिक नीति पर चलते हुए साम्राज्यवादी संगठनों के आदेशों पर मजदूरों को बेरोजगारी में धकेल रही है. हालांकि 10 कम्पनियों को बन्द करने का फैसला जनवरी 1998 में ही हुआ, लेकिन मजदूर वर्ग के विरोध के चलते, नवम्बर-98 में प्रस्तावित चुनावों के मद्देनजर सरकार ने जल्दी ही उस पर अमल करने का साहस नहीं किया. लेकिन 1999-2000 के बजट के

पहले अमल में लाया.

बजट घाटे के नाम पर सरकार ने मार्च 1999 से बिजली दरों में भी एक साथ 19 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके गरीब और मध्यमवर्गीय जनता पर ज्यादा आर्थिक बोझ लादा. इन बढ़ी हुई दरों से 567 करोड़ रूपए मिलने की बात पर सरकार खुश है.

कई किस्म के करों के नाम पर ढेरों पैसा वसूलने के बावजूद, मध्यप्रदेश की आर्थिक हालत तो भीषण संकट में फंस गई. 1990-91 तक राज्य सरकार पर 4104.20 करोड़ रूपए का कर्ज रहा, जबकि 1997-98 तक तीन गुना बढ़कर 13923 करोड़ हो गया. इन कर्जों पर ब्याज चुकाने के लिए सरकार हर वर्ष 1659करोड़ का नया कर्ज उठा रही है, तो दिग्गी राजा की योजनाओं से जनता की कितनी भलाई होगी, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है. दरअसल, सरकार की आय का 17% भाग ब्याज अदायगी में चले जाना बेहद खराब आर्थिक हालत माना जाता है. कर्जों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा तो वर्ष 2002-03 तक 21% आय ब्याज अदायगी में ही चली जाएगी. ऐसे में राज्य सरकार का दिवाला निकलना निश्चित है. वर्ष 1999-2000 के लिए वित्तमंत्री अजय नारायण मुश्रान ने 22 करोड़ का घाटा दर्शाया. इससे 150 करोड़ की आय के लिए से नए कर भी परोसे. इसके चलते किसानों को मुसीबतें झेलना निश्चित है. विगत में 10 एचपी तक के बिजली पम्पों को वाणिज्य शुल्क से मुक्त रखा गया, अब अजय नारायण और दिग्गी राजा ने मिलकर 3 एचपी तक घटा दिया. इससे 5 करोड़ की आय होने की बात कही जा रही है. और खेत-जमीनों को पानी का कर भी पहले के 24 रु. के मुकाबले अब 81 रु. तक बढ़ा दिया गया. इससे मिलने वाले 5 करोड़ के लालच में किसानों की फसलों से खिलवाड़ किया गया.

सिले-सिलाए कपड़े, खेल की सामग्री, माचिस, अगरबत्ती, खाद्य तेल, चायपत्ती जैसी दैनिक उपयोगी चीजों पर 2% से 4% तक वाणिज्य कर में बढ़ोत्तरी की गई. इससे 30 करोड़ जुटाने की बात कही जा रही है. मिट्टी तेल पर वाणिज्य कर 2% से एकाएक 8% बढ़ाकर 2 करोड़ जुटाने की बात कही गई. गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार ने उनके स्वास्थ्य पर भी कुठाराघात करने का ही निश्चय किया. इससे पहले अस्पतालों को मिलने वाली दवाओं और उपकरणों पर वाणिज्य कर की छूट थी. इस सदी के अंत तक उसे समाप्त कर दिया गया.

रासायनिक उर्वरकों पर 4% वाणिज्य कर लगाया गया. इसके अलावा, सभी किस्म के बीजों पर 4% कर लगाया गया, जिससे 45 करोड़ की आय होगी.

अजीब बात है जो सरकार शिक्षा देने का ढोंग कर रही है, उसी ने स्कूली बच्चों की नोट-बुकों पर 4% वाणिज्य कर बढ़ाकर 6 करोड़ लूट लिया.गरीबों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अल्यूमिनियम के बर्तन पर अब तक कोई वाणिज्य कर नहीं था, अब 4% लगाया गया. तुगलक के करों को भुला देते हुए सभी किस्म के कर जबर्दस्ती वसूले जा रहे हैं. दिग्गी राजा ने छोटे बच्चों के बिस्कुटों और चाकलेटों को भी नहीं बख्शा. उन पर 1.1% कर लगाया गया, जिससे 5 करोड़ की आय तय है. सालाना 50 हजार आय वाले व्यवसायियों से 1000 रुपए का वार्षिक व्यावसायिक कर वसूलने वाली सरकार अब 2400 रु. तक बढ़ाकर समाज के सभी तबकों की जनता की नफरत की शिकार हो गई. इससे 108 करोड़ रु. मिलने की उम्मीद है सरकार को.

देश का लम्बा इतिहास बताता है कि शासक वर्गों के अनगिनत वायदों के बावजूद, खुद बड़े संकटों में फंसे होने के कारण किसी को भी अमलीजामा नहीं पहनाया जाएगा. जुलाई में प्रदेश का वार्षिक बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने विधानसभा में बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बदहाली विश्व और देश के आर्थिक संकट का प्रतिबिम्ब ही है. आज तक भी भारत में जनता की एक भी मूलभूत समस्या का हल नहीं हो पाया. 'जोतने वाले को ही जमीन' जब तक नहीं मिलेगी तब तक ग्रामीण किसानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा. आज भी प्राचीन खेती के तरीकों से छटपटाने वाले आदिवासियों के जीवन में तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक कि उनके खेती के तरीकों में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता. इसके लिए बेईमान लुटेरे शासक वर्ग कोई प्रयास नहीं करेंगे. परिणामस्वरूप बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी. सरकार भले ही अनगिनत योजनाएं करे, पर जनता के जीवन में मूलभूत बदलाव के बिना उनसे कुछ फायदा नहीं होगा. इनसे कर्जों का बोझ ही बढ़ेगा. इसलिए हम आशा करते हैं कि दण्डकारण्य का किसान अपनी जिन्दगी संघर्षों के ही जरिए बदल पाएगा, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाएं हासिल कर लेगा और सरकार द्वारा उत्पन्न तमाम बाधाओं को पार करेगा. ✪

(...पृष्ठ 21 का शेष)

एनपीए की एक दूसरी इकाई ने घात वाली जगह के निकट ही पीएनपी की प्रान्तीय मोबाइल फोर्स के मुख्यालय पर हमला करके दो सिपाही मार दिए और बहुत से घायल कर दिए. इन दोनों हमलों में एनपीए को कोई भी नुकसान नहीं हुआ. जबकि इन्होंने एक दर्जन हथियार छीन लिए, जिनमें एम-16, एम-14 रायफलों के साथ एम-60 मशीनगन और एस्सार्टिड गन भी थी.

इसी दौरान बाईकाल क्षेत्र में, जोकि लूजोन टापू के दक्षिणी भाग में है - एनपीए ने दुश्मन के 10 सिपाहियों को नकारा कर दिया (सात मारे, 3 घायल किए) और 25 हथियार छीन लिए. (ज्यादातर एम-16 रायफलें) यह सब मार्च से अगस्त तक हमलों में हुआ.

लूजोन टापू के दूसरे प्रान्तों में एन.पी.ए. की तीन आदमियों वाली स्पैरो इकाई ने, बांटगास प्रान्त में पीएनपी की मोबाइल फोर्स कम्पनी के एक पुलिसिए को सजाए मौत दी और उससे एम-16 रायफल और .45 कैलिबर पिस्तौल छीन लिया.लूजोन के उत्तरी हिस्से के पहाड़ी प्रान्त में एनपीए की एक प्लाटून ने दुश्मन की 54 वीं इनफैंट्री बटालियन की गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर हमला करके एक अफसर को मार डाला और दो कॉर्पोरल घायल कर दिए.

इसी समय मिण्डनऊ टापू के दक्षिण में एनपीए ने जुलाई में दुश्मन की एक भरी जीप पर घात लगाकर हमला किया, जोकि डवाऊ प्रान्त में है. चार सिपाही मारे गए, अन्य घायल हुए, मारे जाने वालों में उसी प्रान्त की बोस्टन मुनिसिपालिटी का पुलिस मुखिया भी शामिल था.

अप्रैल में मिण्डनऊ में भी, एनपीए ने, अगुसन डेलसूर प्रान्त के ऐस्प्रेन्जा शहर के एक बदनाम रबड़ बागान के प्रशासक को मौत की सजा दी. इस अपराधी ने एस्प्रेन्जा में बहुत से किसानों और मजदूरों को परेशान कर रखा था और इसमें कोई हैरानी नहीं कि जब उन्हें यह खबर मिली कि एनपीए ने जालिम प्रशासक से उन्हें मुक्ति दिला दी है तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई. ❖

बस्तर के मुक्ति संग्राम से...

राजसत्ता के मोह ने गद्दारी करके गला कांटा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान ने फांसी के फंदे की खिल्ली उड़ाई

काकतीयों (चालुक्यों) के शासन के शुरू होने से पहले बस्तर कई छोटी रियासतों में बंटा हुआ था. 770-1324 ईसवीं तक वहां जारी उन रियासतों में गोण्डी जनता की परम्परा के तहत जनवादी शासन-प्रणाली चलती थी. काकतीयों के आगमन के साथ वह छिन्न-भिन्न होने के अलावा, विदेशियों के शासन और जमींदारी प्रणाली की नींव पड़ी.

ऐसा जान पड़ता है कि 1324 ई. के पहले बस्तर 16 जमींदारियों में विभाजित था.लेकिन 1324 में बस्तर के सिंघासन पर बैठे अन्नमदेव के काल में 12 जमींदारियां हुआ करती थीं. भेज्जी, चिन्तलनार, कोत्तापल्लि, पामेड, सुकमा, पुतकेल, भूपालापट्टनम, कुटरू, भैरमगढ़, तोयानार, गुदमा, नैमेड और परालकोट के बारे में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध है, जबकि 1910 तक सिर्फ भूपालापट्टनम, कुटरू, चिन्तलनार, पुतकेल, कोत्तापल्लि सुकमा और परालकोट के बारे में जानकारी उपलब्ध है. वैसे, 1938-47 के बीच सिर्फ भूपालपट्टनम, सुकमा, कुटरू और कोत्तापल्लि-पामेड ही शासन कर रहे थे.

मई 1998 तक जो बस्तर जिला रहा, वह पहले दो रियासतों में, कांकेर और बस्तर में विभाजित था. 1777 में बस्तर मराठा भोंसले राजाओं के अधीन हो जाने के बाद, 1853 तक भोंसले राजाओं ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो बस्तर भी पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया. काकतीयों का भैरमदेव उस समय बस्तर का शासक था. दलगंजन सिंह मन्त्री था. ये दोनों अंग्रेजी हुकूमत से बेहत कुंठित थे. बस्तर राज्य की सीमाएं पश्चिम में इन्द्रावती और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थीं. (राजाओं की ताकत के मुताबिक ये सीमाएं भी बदलती रहती थीं) बस्तर के पड़ोस में स्थित महाराष्ट्र के सिरोंचा में अंग्रेजी अधिकारी पोलिटिकल एजेन्ट के तौर पर रहता था. छत्तीसगढ़ इलाके का प्रथम डिप्यूटी कमीशनर मेजर चार्लेस इलियट सिरोंचा में पहला कमीशनर के तौर पर रहा.

1853 में अंग्रजों के सीधे शासन में जाने के बाद बस्तर के लोगों में स्थानीय शासकों के प्रति इतनी विरोधिता व्याप्त थी कि अंग्रेजों को इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह क्रोधाग्नि किस रूप में भड़क जाएगी. आखिर में 3 मार्च 1856 को चिन्तलनार युद्ध के रूप में वह भड़क गई.

बस्तर की जमींदारियों में चिन्तलनार एक थी जिसमें एक परगना था लिंगसिरी. वह परगना भूपालपट्टनम तक 50 वर्ग मील के क्षेत्र में पैला हुआ था. वहां दुर्वाराव तालुकदार पद में था. अंग्रेजों के खिलाफ इसका ज्यादा गुस्सा था. इससे उसने अपने इलाके के लोगों को बगावत के लिए एकजुट किया. उसने यह जानकर कि बस्तर के शासक भैरमदेव में भी अंग्रेजों के खिलाफ काफी नफरत है, साझे तौर पर बगावत का ऐलान करने की पेशकश की. पर उसने इस पर सहमत नहीं होने के बावजूद यह वादा जरूर किया कि वह भी लड़ाई का ही हिमायती है.

अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बगावत शुरू हो गई. बस्तर की जनता के संसाधनों को लूटने वाले अंग्रेजों के आवागमन के रास्तों को लोगों ने अपना निशाना बनाया. बैलगाड़ियों में ले जाए जाने वाले सामान को जब्त कर लिया. अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने वाले बहादुर आदिवासियों का बचाव आसपास के पहाड़ों ने ही किया. उन्होंने छापामार तरीकों को अपनाया. ऐसे लोगों को जो अंग्रेजी अधिकारियों के सम्पर्क में हों, भी गद्दार मानते हुए सजा देने लग गए. सिरोंचा से अंग्रेजों के बस्तर आने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें धुर्वाराव एक बहुत बड़ी बाधा बन गया था. जब-जब मौका मिले उसने अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया था. अंग्रेजों ने भूपालपट्टनम के जमींदार से दोस्ती करके धुर्वाराव के संघर्ष की जानकारी लेना शुरू किया.

इसकी सूचना लेकर कि अंग्रेजी फौजें चिन्तलनार के रास्ते पर जाने वाली हैं, धुर्वाराव ने अपने 3 हजार जन-बल से चिन्तलनार के पहाड़ों में घात लगा रखा था. उस दिन, 3 मार्च, 1856 की सुबह के 8 बजे अंग्रेजी फौजों पर धुर्वाराव की सेना ने धावा बोला. लगभग 8 घण्टे तक भीषण लड़ाई हुई. उस समय आधुनिक शस्त्रों से लैस उन विदेशी फौजों का परम्परागत हथियारों से लैस विशुद्ध आदिवासी सेना ने जबर्दस्त मुकाबला किया. इस लड़ाई में दुश्मन का पक्ष लेने वाला भूपालपट्टनम का जमींदार किसी तरह अपनी जान बचाने में तो कामयाब हो गया, पर घायल हो गया. एक और सरकारी अधिकारी कुत्ते की मौत मरा था. लेकिन इस लड़ाई में जनता का प्यारा लड़ाकू नेता धुर्वाराव अंग्रेजी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. अन्य 460 महिलाएं एवं बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए. इनमें धुर्वाराव के बीवी-बच्चे भी शामिल थे. दो दिन के भीतर ही अंग्रेजी सेना ने जनता के इस नेता को फांसी की सजा दी. राष्ट्रीय स्वाभिमान से फांसी के लिए तैयार होकर जनता के पक्ष में लड़ने वाले इस योद्धा के लिंगसिरी इलाके को अंग्रेजी शासकों ने भूपालपट्टनम के गद्दार जमींदार को सौंप दिया.

लेकिन भूपालपट्टनम जमींदार के पुत्र यादवराव ने अंग्रेजों की कार्रवाई को ठुकराकर अपने पिता की गद्दारी से नफरत की. अंग्रेजी सेनाओं के साथ लड़ते हुए वीरगति को पाने वाला धुर्वाराव यादवराव का अच्छा दोस्त था. अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर यादवराव ने अपने दोस्त का ही रास्ता चुना. अपने पिता द्वारा की गई नीचता के विपरीत उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया. उस इलाके के लोगों को लामबन्द करके अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ 2,000 लोगों की फौज खड़ी कर दी. दक्षिण बस्तर के सभी *दोर्ला* (गोण्ड) सपूतों ने तीर-कमान उठा लिए. इस बार भी फिर एक बार यादवराव के पिता ने अपने पुत्र और जनता के खिलाफ विदेशियों का पक्ष लिया. जनता का पक्ष लेकर आजादी की तमन्ना से मैदान-ए-जंग में मोर्चा संभालने वाले पुत्र को उसके पिता ने ही बन्दी बनाकर अंग्रेजों के आदेश पर फांसी के फंदे में लटका दिया. एक और भोर का तारा डूब गया. अनगिनत आदिवासी सपूतों को अंग्रेजी बर्बरों और उसके साथ सांठगांठ करने वाले स्थानीय गद्दारों ने कत्ल किया. बस्तर की समूची धरती अंग्रेजी साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाइयों से भड़क उठी थी. विदेशी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले अनगिनत योद्धाओं ने सच्चे मन से जनता का

ही पक्ष लेकर वीरगति को प्राप्त किया.

यादवराव ने भूपालपट्टनम में जारी संघर्ष की मदद में पड़ोस के चांदा जिले के मल्लमपल्लि, आल्लपल्लि और घोट के जमींदारों से सम्पर्क कायम किया ताकि संघर्ष को विस्तार दे सके. मल्लमपल्लि के जमींदार वीर बाबूराव सडिमेक और आल्लपल्लि एवं घोट के जमींदार वेंकटराव के साथ दोस्ताना रिश्ते के कारण उन दोनों इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष साझे तौर पर चलाए गए. भैरमदेव ने इन दोनों संघर्षों के प्रति भी अपनी परोक्ष मदद प्रकट की. 1858 के मार्च में बाबूराव और वेंकटराव ने ब्रितानी हुकूमत से बगावत का ऐलान किया. उन्होंने अपनी फौजों से हमलों की तैयारी की. 29 अप्रैल, 1858 की रात को इन विद्रोहियों के दस्ते ने प्राणहिता के तट पर चुंचुगोंडी के निकट गार्टलान्ड, हाल और पीटर नामक टेलिग्राफ अधिकारियों पर हमला किया. इस हमले में गार्टलान्ड और हाल कुत्ते की मौत मर गए थे जबकि पीटर भाग गया. उस इलाके में बगावत को कुचलने के अभियान की कमान केप्टेन क्रिक्टन को सौंपी गई थी. पीटर के आने के बाद हमले की खबर सुनकर क्रिक्टन ने तत्काल ही पीटर को आदिवासी के वेष में अहेरी की जमींदारिणी लक्ष्मी बाई के पास भेजा. तब लक्ष्मी बाई अंग्रेजों के ही पक्ष में थी. (आज भी उसका पूरा खानदान जन संघर्षों के विरोधी पक्ष में ही खड़ा है.) बाबूराव और वेंकटराव की फौजों ने अंग्रेजों के खिलाफ हमले तेज किए. लेकिन पर्याप्त साधन-सामग्री के अभाव में अपेक्षित उपलब्धियां नहीं मिलीं. और तो और, वीर बाबूराव लक्ष्मी बाई की गद्दारी का शिकार बन गए. लक्ष्मी बाई द्वारा रचे गए षडयन्त्र के चलते, आखिर में बाबूराव को विदेशियों ने गिरफ्तार करके चंद्रपुर जेल में कैद कर दिया.

भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का दौर था वह. एक साल पहले ही लिंगसिरी के संघर्ष ने अंग्रेजों को हमलों का मजा चखा दिया था और धुर्वाराव ने उसमें अपने प्राणों की आहुति दी थी. भारत भर में सुलग रही बगावत की आग से अंग्रजी शासकों में कंपकंपी पैदा हो चुकी थी. राजाओं (जमींदारों) के बीच झगड़ों और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन संघर्षों को कुचलने में अंग्रेजी शासक कामयाब रहे. उस समय लड़ाई के लिए अपनी कमर कस लेने वाले अनगिनत जन योद्धाओं को उन गद्दारों ने कत्ल किया. हमारे वीर योद्धा बाबूराव सडिमेक को 21 अक्टूबर 1858 को चन्द्रपुर जेल में फांसी की सजा दी गई.

दूसरी ओर, हमलों की विफलता के चलते वेंकटराव ने बस्तर के राजा भैरमदेव पर भरोसा करके वहां आश्रय लिया था. लेकिन ऐसी पृष्ठभूमि में जबकि अनेक संघर्ष चोट-दर-चोट खाते जा रहे थे, भैरमदेव ने अपनी राज्याकांक्षा के चलते अंग्रेजों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया. इस दोस्ती में, भैरमदेव ने अपने दोस्त वेंकटराव के साथ गद्दारी की. परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने उन्हें भी फांसी पर लटका दिया. लेकिन आज तक भी भारत सरकार ने इनमें किसी को भी कम से कम, शहीद भी घोषित नहीं किया. आदिवासी जन संघर्षों के प्रति सरकारी महकमे द्वारा रची गई घिनौनी साजिश है यह.

अपने राज्य के लिए, गुलामी की जिन्दगी के खिलाफ, दुनिया को अपनी मुठ्ठी में बांधकर रखने के सपने देखने वाले अंग्रेजी साम्राज्यवादियों के खिलाफ अपनी फौजों से और अपने तरह के हथियारों व प्रशिक्षण से लड़ने वाले तमाम जन योद्धा सदा के लिए अमर हैं. इस देश से उपनिवेशी शासकों को मार भगाने की उनकी सशक्त आकांक्षा आज तक पूरी नहीं हुई है. अब सामंतवाद और साम्राज्यवाद सांठगांठ करके साझी लूटपाट मचा रहे हैं. वही वर्ग जिसने साम्राज्यवादी इस लूट-खसोट के लिए दरवाजे खोलकर, उनकी जूठन के लालच में उनका पल्ला थाम लिया था, हमारे दण्डकारण्य के संघर्षों को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है.

आज हमारे दण्डकारण्य के संघर्ष 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं. मार्क्सवाद को अपना हथियार बनाकर हमारे संघर्ष आगे कदम बढ़ा रहे हैं. लुटेरे शासक वर्गों को थरथरा रहे हैं. इस देश के शासक वर्गों द्वारा पूरी तरह भुला दिया गया जन योद्धाओं का इतिहास हमारी जनता के दिलों में संजोया हुआ है और क्रोध का लावा उगल रहा है. उन वीरों को लोग आज भी 'देवताओं" के रूप में पूज रहे हैं. उन्हें सर्व शक्ति सम्पन्न मानते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं. आज के हमारे संघर्ष उन वीरों के अनुभवों के आधार पर और जनता के संपूर्ण सहयोग से ही जारी हैं. इन जन संघर्षों को कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी. जन संघर्षों को दमन और गद्दारी के बल पर कुचलकर जन योद्धाओं को कत्ल करने वाले तमाम गद्दारों को दण्डित करेगा. उनके खून का कर्ज उतारकर ही दम लेगा.

धुर्वाराव का शहादत दिवस - मार्च 5

बाबूराव सडिमेक का शहादत दिवस - 21 अक्टूबर

साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई में बहादुरी से लड़कर
जान गंवाने वाले जन योद्धा सदा अमर रहेंगे!

*(श्री हीरालाल शुक्ल की किताब **'बस्तर का मुक्ति संग्राम'** से साभार)*

मावाब के चार शहीदों को लाल सलाम

2 अगस्त, 1999 को फिलिप्पींस की प्रतिक्रियावादी सरकार के हथियारबन्द बलों ने एनपीए के चार योद्धाओं को गिरफ्तार करके पाशविकतापूर्ण यातनाएं पहुंचाईं और फिर कत्ल कर दिया. चूंकि फिलिप्पींस में जनयुद्ध आगे बढ़ रहा है इसलिए शासक वर्ग दिन-ब-दिन बर्बर दमन पर उतर रहे हैं.

एनपीए के चार योद्धाओं में कॉमरेड का पाकिंग भी थे जो कि फिलिप्पींस की कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े जिम्मेवार कार्यकर्ता थे और मिण्डनऊ में एनपीए के कमाण्डर थे. उन्होंने अपने क्षेत्र में भूल-सुधार आन्दोलन को बड़ी जिम्मेदारी से चलाया और दो साल के अरसे में खोई हुई साख को बहाल करके बड़ी कामयाबी हासिल की और नए इलाकों को बढ़ाया.

मावाब के चार लोगों के कत्ल से जाहिर हो गया है कि एस्ट्राडा सरकार को लोगों की क्रान्तिकारी ताकत के बढ़ते जोर से बहुत खौफ और नफरत है और यह मानवाधिकारों की सरासर खिलाफत है. 'प्रभात' इस पाशविक हमले की निंदा करती है और फिलिप्पींस की क्रान्ति के लिए अपनी जान देने वाले इन शहीदों को लाल सलाम करती है. यह कॉमरेडों और शहीदों के परिवारों को अपनी हार्दिक संवेदनाएं भेजती है. ❖

फिलिप्पींस की लड़ाई की खबरें

एस्ट्राडा की प्रतिक्रियावादी फौजों के खिलाफ नई जनसेना (एनपीए) के हमले तेज

एनपीए के एक छापे में 84 हथियार छीन लिए गए

फिलिप्पींस में एस्ट्राडा सरकार के साथ फिलिप्पींस के राष्ट्रीय जनवादी मोर्चा (एनडीएफपी) की शान्ति वार्ताएं 1 जून, 1999 को खत्म हुए अभी दो हफ्ते ही गुजरे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमाई में एनपीए ने नाटकीय अंदाज में दो कार्यनीतिक हमले कर दिए जिनसे पता चलता है कि हथियारबन्द संघर्ष ताकतवर हो गया है और अपनी सामर्थ्य के मुताबिक जहां चाहे हमला कर सकता है.

एनपीए के छापामारों ने फिलिप्पींस के मध्य भाग के एक टापू बोहोल पर 11 जून को हमला किया, और फिर 15 जून को दावाऊ शहर पर हमला कर दिया जोकि फिलिप्पींस के बड़े दक्षिणी टापू मिंडनाऊ में है.

फिलिप्पींस के मध्य प्रान्त बोहोल के बातुआन के 7वें रीजिनल मोबाइल ग्रुप-कंबैट स्पोर्ट कम्पनी बारांगे रिजल के मुख्यालय पर जब हल्ला बोला गया, तो 84 हथियार हासिल हुए हैं जोकि फिलिप्पींस के क्रान्तिकारी आन्दोलन द्वारा 1992 की 'दूसरा बड़ा भूल-सुधार आन्दोलन' के बाद एनपीए का एक कार्यनीतिक हमला था.

एनपीए ने एक भी गोली दागे बिना 11 जून की सुबह को कामयाबी के साथ हमला किया. यह हमला एनपीए की रीजनल ऑपरेशन कमाण्ड, जोकि मध्य विसयास में है, की रहनुमाई में लाल-योद्धाओं ने किया था.

7वीं रीजनल मोबाइल पुलिस पीएनपी की अहम इकाई है जोकि लोगों के खिलाफ और मध्य विसयास के क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ दमनकारी मुहिम छेड़े हुए है और बहुत से मानवाधिकार उल्लंघनों की जिम्मेवार है. एक बयान में एनपीए ने कहा कि यह हमला बाहांगेरिजल के लोगों के अनुरोध पर किया गया था, ताकि बदमाश पुलिस इकाई को सजा दी जाए.

कामयाब कार्यनीतिक हमले का सेहरा युक्ति से जांच और सही योजना के सिर है और ये दोनों तभी मुमकिन थे कि एनपीए को स्थानीय बस्ती के लोगों की गम्भीर और विशाल हिमायत हासिल थी. जांच के सिलसिले में एनपीए को मालूम हुआ था कि दुश्मन की फौजी टुकड़ियां एक पहाड़ के सिरे पर और नीचे टिकी थीं.

गोलीबारी और छल-कपट के हमले के दावपेंच ठीक नहीं होने थे. एनपीए की कमान ने फैसला किया कि रणनीति और बेहतर ताकत को इस्तेमाल करके कमाण्डोज पर छापा मारा जाए.

कार्यनीतिक हमला बड़ी दिलेरी से किया गया. एक सौ से ज्यादा योद्धा ठीक 6.56 सुबह फौजी ठिकाने पर पहुंच गए. वे वैनों में भरे थे जिन पर स्थानीय प्रतिक्रियावादी सरकार और डिपार्टमेन्ट ऑफ इन्टीरियर के निशान लगे थे और ऐसा लगता था कि पीएनपी के फौजी पकड़े गए छापामारों को ला रहे हैं. इसने लाल योद्धाओं को शिविर में घुसने के योग्य बना दिया था. साथ ही वैन से उतरते हुए एक छापामार अपनी पारम्परिक कमीज में (बारोंग टेगालॉग) था, जिसके साथ तीन चुस्त वर्दीधारी महिलाएं थीं. सभी सरकारी अफसर लगती थीं. एक छापामार पुलिस मेजर की वर्दी में था और ज्यों ही एनपीए टोली भवन में दाखिल हुई, दुश्मन के सिपाहियों ने सैल्यूटें मारीं.

ज्यों ही अन्दर पहुंचे, छापामारों ने बन्दूकें थाम लीं और फुर्ती से हथियार छीन लिए और शिविर के 36 सिपाहियों और रंगरूटों को हिरासत में लिया. एक इशारा किया गया और पलक झपकते ही 100 लाल योद्धा आ खड़े हुए, हथियार, असला और दूसरा फौजी सामान इकट्ठा करने लग पड़े, जोकि उनके हमले का निशाना था.

कुल मिलाकर जब एनपीए के छापामार पीछे हटे तो उनके साथ 84 बड़ी शक्ति के और दूसरे दर्जे के हथियार थे, जिनमें एम-16 और एम-14 रायफलें, एक एम-60 मशीनगन और ग्रेनेडलॉन्चर, एक 60 एमएम मोर्टार, एस्सार्टिड हैण्डगनें और बहुत से गोली-बारूद के साथ कई तरह का फौजी सामान था.

यह हमला 9 बजे तक जारी रहा. लौटने से पहले लाल योद्धाओं ने एक जलसा भी किया. पुलिस के सिपाहियों में प्रचार किया. उनमें पर्चे बांटे गए और हमले की राजनीतिक बुनियाद के बारे में समझाया गया. गिरफ्तार किए गए सिपाही खुली बहस के तुरन्त बाद छोड़ दिए गए.

कामयाब कार्यनीतिक हमला, दूसरा बड़ा भूल सुधार आन्दोलन के सही उसूलों के दुरुस्त होने का सबूत है कि हथियारबन्द संघर्ष कदम-ब-कदम ही जनाधार को बढ़ाकर ही किया जाएगा.

यहां तक कि शर्मसार पुलिस अफसर भी कुछ नहीं कर सके और कबूल करते हैं कि बातुअन के लोगों के सहयोग के बिना हमला नहीं किया जा सकता था. भारी भय के कारण मध्य विसयास की पीएनपी की कमान ने टुकड़ी के चीफ इन्सपेक्टर रिचर्ड कैबलरो को सारी कम्बैट सुपोर्ट कम्पनी के साथ ही रिहा कर दिया.

बातुअन का यह कार्यनीतिक हमला एस्ट्राडा सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो क्रान्ति विरोधी हिंसा से लोगों और क्रान्तिकारी आन्दोलन को आतंकित करने में लगी है.

साल के शुरू में ही बोहोल अखबारों की सुर्खियों में था जब एक वाईस मेयर क्रान्तिकारी आन्दोलन में आ जुड़ा और जनवरी में एनपीए में शामिल हो गया. इसके कुछ महीनों के बाद एनपीए के छापामारों ने एक घात लगाकर किए गए हमले में एक मेयर पद के उम्मीदवार को मार डाला, इसके कुछ बाद बातुअन मुनिसिपालिटी के टाउन हाल और मेयर के निवास स्थान पर हमला किया गया.

इन सभी कार्रवाइयों और इस नई घटना के साथ और पुलिस मुख्यालय पर हुए हमले से मीडिया के समीक्षकों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि एनडीएफपी (फिलिप्पींस का नया जनवादी मोर्चा) का आधार विसयान के टापुओं में या फिलिप्पींस के मध्य भाग में बोहोल बन चुका था.

दावाऊ शहर के हमले में 100 लाल योद्धाओं की टोली द्वारा फिलिप्पींस

सेना की गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर किए हमले में 6 सिपाही मारे गए और 12 घायल हुए. दुश्मन ने शहर की सरहद पर घात के क्षेत्र में भारी सैन्य सामग्री भेज दी जिसमें एक हैलिकॉप्टर तथा गनशिप भी था और दूसरे दिन जब गोलीबारी शुरू हुई तो छापामार जंगल में चले गए. दुख की बात यह है कि दो छापामार भी लड़ाई में मारे गए.

एनपीए के 100 मजबूत छापामारों ने कमाण्डर पारगो के नेतृत्व में जो फिलिप्पींस के लोगों की नजरों में एनपीए की इकाई का मशहूर कमाण्डर है, एक बार सरकारी फौज का एक जनरल को पकड़कर युद्धबन्दी बनाया था जिसके साथ एक कप्तान भी कुछ महीने हुए युद्धबन्दी-कैदी बनाया गया था. दोनों युद्ध बन्दियों - इनके साथ तीन दूसरे जंगी कैदी, दो पुलिस अफसर और एक सिपाही देश के विभिन्न भागों से पकड़े गए थे - उनको बाद में छोड़ दिया गया, जब एनडीएफ की कई मांगों को एस्ट्राडा की सरकार मानने पर मजबूर हो गई थी.

दक्षिणी टागालॉग में कार्यनीतिक हमलों में बढ़ोत्तरी

दक्षिणी टागालॉग में मई-जून में एनपीए के द्वारा कार्यनीतिक हमलों में निजी सेना के 5 सदस्यों व 4 सिपाही मारे गए और 3 सैनिक घायल हुए.

गोल्डन कण्टरी फार्म्स इनकॉर्पोरेटेड (जीसीएफआई) के 5 सुरक्षा पहरेदारों को एनपीए के छापामारों ने 10 जून को बारांगे बालांसे, मम्बुराऊ मिण्डोरो ऑक्सिडैण्टल में घात लगाकर मार डाला. ये सुरक्षा पहरेदार किण्टोज रिकार्डो के निजी सैनिकों की तरह काम करते हैं. रिकार्डो किन्टोज एक बड़ा जालिम जमींदार है जिसके स्वामित्व में 7,000 हेक्टेयर गोल्डन कण्टरी फार्म इनकार्पोरेटेड की जमीन है. किण्टोज और इसके सिपाही मुम्बराऊ के किसानों के कत्ल करने, जमीन हड़पने और दूसरे जुल्मों के लिए जिम्मेदार हैं. दो सैनिक उस समय मारे गए जब लाल योद्धाओं ने 25 मई को बारांगे वालेई, पाड्रे बर्गोजकिजोन के राष्ट्रीय मार्ग पर घात लगाकर 76वीं आईबी के 2 सैनिक मार डाले. ये सैनिक कैनेडी टाइप जीप में सवार थे जब छापामारों की लगाई हुई सुरंग ने उनके वाहन को उड़ा दिया. दो सिपाही घायल भी हुए थे.

इसी दौरान मई में एनपीए के छापामारों ने सिटिओ इल्यांग क्रासिंग बरांगे सायाऊ, मॉगपॉग मरिण्डुक में फिलिप्पींस फौज की एक टुकड़ी पर हल्ला बोला था. एनपीए का इस प्रान्त में यह पहला हमला था.

कम्पोस्टेला घाटी में घात लगाकर हमले शुरू

इस साल जून में कम्पोस्टेला घाटी में, एनपीए द्वारा घात लगाकर किए गए दो हमलों में सिटीजन्स आर्म्ड फोर्सिज ज्योग्राफिकल यूनिट के 4 सैनिक और एक सिपाही मारा गया, ये दो अलग-अलग हमले थे. 27 जून को लाल योद्धाओं ने बारांगे लिबुलोन माबिनी शहर, जो दावाऊ डेल नॉर्टे में है, इसी यूनिट की गश्ती टीम के तीन सिपाही घात लगाकर मार डाले. इससे पहले सिटीजन्स आर्मड फोर्सिज ज्योग्राफिकल यूनिट और फिलिप्पीनी आर्मी का संयुक्त इकाई पर छिपा हमला करके लाल योद्धाओं ने दो सिपाहियों को मार डाला था जो गश्त पर थे. एनपीए की रोक लगाने वाली टुकड़ी (स्टॉप पार्टी) ने दुश्मन की आने वाली कुमुक पर गोलीबारी की थी.

पीआईसीओपी और एएफपी की टुकड़ियों पर एनपीए के हमले

पीआईसीओपी और एएफपी की टुकड़ियों पर एनपीए ने मई महीने में सूरिगाऊ डेलसूर में लगातार तीन कार्यनीतिक हमले किए. लाल योद्धाओं ने डोना कार्मेन नगर में 23 मई को 29वीं आईबी की टुकड़ी पर हमला करके तीन एम-16 और तीन कॉर्बाइनों के साथ एक हाथ में पकड़ने वाला वायरलेस सेट छीन लिया. इससे पहले 19 मई को बिसलिग नगर के पास पीआईसीओपी की फैक्टरी पर छापा मारा और उसे जलाकर राख कर दिया. इसके सात दिन पहले छापामारों ने फैक्टरी पर हल्ला बोला था और पीआईसीओपी की निजी सेना के आदमियों पर हमला किया था. घात लगाकर किए गए हमले में एक सुरक्षा कर्मचारी मारा गया था.

पीआईसीओपी के पास मिण्डनऊ के चार प्रान्तों की सरहद पर 1,95,000 हेक्टेयर की रियायती जमीन है. पीआईसीओपी एशिया की सबसे बड़ी निगम है जो प्लाईवुड और कागज की चीजें तैयार करके निर्यात करती है और औद्योगिक पेड़ लगाने का काम करती है.

एनपीए ने 29वीं आईबी पर तीन कार्यनीतिक हमले निगम को सजा देने के लिए किए थे जो पीआईसीओपी के मजदूरों के अधिकारों को कुचलती थी. 1998 में पीआईसीओपी ने 28वीं और 29वीं आईबी से गठजोड़ करके मजदूरों की हड़ताल को कुचला था.

पीआईसीओपी ने स्पेशल सिविलियन अग्जिलरी आर्मी का भी इस्तेमाल किया था जो कि इसकी निजी सेना और सुरक्षा सेना के तौर पर इसकी सेवा करती है और किराए के कातिल हैं.

रक्षात्मकता को जीत में बदल दिया

16 जून को बारांगे डोमिंगा कैलिनान, डबाऊ शहर में जब दुश्मन की फौजों ने एनपीए के शिविर को घेर लिया तो छापामारों ने रक्षात्मक सुरते-हाल पर काबू पा लिया, जब एलफा कम्पनी की 73वीं आइबी फिलिप्पीनी फौज ने उन पर हमला किया तो छापामारों ने अपने बचाव में लड़ते हुए 7 सैनिकों को मार डाला. 6 सिपाहियों को घायल कर दिया जबकि अन्य छह सिपाहियों को घायल कर दिया. दक्षिणी मिण्डनऊ की एनपीए की रीजिनल इकाई के कमाण्डर मिरार्डो आर्स ने एक बयान में कहा कि जब एनपीए शिविर का पता चला तो फौज ने गोलीबारी की और 2 लाल सैनिक मारे गए. पहली गोलीबारी के तुरन्त बाद एनपीए ने एक अनुकूल मोर्चा संभाल लिया और पलटकर हमला करने के काबिल हो गए. हमला करने वाली सेना का कमाण्डर सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट डोमिनिक बहुगा घबरा गया और अपने सैनिकों को जंग में छोड़कर भाग गया.

1998 की कुछ छापामार कार्रवाइयां

1998 के दौरान एनपीए के छापामार देश के बहुत से क्षेत्रों, टापुओं और प्रान्तों में सक्रिय रहे. टापुओं के सभी रणनीतिक जगहों में एनपीए के 81 छापामार मोर्चे थे. 1998 में एनपीए ने ये कार्यनीतिक हमले किए.

विसयास के समार टापू पर लावजारेज नगर में एनपीए ने एक लदी हुई फौजी जीप पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें तीन फौजी मरे, जिनमें एक लेफ्टिनेन्ट भी शामिल था. लगभग उसी समय *(बाकी पृष्ठ 17 पर...)*

गोण्डी रिपोर्ट **बालाघाट-भण्डारा संयुक्त डिवीजन**

मलाजखण्ड एरिया ते छापामारकुना कैदे पुलिस एजेन्टकुना मौत

क्रान्तिकारी किसान आन्दोलन तुन कुचले कीयले मलाजखण्ड दल एरिया ते 1991 ते डाबरी नाटे पुलिस वाडकु चौकी दोस्सिकुन दसियों आदिवासी बाईलकुना इज्जत बिगड़े कीत्तुर. सैकड़ों आदिवासी भाईलकुन मारपीट कीसिकुन बाकीलकुन जेल रोहतोर. बाकीलकुन चौकी तले छोड़े कीत्तुर. आदिवासीलकुना सैकड़ों रुपए, फसल, सब्जी-भाजी, भुट्टा, कोरकु, दारु कलतोर. ईता सभी कामकुने नाटाल कुछ गद्दारकु वोडकुना संग मत्तोर. बढ़ेमात्ता छापामार लड़ाई तुन हुडसि तना सुरक्षा लाई 25 जून 1999 ते चौकी खाली कीया पड़ेमाता.

28 जुलाई तुन डोडराटोला ता डीएकेएमएस वाडकु डाबरी हंजि बैठक कींदुर. बैठक ताकिनेके नाटोर सियानकु अणि कुछ पुलिसकुनोड संगीलो मिलेमासि संगठन वाडकु कॉ. भैय्यालाल, कॉ. चैतराम कुन जौकीले कोशिश कीत्तुड, मति जनता भाईल्कु बचे कीत्तुर. इच्चुटे चैतराम पसीत्तुर. भैय्यालाल तुन नरका पड़ी दोहचि हिरतोर अणि सक्काडे पीटे कीत्तुर. बोरी ते निहचि देव नदी ते फेंकीना विचार मत्ता. मत्ति जनता बचे कीत्तुर. अस्के भण्डेरी सरपंच, बीडीसी मेम्बर कुन सोंपे कीत्तुर. संगठन वाडकु कल्लु वुंजि वात्तोर, 15 हजार रुपए मांग कींदुर ते बोइसि हिरतोम इंजि फर्जी कागज बने कीत्तुर.

तीना बदला ते छापामारकु अणि मिलिशिया सदस्यल्कु कुल 34 जन मिलेमासि 3-8-1999 ता राततुन मर्सकु, भरमारकु, साबरकुना संग हंजि हमला कीसि 3 जनकुन लालसिंग वल्के, प्रेमसिंग टेकाम, मूलचंद टेकाम कुन जौकसि ओंडि भरमार जब्त कीत्तुर. ईर मूंड जनकुना इतिहास हूडकाट -

1. लालसिंग वल्के : पुलिस कुना डेरा बस्केटाल डाबरी ते लागता अस्केटाल वोडकुन कल सप्लाई कीयना, नाटा भेद सीयना, वोडकुना पेटेन्ट मत्तोर. वीन '92 ते ओंडि गन अणि '97 ते दूसरी बार समझे कीसि आत्तुन.

2. प्रेमसिंग टेकाम : वीनोर मिय्यड सडाई पितकोना तोर नाटाल विरोध आसि हंजि रुपझर डेरा बइत्तोर. प्रेमसिंग तोना ससुराल ता पुरा ये काडू रासिमेट्टा तोर नाटाल गद्दार बनेमासि हंजि रुपझर डेरा बइत्तोर. इडकुनाल वरोर पुलिस चौकीदार भी आंदुर.

3. मूलचंद टेकाम : ईर प्रेमसिंग तोर भाई आन्दुर. वीनिगा लुक्मा बन्दूक मत्ता. दल वीना लोहतले हंजि ते ईर दल वाडकुना पर्रो फायरिंग कीयला बन्दूक तुन मिडहींदुर.

ईर मूंड जन्कु आणि उंडे कुछ जनाल्कु मिलेमासि संगठन तोडकुन जौक्किले कोशिश कीसि मत्तोर. आपी ईडकुन मौत ता घाट ते छापामारकु अणि मिलिशिया वाडकु मिलेमासि रेहचीत्तोर.24 अगस्त '99 ता शामतुन रंड जनी मिलिशिया बाईल्कु सहित कुल 36 जन्कु (दलतुन भी मिले कीसि) डाबरी ते फोर्सवाडकुना चौकीतुन, साबर, टिकास्कु, मर्सकु बोइसि हंजि कसले कीसि तमा गुस्सातुन जाहिर कीत्तुर.

सनगुड्डा-सतोना नाटेनोर पुलिस चुगलाहाल झाडू आन्दुर. वीना तरीका उंदी नाटे मंदिना इहुने कईयों इलाकानू वेलिसोडे मंदूर. इत्तेके लावारिस वलीयंदुर. पैसांग भी चोरी कींदुर. इताल खराब आदत ताल इद तरीका सोकेटाल जनता वोनू मंडोर ते पैसा ना लालच ते पुलिस चुगलखोर बनेमासी हर नाटे हंदिना, दल ता खबर एतिना, संगठन वाडकुना खबर कीसि बीजागढ़ चौकी अणि लांजी थाना रिपोर्ट कींदुर. पुलिस वाड्कु वोनू पैसा सीसि रोहंदूर. छापामार दल 25 मई, '99 तुन पुलिस चुगलखोर झाडून जौकसीत्ता.

पैसाना लालच हूडसीहचि पुलिस वाडकु पागल रूप नाल बने कीसि डाबरी इलाका ते रोहतोर. वोना काम पूरा दिन भर नाहकुना कच्चुल खेडा ते वेलितीना, नुलपे गाटो तिंदीना समय आत्तेके फिर नाटे वायना, गाटो ताल्कसीकुन तिन्दूर. डाबरी पुलिस चौकी ते 3 दिय्यांग मत्तोर. बाद ते फिर गोदरी हत्तोर. आणि फिर वात्तोर. वीना तरीका दल बेगा डेरा ईर्राल मंदार ते पुलिस वाडकुन दल ता पर्रो मुठभेड़ कीसीयना मत्ता. छापामार दल जून 1999 ते 'पागल' चुगलाहल कुन खतम कीता.

मलाजखण्ड इलाका ते पुलिस दमन

बालाघाट जिला ता मलाजखण्ड दल क्षेत्र ते 1998 नवम्बर ता विधानसभा चुनाव तुन सफल कीसीहताले जनता रप्पो दमन फैले कीत्तुन. ईपी जनता तुन गिरफ्तार कियना, पीटे कीयना - दंदोर फैले कीतुन. बैहर तहसील ते वायन वाडे नार बहुरझिरिया नाटेनोड आदिवासी भाईल्कुन बिना मतलब ताल मारपीट कीसि मनमनी जीसी बालाघाट जेल ते वोसि पुलिस वाडकु बंद कीतुड. वीडकुना जिनगी नोडे-आकी कोयसी अपना जीवन पास कियातोड. बस्केने जावा उनटोड बस्केने आहुने करूकेने मंतोर. इहूनता जिनगी पास किए आदिवासीलकुन 3 महीना नाल जेल ते बन्द इरसी जमानत ते छुटे कीतुन, ताना 19 दिनकुना बाद ते पुलिसकुना मार ते 45 सालकुना उम्मर तोर सुकमनसिंह ता जान डैसीता. बाकी सभी साथीलकु बीमार मनदोड. सुकमनसिंह परिवार ता जिनगी एकदम गम्भीर मंता. वीना परिवार 3 झनकुना मंता. इदेके वोना रोता 4 सालकुना टुडाल मनदोड. इहून ता वोना कठिन ताल भी कठिन जिनगी बितेमायता.

अहूने सोनेवानी नाटे वरोर पुलिस मुखबिर डॉक्टर गणेश प्रसाद ईरु सागर जिलातोर आन्दुर. सोनेवानी नाटे मंजी अगल-बगल ता नाहकुनाल पार्टी ता समाचार एतुंदुर. साथोंसाथ नार-नाटे तनवोर सीआईडी भी तैयार कीत्तोर. अणि खुद भी पुलिस सीआईडी आन्दुर. छापामार दल वीना पर्रो कार्रवाई कीतुन पर पिस्तुर. तेना आरोप ते नार लत्तातोर मोडकुलाल बिसेन तोर मर्री भागचन्द बिसेन तुन बिना मतलब ता मार-झाड कीसि बालाघाट जेल ते वोसि बन्द कीसीतूडकु. ताना बाद ते मोडकुलाल बिसेन जमानत लाई हन्नेके तनवोर मर्री भागचन्द बिसेन ता चिन्ता ते बीच सरदे अरसी सासीत्तुर. इहुन ताल शासन ता रवैया, नीति अणि पुलिसकुना अत्याचार, बलात्कार, जोर जुल्म ताल जनता भयभीत मन्दा. इचुरे आयवेकेने पूरो एरिया ते सिर्री, गोदरी, बहुरझिरिया, डोंगरगांव, रासिमेट्टा, माटे, भालवा, कोडोभर्रा, कुलपा, कुवागोंदी, कसंगी, झकोर्दा, चिलकोना, पितकोना -नाटेनोडकुन पूरो जिला भर ते 1800 जनालकुन धारा 151 ता अंतर्गत बन्द कीत्तुन. चुनाव ता उंदी दिया पहले टले पोलिंग बूथकुनिगा 15 ताल 30 जनाल्कुना पुलिस बैचकु मत्ता. अणि पैट्रोलिंग कीये बैचकु अलग मत्ता. इचुर ज्यादा पुलिस बन्दोबस्त रप्पो चुनाव ताकसीहचिकुन, देश रप्पो जनवादी रूप ताल चुनावकु सफल आता इंजि वेहतुन. चुनावकुना बाद ते भी चुनेकीसि संगठन वाडकुन वोसि इनामी नक्सली बैयेमातुर इंजि पेपरकुने रेडियो ने वेहतीना जारी मंता. आजाद भारत रप्पो आदिवासीलकुना स्थिति इहुन मंदा. ❖

श्रध्दांजलि

पुलिस द्वारा मारपीट और जेल के अमानवीय हालात ने सुखमन की जान ली

बालाघाट डिवीजन के मलाजखण्ड दस्ता इलाके में एक छोटा सा गांव है बहुरझिरिया. यह एक बेहद पिछड़ा दूरस्थ गांव है जहां मुश्किल से 10 मकान होंगे. यहां के सभी लोग गोंड हैं. ये लोग खेती-किसानी नहीं जानते. अपने ढंग से बनाई एक छोटी सी झोंपड़ी के पीछे बरसात के मौसम में थोड़ी-बहुत मकई की बाड़ी बोने के अलावा ये और कोई खेती का काम नहीं करते. साल में 8 महीने से ज्यादा समय ये लोग जंगल में ही बिताते हैं. हालांकि जंगल से ये लोग कन्दमूलों का संग्रहण करते हैं, पर जीवन का वह मुख्य जरिया कतई नहीं है. उनकी जीविका का असली साधन है सिंहाडी (माहुर) के पत्ते एवं बक्कल इकट्ठा करके पास के हाट बाजारों में बेचना. बाजार के सम्बन्ध दूरस्थ जंगलों में भी पहुंच गए हैं जिससे आहार-संग्रहण के चरण से खेती-किसानी की ओर विकसित होने का एक सहज ऐतिहासिक क्रम इनकी जिन्दगी से अछूता रह गया. इस परिणामक्रम के असंतुलित हो जाने से एक ऐसे मेहनतकश तबके का विकास हुआ जो सिर्फ वनोपजों के संग्रहण पर ही निर्भर करते हुए जीवन चलाता है. भारत में ऐसे आदिवासी कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे जो आदिवासी अर्थव्यवस्था के सहज परिणामक्रम में विकसित होने से बाजार के रिश्तों द्वारा कई तरीकों में रोक दिए जाने से भिन्न-भिन्न तरीकों में जी रहे हैं. इनकी जिन्दगी हमेशा गरीबी से जूझती ही रहती है. इन्हें शिक्षा-चिकित्सा जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती. अपनी तरह की दुनिया में पेट की आग बुझाने की खातिर अपने ढंग के तरीकों में अविराम और निरन्तर वनोपजों की खोज करना ही वे जानते हैं. मलाजखण्ड और परसवाडा इलाकों में मौजूद पहाड़ों की शृंखला में दूर-दराज के जंगलों में ऐसे गांव पूरे 10 हैं जो अतीत की निशानी के तौर पर बच गए हैं. 50 किलोमीटर लम्बाई और उतनी ही चौड़ाई के क्षेत्र में दूर-दूर तक बिखरे हुए इन 10 गांवों में 200 से ज्यादा परिवार नहीं होंगे. सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही 1000 से ज्यादा आबादी नहीं होगी. हालांकि ये लोग भी दण्डकारण्य के गोंड समुदाय की ही संतानें हैं, पर इन्हें हेय दृष्टि से देखने वाले वर्गों ने इन्हें 'अंग्रेजी गोण्ड' का नाम दिया. एक समय अंग्रेजी महाचोरों ने हमारे भारत के कुछ आदिवासी कबीलों को 'अपराधी कबीले' घोषित कर दिया था. और 53 सालों की इस कथित आजादी के बाद भी भारत के शासक वर्गों ने अपने संविधान में इन्हें 'पूर्व अपराधी कबीलों' के रूप में चिन्हित कर रखा है, यह बात उनके लुटेरे चरित्र को ही प्रतिबिम्बित करती है. आज गोंडों के अन्दर भी पिछड़ी जीवनशैली में छटपटाने वालों को 'अंग्रेजी गोंडों' के रूप में पुकारना समूचे आदिवासी समाज के लिए ही अपमानजनक है.

इतने अपमानों को झेलते हुए बेहद गरीबी झेलते हुए सदियों पुराने मानव इतिहास के प्रतीक के रूप में खड़े उस गोंड समुदाय के लोगों में से कॉमरेड सुखमन एक था. इन गोंडों को छापामारों से और छापामारों को इन गोंडों से अपार स्नेह रहा. इन गोंडों को लुटेरे सरकार पर किसी तरह के भ्रम या आशाएं नहीं हैं. ऊपर से वे इस सरकार का यह कहकर विरोध करते हैं कि वह उन्हें अपने ढंग से जीने में परेशानियां खड़ी करते हुए अपनी बस्तियों में और यहां तक कि झोंपड़ियों में घुसकर लूट-खसोट मचाती है. उनके स्वाभिमान को समझने के लिए एक उदाहरण काफी है कि उन्होंने इस गुस्से से सरकार के काम करना बन्द कर दिया कि उसने उनकी श्रमशक्ति का अपमान करने के अलावा, उनके साथ गद्दारी भी की. पहले एक बार सरकार द्वारा चलाए जाने वाले बांस कटाई और तेन्दुपत्ता संग्रहण के कामों में जाने के बाद उन्होंने सरकारी कामों में जाना ही बन्द कर दिया और अब पूरी तरह अपनी जीविका के लिए वनोपजों के संग्रहण पर ही निर्भर कर रहे हैं. ऐसी बस्तियों में छापामारों का आना एक त्यौहार से कम खुशी की बात नहीं है. सभी घरों से जो भी बासी-पेज हो उसे इकठ्ठा करके लोग छापामारों की बैठक में शामिल हो जाते हैं. वे उन्हें अपने जीवन की व्यथाओं से अवगत कराते हैं. जंगल में होने वाले तमाम अनुभवों के बारे में विस्तार से और प्यार से समझाते हैं. उनसे क्रान्तिकारी गीत सुनकर खुश हो जाते हैं. लड़ाई के संदेश सुनकर अपना उत्साह जाहिर करते हैं. वे दृढ़तापूर्वक चाहते हैं कि उनकी जिन्दगी भी बदल जाए. ऐसे लोगों में सुखमन भी एक था जो 30 वर्ष का युवक था. उनकी बीवी और एक बेटा भी हैं.

1998 में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के मौके पर बालाघाट डिवीजन में खाकी बलों ने अपने दमन का पंजा फैलाया. सितम्बर और अकटूबर महीनों में लोगों की अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां कीं. जनता को आतंकित करके वोट बटोरने के इरादे से बेहद बर्बरतापूर्ण बरताव किया. पुलिस के इस पाशविक जाल में कॉमरेड सुखमन भी फंस गया था. झूठे मुकद्दमे दायर करने में माहिर पुलिस ने कॉमरेड सुखमन पर गोदरी में एक पुलिस मुखबिर के घर पर जनता द्वारा किए गए हमले का मामला थोप दिया. कॉमरेड सुखमन ने पुलिस की हिरासत में कई यातनाएं झेलीं. अपनी जिन्दगी में पुलिस की हवालात को कभी नहीं देखने वाले और पत्ते-बक्कल बेचकर गुजर-बसर करने वाले सुखमन के लिए पुलिस के यातना-गृह से बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा. हफ्ते भर तक खाकी बलों की बर्बरता झेलने के बाद उसे बालाघाट जेल रवाना कर दिया गया. वह उसके लिए पूरी तरह एक नई और अजीब सी दुनिया थी. वह उस माहौल को झेल नहीं सका. वहां विचाराधीन कैदियों के साथ किए जा रहे बरताव ने उसे झकझोर दिया. सलाखों के पीछे बन्दी बनाकर रखे गए सुखमन को अपने सगे वालों से मिलने का कोई मौका ही नहीं था. उनके अपने जंगल और पास के हाट बाजार के अलावा, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान बहुरझिरिया के गोंडों ने जबरन सुखमन को भूल जाने का निश्चय किया. काले कोटधारी वकील तो सुखमन जैसे निहायत गरीबों की बू तक नहीं लगने देते. काले कपड़ों वालों के न्याय के बारे में सुखमन को कोई जानकारी तक नहीं थी. 3 माह तक काफी यातना भरी जेल की जिन्दगी झेलने के बाद जब सुखमन बहुरझिरिया पहुंचा तो घर वाले काफी खुश हो गए. गांव के लोगों ने पुलिस की पाशविक कार्रवाइयों की घोर निंदा की. वह परिवार और पूरा गांव इस पूरे अनुभव को छापामारों को बताने के लिए बेचैनी से उनकी राह देख रहे थे. लेकिन सुखमन को ऐसा ही मौका ही नहीं मिला. पुलिस की हवालात में एक हफ्ता और जेल में 3 महीने ऐसे यातनाओं को जिनके बारे में उसने अपनी जिन्दगी में कभी सुना तक नहीं था, झेलने वाले कॉ. सुखमन ने 1998 के दिसम्बर माह में, *(बाकी पृष्ठ 27 पर...)*

दण्डकारण्य के संघर्ष-पथ पर...

बेहतर मजदूरी के लिए बांस मजदूरों की रैली

उत्तर बस्तर डिवीजन

डीएकेएमएस की अगुआई में बांस कटाई के मजदूर हर वर्ष अपने संघर्ष के जरिए मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी करते आ रहे हैं. इस साल भी डीएकेएमएस के नेतृत्व में आन्दोलन छिड़ने ही वाला था कि इतने में वन विभाग वालों ने कापसी रेन्ज में मजदूरों के साथ धोखाधड़ी करते हुए यह कहकर बांस कटवाया कि बांस का पासिंग अब नहीं किया जाएगा, बल्कि मजदूरी बढ़ने के बाद ही किया जाएगा. यह काम 15 दिनों तक चलता रहा. इस धोखाधड़ी को समझकर संगठन के नेतृत्व में 10-12 गांवों के लोगों ने 9 नवंबर, 1999 को एक बैठक की जिसमें हड़ताल जारी रखने और कापसी में एक रैली निकालने का फैसला लिया गया. इस रैली के लिए लोगों को तैयार करने के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई जबकि रैली में आगे रहने के लिए तीन सरपंचों ने सहमति जताई. 13 नवंबर को 30 गांवों से लगभग 1500 लोगों ने ट्रैक्टरों और बसों में कापसी पहुंचकर एक रैली निकाली जोकि एक किलीमीटर तक चली. रैली के समापन के बाद अनुविभागीय वन अधिकारी को मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ अन्य 9 मांगों से युक्त मांग-पत्र सौंप दिया गया.

लोगों ने शराब को तबाह किया

बिहार से आए हुए कुछ लोग ग्राम बड़गांव में होटल और शराब दुकानें खोलकर देशी शराब और सस्ती शराब बेचते हुए स्थानीय बदमाश मुखिया और गुण्डे बन गए थे. अकेले बड़गांव में बाजार के दिन ये लोग कोई 60 से 80 हजार रुपए की दारू बेचते थे. ये लोग आदिवासियों को ठगने में बड़े माहिर बन गए. इनके खिलाफ आसपास के गांवों के लोगों ने सरपंचों के नेतृत्व में जुलूस निकालकर शराब दुकानों को बन्द करने की मांग की जिसकी परवाह नहीं करते हुए ये लोग पुलिस को बाकायदा हफ्ते पटाते हुए अपना व्यापार बेरोकटोक जारी रखे हुए थे. इनका विरोध करने वालों को डराना-धमकाना, मारपीट करना आदि हथकण्डे अपनाया करते थे. शराब के नशे में डूबे हुए लोगों के जेब से पैसे छीनकर बेरहमी से दुकान से बाहर खदेड़ दिया करते थे. इनके जुल्मों और काले व्यापार से परेशान 30-40 गावों की जनता पार्टी के सामने लगातार यह मांग रखती रही कि इन्हें सबक सिखाया जाए. गांवों में मौजूद जन संगठनों के सदस्यों ने पहलकदमी करने का फैसला किया. 15 नवम्बर को 6 गांवों से संगठनों के 60 सदस्यों के साथ स्थानीय छापामार दस्ते ने मिलकर बड़गांव के दो होटलों और दो दुकानों पर धावा बोला. वहां बेची जा रही शराब को और जमा रखी हुई शराब के डिब्बों को तोड़फोड़ करके नष्ट कर दिया गया. बाद में इनके संचालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि शराब का व्यापार बन्द नहीं करने से आगे और भी ज्यादा बुरे परिणाम भुगतना पड़ेगा.

सरकार द्वारा चलाई गई 'संघ-सदस्यों के आत्मसमर्पण' की नौटंकी के खिलाफ प्रचार मुहिम

बस्तर के एसपी, डीआईजी और कलेक्टर के नेतृत्व में 13-14 नवम्बर को भानुप्रतापपुर में चलाई गई आत्मसमर्पण की नौटंकी के खिलाफ जोरदार प्रचार मुहिम चलाई गई. इसमें सरकार और पुलिस का पर्दाफाश करते हुए, इस आत्मसमर्पण नौटंकी में पुलिस का सहयोग करने वाले मुखियाओं और सरपंचों को चेतावनी देते हुए पूरे इलाके में 250 पोस्टर लगाए गए. कडिमे पंचायत मुख्यालय में 12 गांवों से 200 से ज्यादा स्त्री-पुरुषों को एकत्र करके सरकार और पुलिस की साजिशों का पर्दाफाश किया गया. इस बैठक में आत्मसमर्पण करने वाले संघ सदस्यों ने स्वीकार किया कि गांव के मुखियाओं के दबाव में उन्हें जाना पड़ा, पर ऐसा जाना नहीं चाहिए था. लुटेरी सरकार का सहयोग करने वाले पटेल और वार्ड पंचों को बुलाकर बैठक में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.

गड़चिरोली डिवीजन

लोगों के स्वास्थ्य कर्मी की गिरफ्तारी

सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य के मामले में रत्ती भर भी चिन्ता नहीं करती, यह बात जग-जाहिर है. ऐसे सैकड़ों लोग हर साल बीमारियों के शिकार बनकर असामयिक मौत की गोद में समा जाते रहते हैं. अगर जनता की भलाई पर सरकार रंच मात्र भी ध्यान देती तो हर साल सैकड़ों लोगों को असामयिक मृत्यु से बचाया जा सकता है. उल्टी, दस्त जैसी सामान्य बीमारियों के कारण भी दवाइयों के अभाव में लोग मौत के चपेट में चले जाते हैं. यह कहानी कई सालों से लगातार दोहराई जाती रही है. पर पिछले दो दशकों से जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन ने इसे गम्भीरता से लिया, और उन गांवों में जहां जन-संगठन ज्यादा मजबूत हों और जनता की पर्याप्त चेतना हो, वहां पर स्थानीय युवकों को थोड़ा-बहुत चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण देकर डॉक्टर के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है. लेकिन लोगों की संगठित ताकत से और दिनोंदिन बढ़ रही उनकी चेतना से शासक वर्ग इतने खफा है कि यहां तक कि गांवों में लोगों की पहल पर स्थापित किए गए इस तरह के स्वास्थ्य केन्द्रों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण है गड़चिरोली डिवीजन के भामरागढ़ दस्ता इलाके के दक्षिण गट्टा रेन्ज स्थित ग्राम अलवेर में की गई स्वास्थ्य कर्मी की गिरफ्तारी. ग्राम अलवेर क्रान्तिकारी आन्दोलन के मजबूत गढ़ों में से एक है जहां से कमाण्डर जूरू (प्रभाकर) जैसे नेता उभर कर क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल हो गए थे और भारत की नव जनवादी क्रान्ति के लक्ष्य के लिए दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान कुरबान कर दी थी. इस गांव में पिछले तीन साल से विकास कमेटी बनकर काम कर रही है जिसकी देखरेख में एक स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित हो चुका है. इस केन्द्र को

जो युवक चलाता था उसे पुलिस ने 29 सितम्बर,1999 को गिरफ्तार करके, वहां मौजूद दवाइयों को लूटा. उस युवक को भामरागढ़ थाने में तीन दिन रखा गया. इस पाशविक और कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हुए गांव की जनता ने पहलकदमी के साथ एक बैठक की और उसमें फैसला लिया गया कि भामरागढ़ थाने में धरना दिया जाए. उसके मुताबिक लोगों ने 1 अक्टूबर को थाने में जाकर पुलिस वालों को खरी-खोटी सुना दी. उनकी पाशविक कदम की जमकर भर्त्सना की. लोगों ने यह भी पूछा कि क्या गांव में स्वास्थ्य केन्द्र खोलना अपराध है? लोगों के इस सवाल से पुलिस चुप रह गई कि तुम हो कि हमारी भलाई करते नहीं, और ऊपर से हमने खुद ही हमारे विकास का बीड़ा उठाया, तो हमें ऐसे करने से रोकते हो. लोगों की संगठित ताकत के सामने पुलिस को सिर झुकाना ही पड़ा और गांव वाले अपने जन-स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारी को छुड़ाकर अपने साथ गांव ले गए.

पुलिस द्वारा गांव के युवकों की गिरफ्तारी

22 अक्टूबर, 1999 को गड़चिरोली के कमेण्डो पुलिस बलों ने दक्षिण गट्टा रेन्ज के ग्राम नेंडवाड़ी के देवू गावडे नामक आदिवासी युवक को तब गिरफ्तार किया जब वह जंगल में गाएं चरा रहा था. उसे जंगल में ही पकड़कर गांव भी नहीं लाते हुए खूब यातनाएं दी गईं. इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से उसे यातनाएं दी गईं कि उसकी उंगलियों को चाकू से काटा गया. भयंकर यातनाएं देकर उसे नागपुर जेल भेज दिया गया. इसी गांव के जोगा गावडे को 23 तारीख को गिरफ्तार करके खूब मारा-पीटा गया. उसे शारीरक और मानसिक तौर पर यातनाएं दी गईं. इसके पास एक बारूदी सुरंग मिलने का आरोप लगाते हुए नागपुर जेल भेज दिया गया.

ताडिगांव रेन्ज के पोकूर गांव के पाण्डू को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया. उसे पुलिस ने तब पकड़ा जब वह अपने खेत की तरफ हाथ में चावल और कपड़ा लेकर जा रहा था. उसें पुलिस ने इतना मारा कि उसे आखिर यह बात बोलनी पड़ी कि चावल नक्सलवादियों का है, लेकिन वास्तव में तो चावल उसी आदिवासी का था. पुलिस की ज्यादतियां इतनी भयंकर रूप से बढ़ गई हैं कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है. बस उस पर वही मुकदमा बन गया और उसे नागपुर जेल भेज दिया गया.

आम लोगों की इन अवैध गिरफ्तारियों के खिलाफ नेंडवाड़ी और पोकूर गांवों के लोगों ने भामरागढ़ थाने पहुंचकर अपना विरोध जताया, तो पुलिस वालों ने अपनी बर्बरता फिर एक बार दोहराते हुए लोगों की निर्मम पिटाई करके वहां से भगा दिया. इस तथाकथित महान लोकतन्त्र में जीने के अधिकार से भी वंचित होना पड़ रहा है और यहां तक कि जनवादी तरीके से अपना विरोध प्रकट करना भी पुलिसिया राज में अपराध बन गया है. इस तरह गैर-कानूनी ढंग से लोगों को मारपीट करने और गिरफ्तार करके झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में बन्दी बनाने से जन आन्दोलन नहीं रुकेगा, बल्कि इस लुटेरे सरकार के खिलाफ जनता की नफरत और भी बढ़ेगी.

शराब के विरोध में लोगों का मोर्चा

भामरागढ़ तहसील के ताड़गांव रेंज के ग्राम जिंजगांव के लोगों ने डीएकेएमएस के नेतृत्व में गुड और महुए से बनाकर बेची जाने वाली शराब को बन्द करने की मांग को लेकर मोर्चा निकाला. इसके पहले डीएकेएमएस में गांव में दो-तीन बार आमसभा की गई जिसमें इस धंधे को बन्द करने को कहा गया. पर इस धंधे में लगे लोगों ने इस चेतावनी का अनसुना कर दिया. फिर गांव के 50-60 लोगों ने एक मोर्चा निकाला और शराब बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री जब्त करके गांव की गलियों में प्रदर्शित किया गया. बाद में इस धंधे में लगे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. इस घटना ने आसपास के कई गांवों को प्रभावित किया, लोग ऐसे संघर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. गांवों में दारूबन्दी के बारे में पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

पुलिस मुखबिरों को जन-अदालत द्वारा सजा

दिनोंदिन आगे बढ़ रहे दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए शासक वर्ग तमाम हथकण्डे अपना रहा हैं. पुलिस वाले गांवों में लगातार गश्त लगाते हुए गांवों के कुछ आवारा युवकों को और चोर जैसे छोटे-मोटे अपराधियों को अपना मुखबिर बना रहे हैं. गांवों में पहले से अपनी धाक जमाए बैठे मुखियाओं को भी मुखबिर बनाया जा रहा है क्योंकि क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकास के बाद इन लोगों की प्रभुता पर आंच आ रही थी, इसलिए ये आसानी से आन्दोलन के विरोध में कार्रवाई करते हैं. लेकिन आज उन्नत छापामार इलाके की ओर अपना कदम बढ़ाने वाला दण्डकारण्य का क्रान्तिकारी आन्दोलन ऐसे मुखबिरों को बर्दाश्त कर नहीं सकता. उत्पीड़ित जनता के व्यापक हितों की रक्षा करने के लिए, कई कुरबानियां देकर और कठोर संघर्षों के बदौलत हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को अवश्य ही सजा देनी पड़ती है. इन लोगों को सजा देते समय इनकी गलतियों की गम्भीरता और इनके वर्ग-चरित्र का खयाल रखते हुए ही क्रान्तिकारी आन्दोलन कार्रवाई का कदम उठा रहा है. लेकिन ऐसे लोगों की मौत की खबरों को बूर्जुवाई प्रचार माध्यम अपने ढंग से 'नक्सलियों द्वारा आदिवासी की हत्या' जैसे शीर्षक देकर सुर्खियों में छाप देते हैं जोकि उनके वर्ग-चरित्र के मुताबिक ही है. पर जनता के हितों के खिलाफ चलकर, लुटेरे शासक वर्ग की जूठन के लालच में इन मुखबिरों ने जनता को, जन आन्दोलन को कितना नुकसान पहुंचाया है जिससे उनके खिलाफ यह कदम उठाना पड़ा, संघर्षशील जनता अच्छी तरह से जानती है. हाल के महीनों में ऐसे कुछ लोगों का उत्तर बस्तर और गड़चिरोली डिवीजनों में जनता, जन-संगठनों और छापामार दस्तों ने सफाया कर दिया. कुछ और लोगों को अन्य किस्म की शारीरक सजाएं दी गई हैं.

उत्तर बस्तर डिवीजन के कोइलीबेड़ा इलाके के ग्राम सुलंगी का पूर्व कोटवार मंगल गाण्डो का पुलिस के साथ शुरू से ही सम्बन्ध रहा. आसपास के कोई 20 गांवों के लोगों को परेशान कर रखा इसने. छोटे-मोटे पुलिस केस हो जाने पर लोगों से यह पैसा रिश्वत में वसूलकर उन्हें केस मुक्त कराने का बहाना किया करता था. लोगों को इसके काले कारनामों पर जब क्रोध आया तो इसे कोटवार के पद से हटा दिया. इसकी जगह पर दूसरे आदमी को कोटवार नियुक्त किया. लोगों की इस चेतना के पीछे डीएकेएमएस था इस बात को मंगल अच्छी तरह से जानता था. इसके बाद उसने डीएकेएमएस के प्रति और छापामारों के प्रति नफरत बढ़ा ली. और बराबर उनकी सूचना

पुलिस को पहुंचाता रहा. डेढ़ साल पहले कोइलीबेड़ा थाने के पास छापामारों द्वारा की गई एक कार्रवाई में मारे गए पुलिस हवलदार राजेश पाण्डे का यह बेहद करीब आदमी था. कई चेतावनियों के बावजूद इसने लोगों की बात नहीं मानी, परिणामस्वरूप 2 दिसम्बर, 1999 को जन अदालत में इसके सभी काले कारनामों पर विस्तृत बहस करने के बाद एकमत से इसे सजाए मौत देने का फैसला लिया गया, और तत्काल ही उस फैसले पर अमल किया गया.

15 दिसम्बर को ग्राम बद्रंगी के निवासी रवी नामक मुखबिर का छापामारों ने सफाया कर दिया. रवी के चरित्र के बारे में समझने से इसका अंदाजा लगाना आसान होगा कि पुलिस क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए कितने घिनौने हथकण्डे अपना रही है और कितने घटिया से घटिया लोगों का इस्तेमाल कर रही है. रवी एक आवारागर्द युवक था, दारू पीना लोगों के साथ लड़ना-झगड़ना इसका रोज का धंधा था. यूं ही एक दिन नंदलाल नामक एक मुंशी से इसका झगड़ा हो गया था. नंदलाल ने रवी को चाकू से मारा. इससे रवी को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा. मामला पुलिस तक पहुंच गया. बस, और क्या चाहिए पुलिस को? चाकू मारने वाले और घायल होने वाले दोनों को पुलिस ने मुखबिर बना लिया. दोनों को मुकदमे से बरी कर दिया. नंदलाल द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ग्राम सुलंगी में दस्ते पर पुलिस ने हमला करके गोलीबारी की. लेकिन दस्ते ने इसका मुकाबला करते हुए खुद का बचाव किया. तबसे नंदलाल फरार हो गया. रवी को पुलिस ने अबूझमाड़ के पहाड़ों पर भेजकर वहां के क्रान्तिकारियों की गतिविधियों का पता लगाने का जिम्मा सौंप दिया. यह रवी रिश्तेदारी के बहाने गांवों में जाकर दस्ते की खुफिया सूचना इकट्ठी करने की कोशिश किया करता रहा. एक बार दस्ते ने इसे चेतावनी देकर वहां से भगा दिया. फिर भी रवी कोइलीबेड़ा और सोनपुर के आसपास लगातार घूमते हुए छापामार दस्ते की सूचना एकत्र करने का काम बराबर करता रहा. और यह दस्ते की पकड़ में आने से बचते हुए सारी सावधानियां बरता करता था. लेकिन लोगों की सक्रिय मदद से इसे पकड़कर जन-अदालत में इस पर मुकदमा चलाया गया. लोगों को पहले से की गई इसकी सारी गतिविधियों के बारे में समझा दिया गया इसके बाद सभी लोगों ने इसे मौत के घाट उतार देना ही उचित समझा.

इसी इलाके के ग्राम कोद्दापाका के निवासी जयराम नरोटी और नातू जन अदालत में पिटाई कर दी गई. ये दसरू नरोटी और सोबी नेताम नामक उन कट्टर मुखबिरों के तहत 'उप-मुखबिर' के तौर पर काम कर रहे थे, जो अपने गांवों से अरसे पहले भागकर पुलिस थाने में डेरा लगाकर पुलिस की सुरक्षा में मुखबिर का काम कर रहे थे. क्रान्तिकारी आन्दोलन ने इन पुलिस मुखबिरों की जमीन की काश्त करने पर रोक लगाई थी जिसका उल्लंघन करते हुए नातू न केवल काश्त कर रहा था, बल्कि मुखबिरों को सूचना पहुंचाने का काम भी करता रहा. दसरू का करीबी रिश्तेदार जयराम भी पुलिस की मुखबिरी करते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन को नुकसान पहुंचाता रहा. 12 सितम्बर को कोद्दापाका में दस्ते के होने की सूचना इन्होंने सायकिल पर सवार होकर दुर्गकोंदुल पुलिस थाने में जाकर दी. तत्काल ही पुलिस हरकत में आते हुए छापामार दस्ते पर हमला करने के इरादे से धावा बोला, पर चूंकि दस्ते ने अपना डेरा बदल दिया था, इसलिए मुठभेड़ टल गई. 23 नवम्बर, 1999 को दोनों के खिलाफ जन-अदालत बुलाकर जनता में इनकी हरकतों के बारे में बहस की गई. जनता ने इनकी पिटाई करके सुधरने का एक और मौका देने का फैसला सुनाया.

गड़चिरोली डिवीजन के भामरागढ़ इलाके के ग्राम आरेवाडा का निवासी ओकसा पाकिरी गत एक दशक से मुखबिर बना हुआ था. पुलिस द्वारा इसे हर महीने 900 रु. का बाकायदा वेतन दिया जाता था. आलम पाण्डू नामक पुलिस दरोगा, जिसको कि 1997 में एक घात हमले में छापामारों ने मार डाला, ने जब 1991 में आरेवाडा के निकट चार निरीह आदिवासी युवकों को मुठभेड़ के बहाने मार दिया था, तब इस ओकसा पाकिरी भी उसके साथ था. तबसे लेकर यह लाहेरी के पुलिस कैम्प में रहते हुए अक्सर गांवों में घूमते हुए क्रान्तिकारियों की गतिविधियों का पता लगाने का काम करता रहा. इत्तेफाक से 24 सितम्बपर, 1999 को छापामार दस्ता जब एक सड़क से गुजर रहा था तब यह पुराना मुखबिर में सायकिल पर आते हुए पकड़ा गया. तत्काल ही इसे मौत के घाट उतारा गया और इस तरह आरेवाडा के शहीद साथियों के खून का कर्ज उतारा गया.

इसी इलाके के दक्षिण गट्टा रेन्ज के ग्राम खंडी के निवासी रामा कुडियामी को छापामार दस्ते ने मौत के घाट उतार दिया. रामा के बाप और बड़े बाप गांव में एक समय मुखिया रहे. लेकिन जब से गांवों में क्रान्तिकारी जन संगठनों का निर्माण हो गया, तबसे मुखियाओं का प्रभाव कम हो गया. पहले कुडियामी परिवार के मुखियागण लोगों से छोटे-मोटे विवादों पर पंचायत के नाम पर जबरन पैसा वसूलकर, लोगों को डरा-धमकाते हुए अपना मनमाना चलाया करते थे. सहज ही क्रान्तिकारी आन्दोलन द्वारा बढ़ाई गई चेतना से लोगों ने इनके जुल्मों व अत्याचारों का विरोध करना शुरू कर दिया. उतनी ही सहजता से ये लोग क्रान्तिकारी आन्दोलन के विरोधी खेमे में शामिल हो गए. 1995 में एक बार जन-अदालत में इन्हें पीटकर चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया, पर वे रास्ते पर नहीं आए. अपनी जन विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम देते रहे. 1996 में 28 जुलाई के दिन इनके द्वारा दी गई खबर के आधार पर पुलिस ने छापामार दस्ते की एक तीन सदस्यीय टुकड़ी पर धावा बोलकर हमारे प्यारे साथी कॉ. रघु की गोली मारकर हत्या की थी. तब रामा कुडियामी के साथ पटेल ने भी मुखबिरी की थी. इसलिए छापामार दस्ते ने पटेल का सफाया करके रामा कुडियामी को चेतावनी देकर एक मौका दिया. पर इसके बाद भी रामा अपनी मुखबिरी के काम पर अड़ा रहा, जिससे 21 अक्टूबर को छापामारों ने इसे मौत के घाट उतार दिया. उसके परिवार को गांव से बहिष्कृत कर भगा दिया गया.

इसी इलाके के ताड़िगांव रेन्ज के ग्राम टेकला का पटेल तानिया मासा दुर्वा 1989 से पुलिस की मुखबिरी करता था. लोगों पर अपनी धाक जमाकर डरा-धमकाना, संगठन के खिलाफ प्रचार करना, संघ के कार्यकर्ताओं के नाम पुलिस को देना आदि हरकतें करता रहा. इसने अपने एक भाई को पुलिस में भर्ती करवाया. दोनों भाई मिलकर लोगों को संघ में शामिल होने के जुर्म में जेल भेजने और पुलिस केस में फंसा देने का डर बताकर हजारों रुपए वसूल लिया करते थे. जो पैसे नहीं देते उन्हें जेल भिजवाया करते थे. आसपास के कई गांवों की जनता ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग क्रान्तिकारी आन्दोलन से की. तब पार्टी ने तानिया को सख्ती से चेतावनी दी कि तुम्हारे भाई को पुलिस से वापस लाओ और अपनी गलतियों पर जनता से माफी मांग लो.

बाद में तानिया अपनी जन विरोधी कार्रवाइयों को नहीं रोकते हुए अपना डेरा भामरागढ़ में डाल रखा था. वहीं से पुलिस थाने के सहारे जनता को धमकियां देना, जन संगठनों और छापामारों के खिलाफ दुष्प्रचार करना आदि जन विरोधी गतिविधियों को जारी रखा *(पृष्ठ 27 में जारी...)*

कर्नाटक पुलिस अब आन्ध्र के नक्शेकदम पर

27 अगस्त, 1999 को साढ़े चार बजे शाम को कॉमरेड भास्कर को कर्नाटक के रायचूर जिले के गंजल्ली गांव के निकट एक झूठी 'मुठभेड़' में कत्ल कर दिया गया. 28 साल के कॉमरेड भास्कर उर्फ बालकृष्ण आन्ध्रप्रदेश के जिला श्रीकाकुलम के थे, जिन्हें कर्नाटक के नक्सल-विरोधी पुलिस दस्ते के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कमेण्डों ने पकड़ने के बाद मारा.

इस घटना पर पुलिस बयान को उनके मीडिया ने बड़ी वफादारी से हूबहू तोते की रटंत की तरह छाप दिया ताकि असली मुठभेड़ की तरह लगे, कि जब पुलिस का सामना छापामारों से हुआ तो पुलिस पर गोली चलाई गई और जवाबी गोलीबारी में एक नक्सली मारा गया... ऐसी कहानी है पुलिस की . मगर तथ्य कुछ अलग ही कहानी बताते हैं.

पुलिस अपने मुखबिर से खबर पाकर अचानक चार सदस्यीय दस्ते पर टूट पड़ी जो कि एक जंगल में आराम कर रहे थे. पुलिस ने एक किलोमीटर तक उनका पीछा किया. कॉमरेड भास्कर को एक पत्थर से चोट खाने के कारण टांग में चोट आई और वे गिर पड़े तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. उनकी पत्नी कॉमरेड सुनीता भी पुलिस के मुकाबले तेज दौड़ने के काबिल नहीं थी और वे भी पकड़ी गई. कॉमरेड भास्कर के हाथ पीठ के पीछे बांध दिए गए और कुछ देर तक यातनाएं पहुंचाने के बाद उन पर निकट से तीन बार गोलियां चलाई गईं. रायचूर में एक साल के अरसे से चले आ रहे सरकारी दमन और दहशत में एक नाटकीय मोड़ आया है.

इस साल जुलाई-अगस्त के दमन के बाद इस 'मुठभेड़' की बारी आ गई. सरकार को इस पर भी तसल्ली नहीं हुई और उसने कर्नाटक रैयतु कूली संघ के आठ सदस्यों को जेल में ठूंस दिया, जिनमें पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी थे; उसने प्रगतिशील युवा केन्द्रऔर प्रगतिशील विद्यार्थी केन्द्र रायचूर के नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है. जिसमें छात्र संगठन के राज्य स्तर के संयुक्त सचिव कॉमरेड कुमार भी शामिल हैं. इस पर भी सरकार को संतोष नहीं हुआ और दूसरे जनवादी संगठनों के सदस्यों को, हुकूमत के खिलाफ साजिश के जुर्म में और बदनाम गुण्डा विरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया. इसी के साथ 14 से भी अधिक लोग जेलों में बन्द हैं और आधे तो एक साल से बन्द हैं.

ज्यादा कार्यकर्ताओं की तलाश में क्रान्तिकारियों के बीवी-बच्चों को सताया जाता है. महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी जाती है. धमकियां, यातनाएं, मुकदमे, रिश्वतें, और रात में छापों के अलावा दूसरे हथकण्डे इस्तेमाल किए जाते हैं.

अदालतें बेरुखी जाहिर करती हैं और कठोर लहजे में जमानत लेने से इन्कार करती हैं. यहां तक कि जनवाद का 'महान अमल' किया जाता है, उधर, बदतर तथ्य रायचूर के धूप से तपे खेतों से फूट कर अलग ही सचाई पेश करते हैं. पुलिस ने इरादा कर लिया है कि वह कर्नाटक में किसानों के क्रान्तिकारी संघर्ष को खत्म कर देगी. वे इस सड़ी-गली प्रतिक्रियावादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए लाशों को रौंदते हैं और मासूमों को कुचलते हैं.

रायचूर आन्ध्र की सरहद पर है और पड़ोस का दमन आसानी से कर्नाटक की पुलिस को भी असर में लेता है. उन्होंने अपने जोर-जुल्म से साबित कर दिया है कि वे भी आन्ध्र के रास्ते पर चल रहे हैं.

लेकिन रायचूर आन्ध्र की सरहद पर है, जहां से दूसरा असर भी दबे-कुचले लोगों पर आसानी से पड़ता है, वह है हथियारबन्द क्रान्ति! जब सभी राहें रोक ली गई तो कर्नाटक के किसान भी आन्ध्रप्रदेश के रास्ते पर चल पड़े हैं. और इसकी बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि कॉमरेड भास्कर द्वारा शहादत के पहले ही रास्ता जगमगा दिया गया है!

(... पृष्ठ 26 का शेष)

हुआ था. लेकिन भामरागढ़ में रहने से गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था. इसलिए उसने आत्मसमर्पण का नाटक रचकर फिर से गांव में डेरा डाला. लेकिन उसने अपनी पुरानी कार्रवाइयों को बराबर जारी रखा. 1999 के जुलाई माह में आसपास के सभी गांवों में लोगों से 120 भरमार बन्दूकें जब्त करने में उसने पुलिस की मदद की. और हर बन्दूक के बदले में 3,000 रु. रिश्वत वसूली ताकि मुकदमे से मुक्त हो सके. उसी तरह लोगों के बीच कोई झगड़ा हो, तो उसके निपटारे के बहाने वह कम से कम एक हजार रुपए वसूलता था. गांव में रहते हुए ही पुलिस को क्रान्तिकारी आन्दोलन की गतिविधियों के बारे में बराबर सूचना दे दिया करता था. इसके पूरे इतिहास को ध्यान में रखते हुए, आसपास के गांवों की जनता की राय से और उसके सुधर जाने की किसी भी सम्भावना के अभाव में दस्ता एरिया कमेटी ने चर्चा करके उसे मौत की सजा दी. इस तरह इस बदमाश पटेल और पुलिस के कट्टर मुखबिर का सफाया 4 नवम्बर, 1999 को कर दिया गया. ⌘

(...पृष्ठ 23 का शेष)

जेल से रिहा होने के बाद एक सप्ताह के अन्दर ही दम तोड़ दिया.

उसके बाद बहुरझिरिया जाने वाले छापामारों को लोग सुखमन की यातनाओं की व्यथा-गाथा सुनाकर रो पड़े. नमी आंखों से छापामारों ने उस शहीद की स्मृति में शोक-सभा का आयोजन करके क्रान्तिकारी सलामी पेश की. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहकर ढिंढ़ोरा पीटे जाने वाले इस देश में शासक वर्गों ने एक निरीह आदिवासी युवक की महज इस वर्ग-घृणा से हत्या कर दी कि उसने छापामारों को भोजन-पानी दिया था.इस देश में हजारों हजार तरह से सालों से लोग शासक वर्गों द्वारा किए जा रहे जुल्म और अत्याचारों का मुकाबला कर ही रहे हैं. इनसे तीखी नफरत से अपने खून से लाल-लाल कुरबानियां देकर महान ऐतिहासिक रास्तों का विमोचन कर ही रहे हैं. उस रास्ते में हमारा सुखमन एक है. उस इलाके के गोंडों के इतिहास में हथियारबन्द लड़ाई में अपनी जान की कुरबानी देने वाला पहला योद्धा था. उस योद्धा के संघर्षमय सपनों को संघर्ष को जारी रखकर ही साकार बनाएंगे. ⌘

भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मुख-पत्र
प्रभात
नवंबर 1999 - जनवरी 2000

''मुठभेड़ नहीं पुलिसिया हत्याएं हैं!''

देश भर में जनता की रैलियां और जवाबी कार्रवाइयां

जैसे ही भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के नेताओं की जघन्य हत्या की दुखद समाचार फैल गया, देश भर की पार्टी की इकाइयों, हथियारबन्द छापामार दस्तों, विभिन्न जन संगठनों और क्रान्तिकारी जन समुदायों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देना शुरू किया. लाखों जनता के दिलों में भरे शोक ने जल्द ही हत्यारों के खिलाफ और उस शोषक व्यवस्था के खिलाफ जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं एवं जिसकी रक्षा में उन्होंने ये क्रूरतम हत्याएं कीं, दहकते वर्ग-घृणा का रूप लिया.

3 दिसम्बर को कॉ. शीलम नरेश (मुरली) की अंत्येष्टि से लेकर कॉ. श्याम और कॉ. महेश की अंत्येष्टियों में हजारों लोगों ने पुलिस द्वारा कई रुकावटें खड़ी की जाने के बावजूद भाग लिया. 15-16 दिसम्बर को समूचे उत्तर तेलंगाना और आन्ध्र के अधिकांश इलाकों में 48 घण्टों की हड़ताल सफल रही जिसके पहले, 8-14 दिसम्बर के बीच विरोध सप्ताह का पालन किया गया था. दिसम्बर के आखरी सप्ताह में गुण्टूर जिले में 5,000 से ज्यादा लोगों ने सरकार की निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए एक रैली आयोजित की. गुण्टूर जिले के दाचेपल्लि में 11 जनवरी, 2000 को 'झूठी मुठभेड़ों के खिलाफ साझी संघर्ष-कमेटी' (USCAFE) की अगुआई में प्रस्तावित आमसभा को पुलिस ने भंग कर दिया. इस इलाके में भारी तादाद में पुलिस बलों को तैनात करके सभा-स्थल पहुंचने के लिए आने वाले लोगों को मार-पीटकर जबरन तितर-बितर कर दिया गया. क्रान्तिकारी लेखक वरवर राव, आन्ध्रप्रदेश के मानवाधिकार संगठन की अध्यक्ष रत्नमाला सहित जो आमसभा को सम्बोधित करने के लिए दाचेपल्लि गए थे, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया.

इस कमेटी ने झूठी मुठभेड़ों को रोकने और कॉमरेड श्याम, महेश और मुरली की हत्या की उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग करते हुए हैदराबाद में 1 जनवरी से बारी-बारी से भूख हड़ताल शुरू कर दी.

जन प्रदर्शन, सभाएं और विरोध के अन्य स्वरूप देश के कई राज्यों में भी फैल गए.

देश की राजधानी दिल्ली में 6 दिसम्बर को पुलिसिया हत्याओं की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों को सजा देने की मांग करते हुए एक रैली निकाली गई. 15 दिसम्बर को कलकत्ता में एक रैली निकाली गई.

उसी दिन, बिहार में, कई जनवादी और क्रान्तिकारी संगठनों और शख्सों ने राजधानी पटना में एक रैली निकाली. अखिल भारतीय जन प्रतिरोध मंच (एआइपीआरएफ), जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी, सर्वहारा चेतना, भाकपा (मा-ले) (एकता पहलू), नारी मुक्ति संघर्ष समिति, जनवादी छात्र संगठन, क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी संघ, जन संवाद और अन्य संगठनों ने इस रैली में भाग लिया. प्रधान एच प्रसाद, प्रीति सिन्हा (*फिलहाल* की संपादक), भूपेन्द्र कुमार, मिथिलेश कुमार और कई अन्य नामी लेखकों और बुद्धिजीवियों ने भी इस रैली में भाग लिया. आकाशवाणी केन्द्र के निकट एक आमसभा आयोजित की गई जिसमें वक्ताओं ने जनता से राजकीय आतंक के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध आन्दोलन का निर्माण करने का आह्वान किया, तथा कॉ. श्याम, महेश और मुरली की हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक मुकदमा चलाने की मांग की.

महाराष्ट्र में दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में मुम्बई और चन्द्रपुर में रैलियां निकाली गईं. मुम्बई और गुजरात के सूरत शहर में क्रमशः 22 और 23 को विरोध-सभाएं आयोजित की गईं.

दक्षिणी राज्य कर्नाटक में, 20 दिसम्बर को मुख्यमन्त्री के निवास तक एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें कर्नाटक रैतु कुली संघ (केआरसीएस), एआइपीआरएफ, अखिल भारतीय क्रान्तिकारी छात्र संघ (एआइआरएसएफ), क्रान्तिकारी युवा मोर्चा (आरवाइएफ) और अन्य संगठनों ने भाग लिया. प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक पुलिस पर कार्रवाई की मांग की जिसकी आन्ध्र पुलिस द्वारा की गई तीन नेताओं की हत्या में सहापराधिता रही.

जन प्रदर्शनों के अलावा हथियारबन्द जवाबी कार्रवाइयां आन्ध्र, उत्तर तेलंगाना, दण्डकारण्य, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में लगभग एक महीने तक चलती ही रहीं, इसे लिखते समय भी रिपोर्टें आती ही रही हैं.

जैसे ही 2 दिसम्बर की शाम यह खबर फैल गई, आदिलाबाद जिले के इंदारम गांव के निकट राज्य परिवहन निगम की एक बस जलाकर हथियारबन्द जवाबी कार्रवाइयों की शुरूआत की गई, और देश के कई राज्यों में फैल गईं. सरकारी वाहनों, अदालतों की इमारतों, केन्द्र व राज्य सरकारों के दफ्तरों, विश्राम-गृहों, टेलीफोन एक्चेंजों, रेलवे स्टेशनों, रेल लाइनों और अन्य सरकारी सम्पत्ति को; शासक वर्गीय राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के घरों व सम्पत्तियों को जनता की क्रोधाग्नि ने राख बनाकर रख दिया. शासक वर्गों के कई प्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों का सफाया कर दिया गया. 5 दिसम्बर को आदिलाबाद जिले के खानापुर कसबे के निकट बारूदी सुरंग का विस्फोट करके पुलिस गश्ती दल की एक गाड़ी को उड़ा दिया गया जिसमें एक उप-निरीक्षक सहित चार पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया जबकि एक पुलिस निरीक्षक और छह अन्य पुलिस वालों को बुरी तरह घायल किया गया.

वरंगल जिले में एटूरनागारम के निकट छापामारों ने दो पुलिस वालों का सफाया करके उनकी पांच रायफलें छीन लीं जिनमें एक एके-47 और तीन एसएलआर शामिल हैं. दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में छापामारों के एक विशेष दस्ते ने वरंगल शहर के बीचोंबीच एक हवलदार को मार गिराया.

19 दिसम्बर को आदिलाबाद जिले में किए गए बारूदी सुरंग के विस्फोट में एक हवलदार मारा गया और कई *(बाकी पृष्ठ 12 पर...)*